शर्मा हार्डওয়্যার
SHARMA HARDWARE
Sharma Gali, SJ Road
Athgaon, Guwahati-01
98648-02947

E-Paper : www.goodluckpublications.com, • www.vbslive.in

हिंदी दैनिक

गुवाहाटी, नई दिल्ली, शिमला और जम्मू से एकसाथ प्रकाशित

राष्ट्र निर्माण में प्रयत्नशील

विकसित भारत समाचार

वर्ष : 13 | अंक : 25 | गुवाहाटी | बुधवार, 26 अगस्त, 2026 | मूल्य : 10 रुपए | पृष्ठ : 8 | VIKSIT BHARAT SAMACHAR | Regd. RNI No. ASSHIN/2014/56526

असम, दिल्ली समेत देश के अधिकांश क्षेत्रों में अगले चार-पांच दिनों तक ... पेज 2
जागीरोड में मंत्री पीयूष ने किया सीएम-एएए लाभार्थियों से संवाद पेज 3
अगले छह माह में यूपी के एक लाख युवाओं को सरकारी नौकरी का ... पेज 5
इंडिया ओपन 2028 का आयोजन दिल्ली की जगह गुवाहाटी में होगा : बीएआई पेज 7

door graph Premium Quality Hinges
S.S. Traders
Suppliers in : All kinds of Door Fittings Modular Kitchen & Accessories, etc.
D. Neog Path, Near Dona Planet ABC, G.S. Road, Guwahati - 05
97079-99344

सुप्रभात

आत्मविजयी सभी प्रकार की संपत्ति एकत्र करने में समर्थ होता है।

- आचार्य चाणक्य

असम के लिए 5,000 करोड़ रुपए की आवासीय मंजूरी

बाढ़ प्रभावित किसानों को मिलेगी अतिरिक्त कृषि सहायता

नई दिल्ली (हिंस)। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने मंगलवार को कृषि भवन में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। बैठक में असम में बाढ़ से हुए नुकसान, किसानों की समस्याओं तथा कृषि और ग्रामीण विकास से जुड़ी केंद्रीय योजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई।

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक के दौरान असम के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण समेत विभिन्न योजनाओं के तहत कई महत्वपूर्ण स्वीकृतियां प्रदान की। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित असम के लोगों की सहायता में केंद्र सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य के -शेष पृष्ठ दो पर

कश्मीर में तीन अलग-अलग अभियानों में आठ *ओवरग्राउंड वर्कर* गिरफ्तार

श्रीनगर (हिंस)। सुरक्षाबलों ने कश्मीर में तीन अलग-अलग अभियानों के दौरान आठ *ओवरग्राउंड वर्कर* (आतंकी सहयोगियों) को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस और सेना के जवानों ने शोपियां जिले के इमामसाहिब इलाके में एक बाग में संयुक्त ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान सुरक्षाबलों ने नजीर अहमद वानी के बाग से एक ग्रेनेड, दो एके मैगजीन, चार मोबाइल फोन और एक प्रतिबंधित आतंकी संगठन के पोस्टर बरामद किए और तीन सहयोगियों को गिरफ्तार किया। इन तीन संदिग्ध ओवरग्राउंड -शेष पृष्ठ दो पर

मनुस्मृति पर आघात राहुल की विद्वेषपूर्ण मानसिकता का परिचायक : एबीजेएस

हैदराबाद (हिंस)। अखिल भारतीय जनसंघ (एबीजेएस) के राष्ट्रीय अध्यक्ष आचार्य भारत भूषण पाण्डेय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा गत दिनों मनुस्मृति को गलत ढंग से उद्धृत कर स्त्री विरोधी बताने संबंधी वक्तव्य की कड़ी निंदा की है। उन्होंने हुए इसे सनातन धर्म के प्रति विद्वेषपूर्ण मानसिकता का परिचायक बताया। आचार्य पाण्डेय ने राहुल गांधी समेत अन्य नेताओं से धार्मिक विषयों पर टिप्पणी करने से बाज आने को कहा। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में किस प्रकार संविधान, लोकतंत्र और नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए हिंदू धर्म और धर्माचार्यों

पर आघात किया गया था, उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाकर लांछित और कारागार में निबद्ध -शेष पृष्ठ दो पर

न्यूज गैलरी

राष्ट्रपति ने ओणम और ईद-ए-मिलाद-उन-नबी की पूर्व संध्या पर देशवासियों को दी शुभकामनाएं

नई दिल्ली (हिंस)। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने मंगलवार को ओणम की पूर्व संध्या पर देशवासियों, विशेषकर भारत और विदेशों में रह रहे केरलम के लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कामना की कि यह पावन पर्व सभी के जीवन में सुख, शांति, उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि लेकर आए। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि ओणम -शेष पृष्ठ दो पर

प्रधानमंत्री समेत कई नेताओं ने यूपीआई के दस साल पूरे होने पर दी बधाई

नई दिल्ली (हिंस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने मंगलवार को एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) के संचालन के दस साल पूरे होने पर शुभकामनाएं और बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि एक दशक पहले यूपीआई लांच किया गया था, जो भारत के डिजिटल पेमेंट के सफर में एक बड़ा मोड़ साबित हुआ। इसका दायरा और पहुंच ऐसी है कि हर भारतीय को इस पर -शेष पृष्ठ दो पर

फर्जी आईटीसी मामले में ईडी की छापेमारी में अबतक 3.6 करोड़ नकद बरामद

नई दिल्ली (हिंस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर एवं गाजियाबाद और हरियाणा के फरीदाबाद स्थित 9 ठिकानों पर सोमवार से जारी छापेमारी में अब तक कुल 3.6 करोड़ रुपए नकद बरामद किए गए हैं। ईडी ने मंगलवार को बताया कि एजेंसी ने इस छापेमारी के बाद सभी परिसरों को सील कर दिया गया है। बरामद नकदी और जब्त किए गए डिजिटल साक्ष्यों की जांच की जा रही है। इससे पहले एजेंसी ने सोमवार शाम तक मुजफ्फरनगर के -शेष पृष्ठ दो पर

सरकारी भर्तियों की मांग को लेकर पटना में छात्रों का उग्र प्रदर्शन, बैरिकेडिंग तोड़ी, वाटर कैनन से रोका मार्च

पटना (हिंस)। बिहार में सरकारी भर्तियों को लेकर छात्रों का आंदोलन मंगलवार को उग्र हो गया। पटना के गर्दनीबाग में 18 अगस्त से धरने पर बैठे छात्रों ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए मार्च निकाला। ऑल बिहार स्टूडेंट यूनियन (एबीएसयू) के छात्र नेता अमन गुट के नेतृत्व में निकले इस मार्च को रोकने के लिए प्रशासन ने जेपी गोलंबर पर भारी संख्या में पुलिस बल और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के जवानों की तैनाती की थी। मार्च के दौरान प्रदर्शनकारी

छात्रों ने जेपी गोलंबर पर लगाए गए बैरिकेडिंग को तोड़ दिया और डाकबंगला की ओर आगे बढ़ने का प्रयास किया। इस दौरान छात्रों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक और तनातनी की स्थिति उत्पन्न हो गई। गांधी मैदान से लेकर इनकम टैक्स गोलंबर तक कई स्थानों पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच भिड़ंत की सूचना है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। गर्दनीबाग में पिछले कई दिनों से धरना दे रहे छात्र अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। मंगलवार को छात्रों ने धरना स्थल से मुख्यमंत्री आवास की ओर मार्च शुरू किया। प्रशासन ने पहले ही जेपी -शेष पृष्ठ दो पर

निजी नर्सिंग होम के खिलाफ असम सरकार अपनाएगी सख्त रुख

गुवाहाटी (हिंस)। असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने निजी नर्सिंग होम -शेष पृष्ठ दो पर

एच1एन1 को लेकर सरकार की निगरानी तेज, घबराने की जरूरत नहीं : आईसीएमआर

नई दिल्ली (हिंस)। देश में मौसमी इन्फ्लुएंजा के बढ़ते मामलों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग (डीएचआर), भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। आईसीएमआर के महानिदेशक और डीएचआर

सचिव डॉ. राजीव बहल ने मंगलवार को कहा कि मौजूदा स्थिति में घबराने की जरूरत नहीं है। देश में फैल रहे इन्फ्लुएंजा वायरस हाल के वर्षों में देखे गए मौसमी पैटर्न के अनुरूप हैं। 73 डीएचआर-आईसीएमआर वायरस रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लैबोरेटरीज के नेटवर्क के -शेष पृष्ठ दो पर

पंजाब में चीनी की कोई कमी नहीं, स्टॉक व आपूर्ति पर पूरी नजर : भगवंत सिंह मान

चंडीगढ़ (हिंस)। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मंगलवार को कहा कि राज्य में चीनी की कोई कमी नहीं है और पंजाब सरकार आम लोगों के हितों की रक्षा के लिए चीनी के भंडारण, बिक्री और आपूर्ति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस आवश्यक वस्तु की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए और कृत्रिम कमी पैदा करने या जमाखोरी करने के किसी भी प्रयास के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री मान ने कहा कि पंजाब के पास पहले से ही चीनी का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर समय आवश्यक स्टॉक बना रहे। चीनी हर घर के लिए एक आवश्यक

वस्तु है और इसकी उपलब्धता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। कृत्रिम कमी पैदा करने या जमाखोरी करने के किसी भी प्रयास से सख्ती से निपटा जाएगा।

10 दिनों में तीसरी बार असम के मुख्यमंत्री शर्मा को जान से मारने की धमकी

गुवाहाटी (हिंस)। असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा को पिछले 10 दिनों में तीसरी बार जान से मारने की धमकी मिली है। सोशल मीडिया पर एक बार फिर मुख्यमंत्री को धमकी देने वाला संदेश सामने आया है। बताया गया है कि नगांव जिले के जुरिया निवासी मोबारेक अली नामक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री को धमकी दी है।

आरोप है कि नगांव लोकसभा क्षेत्र के उपचुनाव के प्रचार अभियान के दौरान एक सभा में मुख्यमंत्री की हत्या करने की धमकी दी गई। -शेष पृष्ठ दो पर

इंफाल पूर्व में भूमिगत ठिकाने से हथियार और विस्फोटक बरामद

इंफाल (हिंस)। असम राइफल्स ने भारतीय सेना और इंफाल ईस्ट पुलिस कमांडो के साथ संयुक्त अभियान में मणिपुर के इंफाल पूर्व जिले के सिनाम कोम इलाके में एक भूमिगत ठिकाने से हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटक बरामद किए हैं। विशिष्ट खुफिया सूचना के आधार पर संयुक्त टीम ने 24 अगस्त को तड़के करीब 3 बजे इलाके में तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान मेटल डिटेक्टर और विस्फोटक पहचानने वाले खोजी कुत्ते की मदद ली गई।

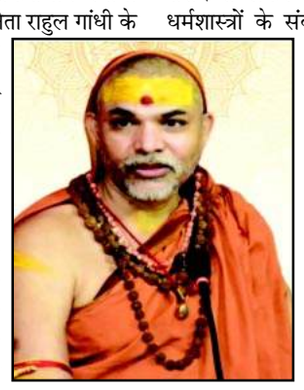

राहुल गांधी हिंदू धर्मशास्त्र विरोधी मानसिकता और असत्य प्रचार छोड़ें : अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती

जोशीमठ (हिंस)। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मनुस्मृति संबंधी बयानों पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि हिंदू धर्मशास्त्रों पर टिप्पणी करने से पहले उनका समुचित अध्ययन और शास्त्रीय संदर्भों की जानकारी आवश्यक है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने मंगलवार को जारी बयान में कहा कि पुणे में एक कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने मनुस्मृति और सनातन सांस्कृतिक विचारों के संबंध में जो टिप्पणियां कीं, वे धर्मशास्त्रों की सतही समझ को दर्शाती हैं। उन्होंने कहा कि संसद से लेकर सार्वजनिक मंचों तक मनुस्मृति और धर्मशास्त्रों के संबंध में बार-बार असत्य एवं भ्रामक

प्रचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन धर्म और शास्त्रों के विषय में टिप्पणी करते समय तथ्य, संदर्भ और अध्ययन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। शंकराचार्य ने राहुल गांधी से आग्रह किया कि वे प्रमाणिक स्रोतों और विद्वानों के माध्यम से हिंदू धर्मशास्त्रों का अध्ययन करने के बाद ही सार्वजनिक रूप से अपनी बात रखें। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि मनुस्मृति सहित -शेष पृष्ठ दो पर

मणिपुर में सुरक्षा बलों की कार्रवाई, संदिग्ध उग्रवादी गिरफ्तार; भारी मात्रा में हथियार बरामद

इंफाल (हिंस)। मणिपुर में सुरक्षा बलों ने बीते 24 घंटे में चलाए गए अलग-अलग अभियानों में कई संदिग्ध उग्रवादी कैडरों को गिरफ्तार किया और बड़ी मात्रा में हथियार, गोला-बारूद एवं संचार उपकरण बरामद किए। अधिकारियों के अनुसार, 24 अगस्त को 28वीं असम राइफल्स से मिली विश्वसनीय खुफिया सूचना के आधार पर सीडीओ/इंफाल ईस्ट ने खुराई थांगजाम लीकाई से सोरेपा के दो सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान लैटोनजाम रॉकी सिंह उर्फ खुटान (37) और पुखरामबाम कुमारजीत सिंह (36) के रूप में हुई है। दोनों कथित तौर पर इलाके में जबरन वसूली के लिए पहुंचे थे। उनके पास से मोबाइल नंबर और सोरेपा के नाम वाला एक हस्तलिखित वसूली पर्चा भी

बरामद किया गया। इसी दिन कांगपोकपी जिले के जे. सोंगतुन गांव में मणिपुर पुलिस, -शेष पृष्ठ दो पर

नौसेना दूसरे स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल *निपुण* को कमीशन करने के लिए तैयार

नई दिल्ली (हिंस)। भारतीय नौसेना 31 अगस्त को मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में निस्तार श्रेणी के दूसरे डाइविंग सपोर्ट वेसल (डीएसवी) निपुण को अपने समुद्री बेड़े में शामिल करेगी। इसके शामिल होने से नौसेना की गहरे समुद्र में गोताखोरी और पानी के नीचे सहायता क्षमताओं में अहम बढ़ोतरी होगी। यह जहाज निर्माण से लेकर ऑपरेशनल सर्विस तक के सफर में नए अध्याय की शुरुआत होगी। विशाखापत्तनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में डिजाइन और निर्मित *निपुण* डिफेंस शिपबिल्डिंग में भारत की आत्मनिर्भरता की कोशिश में मील का पत्थर है। आउटफिटिंग और ट्रायल के एक बड़े प्रोग्राम के पूरा होने के बाद यह वेसल 30 जुलाई, 2026 को भारतीय नौसेना को सौंपा गया था। यह खासतौर पर बनाया गया प्लेटफॉर्म है, जिसे डाइविंग और पानी के अंदर के कई तरह के ऑपरेशन में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह जहाज आधुनिक डाइविंग सिस्टम और पानी के अंदर दखल देने की क्षमताओं से लैस है, जिससे समुद्र में मुश्किल -शेष पृष्ठ दो पर

सरकार जातिगत जनगणना को ठंडे बस्ते में डाल रही : कांग्रेस

नई दिल्ली (हिंस)। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस तरह से जातिगत जनगणना कराई जा रही है, वह केवल व्हाइट वॉश है और कांग्रेस इसे स्वीकार नहीं करेगी। जयराम रमेश ने जातिगत जनगणना की मौजूदा प्रक्रिया को रद्द करने की मांग करते हुए कहा कि बिहार और तेलंगाना में अपनाए गए सर्वेक्षण मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जाए। जयराम रमेश ने आज यहां कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि 20 अगस्त को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में नेता विपक्ष -शेष पृष्ठ दो पर

डीआरडीओ की मिसाइल टेक्नोलॉजी भारतीय रक्षा उद्योगों को होगी ट्रांसफर, सरकार की मंजूरी

नई दिल्ली (हिंस)। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ की ओर से विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को भारतीय रक्षा उद्योग को स्वदेश में ही उत्पादन के लिए हस्तांतरित करने की स्वीकृति दे दी है। स्वदेशी रक्षा उद्योग को बढ़ाने की दिशा में इस फैसले से भारतीय कंपनियों को रेगुलेटरी नियमों का पालन करने वाले एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम बनाने में बढ़ावा मिलेगा। घरेलू क्षमताओं को मजबूत करके सरकार न केवल आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दे रही है, बल्कि देश के

डिफेंस सेक्टर को भी बेहतर बना रही है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस फैसले से मिसाइल प्रणाली के विकास को औद्योगिक उत्पादन में सफलतापूर्वक परिवर्तित करना संभव होगा। इससे उन्नत रक्षा प्रणालियों के विकास और विनिर्माण के उद्देश्य से भारतीय उद्योग जगत की क्षमताओं का लाभ उठाया जा सकेगा। इसका उद्देश्य घरेलू विनिर्माण क्षमताओं में वृद्धि करना, रक्षा क्षेत्र के औद्योगिक आधार को सुदृढ़ करना और आपूर्ति श्रृंखला में भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा अन्य प्रौद्योगिकी साझेदारों की भागीदारी के अवसर उत्पन्न करना है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता में वृद्धि करना, आयात पर निर्भरता घटाना तथा गुणवत्ता और उपयोगिता बढ़ाने के लिए घरेलू स्तर पर सुधार या बदलाव को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही भारत के -शेष पृष्ठ दो पर

CLASSIFIED

For all kinds of classified advertisements please contact

97070-14771
94350-14771

AFFIDAVIT

I **Md Masum Alom**, S/O Abusyed Asraful Alom, resident of Vill - No. 2 Islampur Block, P.O. Dharmapur , P.S. Laluk, Dist. Lakhimpur, Assam, PIN 784160 do hereby declare that I have changed my name from **Md Masum Alom** to **Masum Alom** and henceforth I shall be known as **Masum Alom** in all purpose, vide affidavit no. 9599 sworn before the Notary Public at North Lakhimpur on 05-08-2026. **Masum Alom** and **Md Masum Alom** both are same and one identical person.

असम, दिल्ली समेत देश के अधिकांश क्षेत्रों में अगले चार-पांच दिनों तक बारिश की संभावना

नई दिल्ली (हिंस)। दिल्ली-एनसीआर, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी और तटीय आंध्र प्रदेश समेत दश के अधिकांश क्षेत्रों में अगले चार-पांच दिनों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस दौरान कहीं-कहीं आंधी-तूफान और बिजली गिरने का भी पूर्वानुमान है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में 27-29 अगस्त के दौरान, असम एवं मेघालय में 26-27 अगस्त के दौरान कहीं-कहीं या कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश में 25-27 अगस्त के दौरान, असम, मेघालय, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 25-29 अगस्त के दौरान कहीं-कहीं आंधी-तूफान और बिजली गिरने की संभावना है। नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 29-30 अगस्त के दौरान कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश होने की भी संभावना है। कोंकण और गोवा में 25-31 अगस्त के दौरान, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में 25 अगस्त को काफी ज्यादा से लेकर व्यापक बारिश होने की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में 26-31 अगस्त के दौरान; गुजरात क्षेत्र और सौराष्ट्र एवं कच्छ में 25-31 अगस्त के दौरान कहीं-कहीं या कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना है। मराठवाड़ा में 25 अगस्त को कहीं-कहीं आंधी-तूफान और बिजली गिरने की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र में 25-26 अगस्त के दौरान कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल और तेलंगाना में 25-31 अगस्त के दौरान, केरल, माहे और लक्ष ?द्वीप में 29-31 अगस्त के दौरान, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में 26-31 अगस्त के दौरान कहीं-कहीं या कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना है। 25 से 26 अगस्त के दौरान तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में 25 से 29 अगस्त के दौरान, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और रायलसीमा में कहीं-कहीं आंधी-तूफान, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। 25 अगस्त को तटीय कर्नाटक, उत्तर आंतरिक कर्नाटक और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कहीं-कहीं आंधी-तूफान और बिजली गिरने की संभावना है। 25 से 29 अगस्त के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और रायलसीमा में सतह पर तेज हवाएं चलने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में अधिकतम तापमान में 1-3 सेलसियस और न्यूनतम तापमान में 3-4 सेलसियस की गिरावट आई है। पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में अधिकतम तापमान 31-33 सेलसियस और न्यूनतम तापमान 21-24 सेलसियस के बीच रहा। न्यूनतम तापमान कुछ जगहों पर सामान्य से काफी कम (-3.1 सेलसियस से 5.0 सेलसियस), कुछ जगहों पर सामान्य से कम (-1.6 सेलसियस से -3.0 सेलसियस) और दिल्ली के बाकी हिस्सों में सामान्य (-1.5 सेलसियस से 1.5 सेलसियस) रहा। अधिकतम तापमान कुछ जगहों पर सामान्य से काफी कम (-3.1 सेलसियस से -5.0 सेलसियस), कई जगहों पर सामान्य से कम (-1.6 सेलसियस से 3.0 सेलसियस) और दिल्ली के बाकी हिस्सों में सामान्य (-1.5 सेलसियस से 1.5 सेलसियस) रहा। पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में कई जगहों पर भारी बारिश और कुछ जगहों पर मध्यम बारिश के साथ आंधी/बिजली कड़कने की घटनाएं हुई। पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहे और जमीन पर हवा की गति 20 किमी/घंटा रही, जो कभी-कभी 54 किमी/घंटा तक पहुंच गई; हवा पश्चिम दिशा से चल रही थी। दिल्ली और आसपास के इलाकों में 27 एवं 28 अगस्त को आम तौर पर आसमान में बादल छाए रहेंगे। दोपहर के समय बहुत हल्की बारिश हो सकती है। जमीन के पास हवा मुख्य रूप से उत्तर-पश्चिम दिशा से चलेगी और सुबह के समय इसकी रफ्तार 20 किमी/घंटा तक हो सकती है। दोपहर के समय उत्तर-पश्चिम दिशा से चलने वाली हवा की रफ्तार बढ़कर 22 किमी/घंटा तक हो जाएगी। शाम और रात के समय हवा की रफ्तार कम होकर 20 किमी/घंटा तक रह जाएगी और हवा पश्चिम दिशा से चलेगी। पिछले दो-तीन से जारी बारिश के कारण दिल्ली के अधिकतर निचले इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे आमजन को आवाजाही करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आईएमडी के अनुसार दिल्ली के कुछ इलाकों में झमाझम बारिश हुई।

असम : बाढ़ से 91 गांवों के 19210 नागरिक अभी भी प्रभावित

गुवाहाटी (हिंस)। असम के कई हिस्सों में पानी घटने के साथ हालात सुधर रहे हैं, लेकिन शिवसागर, कछार, गोलाघाट, जोरहाट और नगांव जिलों में बाढ़ का संकट और इसका असर अब भी बना हुआ है। इन जिलों में बाढ़ से 91 गांवों के 19210 नागरिक अभी भी प्रभावित हैं। प्रशासन और आपदा प्रबंधन दल प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों में जुटे हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एएसडीएमए) की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार सभी नदियां खतरे के निशान से नीचे बह रहीं है। इस बार की बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या 106 तक पहुंच गयी है। वर्तमान समय में बाढ़ की स्थिति कुल 5 जिलों में बनी हुई है। प्रभावित जिलों में शिवसागर, कछार, गोलाघाट, जोरहाट और नगांव शामिल हैं। बाढ़ से 5 जिलों के 10 राजस्व मंडलों के कुल 91 गांव प्रभावित हैं। वर्तमान समय में राज्य की कुल 19210 आबादी अभी भी प्रभावित हैं एवं 3109.39 हेक्टेयर कृषि भूमि पानी में डूबी हुई है। राज्य सरकार ने बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए अभी भी कुल 5 राहत शिविर एवं 11 राहत वितरण केंद्र समेत कुल 16 शिविर क्रियान्वित रखे हैं। राहत शिविरों में 159 लोग आश्रय लिए हुए हैं, जबकि राहत वितरण केंद्रों पर 12,505 गैर-शिविर निवासी राहत प्राप्त कर रहे हैं। सोमवार को बाढ़ से प्रभावित जानवरों की कुल संख्या 17,648 दर्ज हुई है। 24 अगस्त के आंकड़ों के अनुसार बाढ़ के पानी में शिवसागर जिले में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कच्चे मकानों की कुल संख्या 175 एवं शिवसागर जिले में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त पक्के मकानों की कुल संख्या 20 बतायी गयी है। शिवसागर जिले में आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त कच्चे मकानों की संख्या 298 दर्ज हुई है। शिवसागर जिले में क्षतिग्रस्त पक्के मकानों की कुल संख्या 194 है। क्षतिग्रस्त अन्य झोपड़ियों की कुल संख्या शिवसागर जिले में 25 है। वहीं, क्षतिग्रस्त अन्य मवेशी शेड की शिवसागर जिले में कुल संख्या 145 है। बाढ़ प्रभावितों के बीच राज्य सरकार की ओर से चावल (क्विंटल में) 212.788 , दाल (क्विंटल में) 37.506, नमक (क्विंटल में) 11.2458, मस्टर्ड ऑयल/सरसों का तेल (लीटर में) 102.69 राहत सामग्री बांटी गई। राज्य सरकार के द्वारा बाढ़ प्रभावित इलाकों में बड़े पैमाने पर हुए सड़क, पुल एवं अन्य आधारभूत ढांचे के नुकसान का आकलन किया जा रहा है। साथ ही प्रभावितों की मदद के लिए आर्थिक एवं अन्य सामग्री भी मुहैया कराई जा रही हैं। राज्य सरकार के अलग-अलग मंत्रालय एवं विभागों द्वारा लगातार समीक्षा बैठक कर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

वंदे मातरम् का 150 वर्ष : *नमामि भारतम्* के तहत विशेष पोस्टर जारी

गुवाहाटी (हिंस)। राष्ट्रीय गीत *वंदे मातरम्* के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विद्या भारती पूर्वोत्तर क्षेत्र ने मंगलवार को *नमामि भारतम्* पहल के तहत विशेष पोस्टरों की श्रृंखला जारी की। इस पहल का उद्देश्य *वंदे मातरम्* की गौरवशाली यात्रा, राष्ट्रीय चेतना के निर्माण में इसके योगदान और देशभक्ति की इसकी स्थायी भावना को जन-जन तक पहुंचाना है। पोस्टर विमोचन कार्यक्रम में विद्या भारती पूर्वोत्तर क्षेत्र के संगठन सचिव डॉ. पवन तिवारी, क्षेत्रीय मंत्री जगदिंद्र राय चौधरी, शिशु शिक्षा समिति के अध्यक्ष कुलेंद्र कुमार भगवती, महासचिव जगन्नाथ राजबंशी सहित विद्या भारती के अन्य पदाधिकारी, कार्यकर्ता और शुभचिंतक मौजूद रहे। इस अवसर पर पदाधिकारियों ने कहा कि *वंदे मातरम्* केवल एक गीत नहीं, बल्कि भारत की राष्ट्रीय चेतना, मातृभूमि के प्रति समर्पण और स्वतंत्रता आंदोलन की प्रेरणादायी विरासत का प्रतीक है। राष्ट्रीय गीत के 150 वर्ष पूरे होना प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का विषय है। शिशु शिक्षा समिति, असम के प्रचार संयोजक मुकुटेश्वर गोस्वामी ने कहा कि विद्या भारती पूर्वोत्तर क्षेत्र *वंदे मातरम्* के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व से समाज को परिचित कराने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहा है।

यूपीआई की 10वीं वर्षगांठ पर वैष्णव ने किया चिदंबरम पर कटाक्ष

नई दिल्ली (हिंस)। यूपीआई के दस साल पूरे होने पर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के पुराने संसदीय बयान को लेकर उन पर राजनीतिक कटाक्ष किया है। वैष्णव ने मंगलवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर चिदंबरम के संसद में दिए पुराने भाषण का वीडियो साझा करते हुए लिखा कि 10 साल उन्हें गलत साबित करने के नाम। वैष्णव द्वारा साझा किए गए वीडियो में चिदंबरम संसद में यूपीआई और डिजिटल भुगतान व्यवस्था को लेकर अपनी आपत्तियां और आशंकाएं व्यक्त करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में उनके पुराने बयान के साथ मौजूदा समय में सब्जी विक्रेताओं और छोटे कारोबारियों द्वारा क्यूआर कोड के जरिए भुगतान स्वीकार करने के दृश्य भी दिखाए गए हैं। भाजपा ने भी यूपीआई की दस साल की सफलता को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि चिदंबरम ने यूपीआई की शुरुआत को बड़ी भूल बताया था और संसद में यह आशंका जताई थी कि गरीबों, सब्जी विक्रेताओं तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए इस डिजिटल भुगतान प्रणाली का इस्तेमाल करना मुश्किल होगा। भाजपा के मुताबिक, चिदंबरम का यह आकलन अब यूपीआई के मौजूदा विस्तार के बिल्कुल विपरीत नजर आता है। पार्टी ने कहा कि आज छोटे दुकानदारों, रेहड़ी-पटरी वालों और आम लोगों के बीच क्यूआर कोड आधारित भुगतान बेहद सामान्य हो चुका है। यूपीआई की दस साल की यात्रा के आधिकारिक आंकड़े भी इसकी व्यापक स्वीकार्यता को दर्शाते हैं। 2016-17 में 1.78 करोड़ लेन-देन से बढ़कर 2025-26 में यूपीआई लेन-देन की संख्या 24,162 करोड़ हो गई। इसी अवधि में लेन-देन का मूल्य 0.07 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 314 लाख करोड़ रुपए हो गया। मार्च 2026 में यूपीआई ने एक महीने में 2,264 करोड़ लेन-देन का नया रिकॉर्ड बनाया, जिनका मूल्य 29.53 लाख करोड़ रुपए रहा। यूपीआई की शुरुआत केवल 21 बैंकों के साथ हुई थी लेकिन अब इसके नेटवर्क में 700 से अधिक बैंक शामिल हैं। यूपीआई भारत के डिजिटल भुगतान का करीब 85 प्रतिशत हिस्सा संभाल रहा है और दुनिया के रियल-टाइम भुगतान लेन-देन में भारत की हिस्सेदारी करीब 49 प्रतिशत है। यूपीआई की पहुंच का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि व्यक्ति से व्यापारी लेन-देन में 86 प्रतिशत भुगतान 500 रुपए से कम के हैं। इससे पता चलता है कि यूपीआई का इस्तेमाल छोटे दुकानदारों, रेहड़ी-पटरी वालों और रोजमर्रा की खरीदारी में बड़े पैमाने पर हो रहा है। यूपीआई अब भारत की सीमाओं से बाहर भी पहुंच बना चुका है और आठ देशों में स्वीकार किया जा रहा है।

200 रुपए के लिए बेटे ने की पिता की हत्या

शोणितपुर (हिंस)। असम के ढेकियाजुली स्थित चपाई चाय बागान में महज 200 रुपए को लेकर एक व्यक्ति द्वारा अपने पिता की कथित रूप से पीट-पीटकर हत्या करने का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान सैमसन गुरिया के रूप में हुई है, जबकि आरोपी बेटे का नाम एलेक्सियस गुरिया बताया गया है। घटना चाय बागान के न्यू लाइन इलाके में हुई, जहां आरोपी ने कथित तौर पर लोहे की वस्तु से अपने पिता पर हमला किया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने 200 रुपए के लिए अपनी साइकिल गिरवी रखी थी। इसी रकम को लेकर पिता-पुत्र के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद घटना ने हिंसक रूप ले लिया।

पृष्ठ एक का शेष

बाढ़ प्रभावित किसानों ...

विकास के लिए धन एवं संसाधनों की कमी नहीं होने दी जाएगी। चौहान ने बताया कि असम के लिए करीब 5,000 करोड़ रुपए की आवासीय स्वीकृतियां दी गई हैं। बाढ़ से जिन परिवारों के मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, सर्वे पूरा होने के बाद पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत नए मकानों की स्वीकृति दी जाएगी। पात्र परिवारों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए असम सरकार ने सर्वे की अवधि 15 दिन बढ़ाई है। प्रारंभिक आकलन के अनुसार असम में हाल की बाढ़ से 26,681 मकान प्रभावित हुए हैं और करीब 480 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि असम सरकार द्वारा चाय बागान श्रमिकों को भूमि का पट्टा दिए जाने के बाद अब पात्र श्रमिक परिवारों को भी पीएम आवास योजना का लाभ दिलाया जाएगा। इसके लिए डिजिटल सर्वे के माध्यम से लाभार्थियों की पहचान की जाएगी। केंद्र ने लाभार्थियों की पहचान के लिए असम में विशेष सर्वे विंडो खोलने का निर्णय लिया है। बैठक में बाढ़ से प्रभावित किसानों को फसल नुकसान के बाद आगामी खेती के लिए अतिरिक्त बीज और कृषि सामग्री उपलब्ध कराने पर भी सहमति बनी। सब्जी उत्पादन समेत आवश्यक कृषि गतिविधियों के लिए राज्य को अतिरिक्त सहायता देने पर विचार किया जाएगा। केंद्र का लक्ष्य बाढ़ के बाद कृषि उत्पादन को जल्द पटरी पर लाना है। शिवराज सिंह ने बताया कि वर्ष 2026-27 के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत असम को कुल 832.70 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसमें 553 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता शामिल है। वहीं, आरकेवीवाई के तहत करीब 279.5 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। कृषि मशीनीकरण के लिए एसएमएएम के तहत 33.36 करोड़ रुपए की पहली स्वीकृति जारी की गई है। इसके अलावा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सब्जी उत्पादन, कोल्ड स्टोरेज और फूड प्रोसेसिंग ढांचे को बढ़ावा देने के लिए एमआईडीएच के तहत 96.87 करोड़ रुपए की वार्षिक कार्ययोजना मंजूर की गई है। असम में संरक्षित खेती को बढ़ावा देने के लिए 1,500 नए बांस पॉलीहाउस भी स्वीकृत किए गए हैं। आरकेवीवाई के तहत कीटनाशक परीक्षण प्रयोगशाला और खाद्य तेल परीक्षण प्रयोगशाला के भवनों को भी मंजूरी दी गई है। कृषि मंत्रालय असम की महिला किसानों को पावर वीडर उपलब्ध कराने की योजना पर भी काम कर रहा है। इससे खेती की लागत और श्रम संबंधी समस्याओं को कम करने के साथ महिला किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। बैठक में असम में महिला सशक्तीकरण की प्रगति पर भी चर्चा हुई। राज्य में 9 लाख से अधिक महिलाएं *लखपति दीदी* बन चुकी हैं। असम के जैविक कृषि उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराने के लिए एपीडा और नेशनल ऑर्गेनिक कोऑपरेटिव लिमिटेड के साथ साझेदारी की जा रही है। किसानों को उत्पादन से लेकर पैकेजिंग, ब्रांडिंग और निर्यात तक सहायता देने की योजना है। बैठक में असम की जैव विविधता, मसाला उत्पादन और फॉक्सटेल ऑर्किड के विकास पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने बाढ़ प्रभावित परिवारों, किसानों, चाय बागान श्रमिकों और ग्रामीण गरीबों के लिए केंद्र से अतिरिक्त सहयोग का अनुरोध किया। उन्होंने केंद्र सरकार और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार जताया।

निजी नर्सिंग होम के ...

में मरीजों और उनके परिजनों से जुड़े मामलों को लेकर सरकार के सख्त रुख के संकेत दिए हैं। एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि अब पैसे का भुगतान नहीं कर पाने के कारण किसी मरीज या मृतक के शव को नर्सिंग होम में रोककर नहीं रखा जा सकेगा। उन्होंने कहा कि मरीजों और उनके परिजनों की सहायता के लिए सरकार जल्द ही महत्वपूर्ण कदम उठाने पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार एक हेल्पलाइन नंबर जारी करेगी, जिस पर नर्सिंग होम के खिलाफ कंप्लेंट किया जा सकता है। इस कंप्लेंट पर पुलिस तत्काल कार्रवाई करेगी। इस संबंध में आगामी कैबिनेट बैठक में अहम निर्णय लिए जाने की संभावना है।

कश्मीर में तीन अलग...

वर्करों की पहचान आशिक हुसैन कुमार, आरिफ कुमार और हैरिस मंजूर के तौर पर हुई है। सुरक्षाबलों ने सोमवार देर रात शोपियां जिले से भी तीन ओजीडब्लू को गिरफ्तार किया था। तलाशी के दौरान उनके पास से दो हैंड ग्रेनेड और हिज्बुल मुजाहिदीन आतंकी संगठन से जुड़ी कुछ आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई। गिरफ्तार लोगों की पहचान जुनैद अहमद डार, आमिर यूसुफ और जुनैद मुजफ्फर के तौर पर हुई है। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा संबंधी मिली जानकारी के आधार पर यारवान जंगल इलाके में घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया गया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन के दौरान संयुक्त टीमों ने दो लोगों को जंगल से सीबी नाथ गांव की ओर संदिग्ध हालत में आते देखा। सतर्क टीमों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों लोगों को पकड़ लिया। पकड़े गए लोगों की पहचान लतीफ अहमद दीदाद और एजाज अहमद बजाद के तौर पर हुई है। अधिकारियों ने बताया कि तलाशी के दौरान उनके पास से एक पिस्तौल, पिस्तौल की 12 गोलियां और एक हैंड ग्रेनेड बरामद किया गया और संदिग्धों को हिरासत में ले लिया गया। आर्म्स एक्ट और गैर-कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया और उनकी गतिविधियों का पता लगाने, बरामद हथियारों और गोला-बारूद के स्रोत और आगे के संबंधों की पहचान करने के लिए जांच शुरू की गई।

मनुस्मृति पर आघात ...

किया गया था और श्रीराम सेतु तोड़ने तथा श्रीराम मंदिर का विरोध का अभियान चलाया गया था, यह देश की जनता को भली-भांति याद है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी मनुस्मृति पर बोलने की बजाय बांग्लादेश में निरीह हिंदुओं के निरंतर हो रहे कत्लेआम पर बोलें। उन्होंने कहा कि राजनीति में अयोग्य, अदूरदर्शी सत्तालोलुप तत्त्वों का बोलबाला बढ़ता जा रहा है और देश विरोधी अराजक तत्व इसका लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं।

फर्जी आईटीसी मामले ...

न्यू राणा हाउस और गाजियाबाद के सुधा स्टील से 1.1 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी बरामद की थी। साथ ही कई डिजिटल उपकरण, दस्तावेज और रजिस्टर भी जब्त किए गए थे। ईडी ने बताया कि अब तक की कार्रवाई में कुल 3.6 करोड़ रुपए नकद बरामद हुए हैं। उल्लेखनीय है कि मामला जंबूद्वीप एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स लिमिटेड से जुड़ा है, जिस पर फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) बनाने और पास करने का आरोप है। जांच में सामने आया है कि कंपनी ने फर्जी चालान और ई-वे बिल के जरिए बिना माल की वास्तविक आवाजाही के आईटीसी का निर्माण और पासिंग किया। इसमें व्यापक सर्कुलर लेनदेन, तेजी से फंड्स की लेयरिंग और नकद निकासी शामिल रही। जीएसटी अधिकारियों ने 9.63 करोड़ रुपए का फर्जी आईटीसी लेने और 10.28 करोड़ रुपए का आईटीसी पास करने की पुष्टि की है, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ। ईडी की तलाशी का उद्देश्य अपराध से प्राप्त धन का पता लगाना, अन्य लाभार्थियों की पहचान करना और नेटवर्क से जुड़े सबूत जुटाना था। ईडी ने कहा कि आगे की जांच जारी है और नेटवर्क से जुड़े अन्य लाभार्थियों तक पहुंचने के लिए दस्तावेजों का विश्लेषण किया जा रहा है।

सरकारी भर्तियों की मांग...

गोलंबर सहित प्रमुख मार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी थी। छात्र जैसे ही जेपी गोलंबर पहुंचे, पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बैरिकेडिंग कर दी। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग हटाकर आगे बढ़ने का प्रयास किया। इसके बाद पुलिस और छात्रों के बीच टकराव की स्थिति बन गई। पुलिस और सीआरपीएफ की टीमें छात्रों को आगे बढ़ने से रोकने में जुटी रहीं। प्रदर्शन के कारण पटना के कई प्रमुख मार्गों पर तनाव की स्थिति बनी हुई है और यातायात भी प्रभावित होने की सूचना है। आंदोलन कर रहे छात्रों की प्रमुख मांग बीपीएससी टीआरई-4 शिक्षक भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया को सरल और स्पष्ट करना है। छात्रों की मांग है कि टीआरई-4 में एक ही परीक्षा के माध्यम से प्रारंभिक परीक्षा (पीटी) और मुख्य परीक्षा (मेंस) की प्रक्रिया पूरी की जाए। छात्रों का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया को इस तरह बनाया जाना चाहिए कि अभ्यर्थियों को बार-बार अलग-अलग परीक्षाओं में शामिल नहीं होना पड़े। उनका तर्क है कि इससे भर्ती प्रक्रिया लंबी होने के साथ अभ्यर्थियों पर अतिरिक्त आर्थिक और मानसिक दबाव भी पड़ता है। इसके साथ ही छात्र टीआरई-4 भर्ती प्रक्रिया में नेगेटिव मार्किंग खत्म करने और परीक्षा प्रक्रिया को अधिक स्पष्ट बनाने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों की एक प्रमुख मांग बिहार की सरकारी नौकरियों में 100 प्रतिशत डोमिसाइल नीति लागू करने की भी है। छात्रों का कहना है कि राज्य की सरकारी नौकरियों में बिहार के स्थानीय अभ्यर्थियों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। छात्रों ने बिहार कर्मचारी चयन आयोग (बीएसएससी) से संबंधित भर्ती प्रक्रियाओं में भी बदलाव की मांग उठाई है। इनमें संविदा कर्मचारियों को मिलने वाला वेटेज समाप्त करने की मांग शामिल है। छात्रों ने बीएसएससी सीजीएल-4, बीएसओ और एईडीओ परीक्षाओं की तारीख जल्द जारी करने की मांग की है।

एच1एन1 को लेकर...

जरिए वायरस की जीनोमिक और महामारी संबंधी निगरानी की जा रही है। जांच में भारत में फैल रहे एच1एन1 वायरस को ए/मिसौरी /11/2025 पीडीएम 09-लाइक वायरस के रूप में पहचाना गया है। इसके हेमाग्लुटिनिन जीन के विश्लेषण में इसे क्लेड 6बी. 1ए5ए2ए, सबक्लेड डी.3.1.1 में रखा गया है। डॉ. राजीव बहल के अनुसार, यह वायरस वंशावली भारत में साल 2025 से लगातार प्रसारित हो रही है। वायरस में पाए गए आनुवंशिक बदलाव सामान्य मौसमी बदलाव हैं, जिन्हें एंटीजेनिक ड्रिफ्ट कहा जाता है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि इन बदलावों से किसी नए या अधिक खतरनाक वायरस के उभरने का संकेत नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि ज़्यादातर लोगों में, सही देखभाल, भरपूर आराम और शरीर में पानी की सही मात्रा बनाए रखने से लक्षण बेहतर हो जाते हैं। सिर्फ़ एच1एन1 होने का मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति को गंभीर बीमारी हो जाएगी या उसे अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, मौसमी इन्फ्लुएंजा, जिसमें एच1एन1 भी शामिल है, स्वस्थ लोगों में आमतौर पर हल्का और स्व-सीमित संक्रमण होता है। इसके प्रमुख लक्षणों में बुखार, खांसी, गले में खराश, सिरदर्द, शरीर में दर्द और थकान शामिल हैं। हालांकि, बुजुर्गों, छोटे बच्चों, पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे लोगों और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले व्यक्तियों में जटिलताओं का खतरा अधिक हो सकता है। ऐसे लोगों को फ्लू जैसे लक्षण होने पर समय पर चिकित्सकीय सलाह दी गई है। सरकार ने लोगों को खांसते या छींकते समय मुंह और नाक ढंकने, नियमित रूप से हाथ धोने, बीमार होने पर घर पर रहने, पर्याप्त पानी पीने और आराम की सलाह दी है। साथ ही लोगों को बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीवायरल या एंटीबायोटिक दवाएं नहीं लेने को कहा गया है। सरकार ने कहा है कि इन्फ्लुएंजा की गतिविधि, वायरस के प्रकार और बीमारी की गंभीरता में होने वाले बदलावों की लगातार निगरानी जारी रहेगी। मौजूदा सबूतों के आधार पर वायरस के व्यवहार में कोई असामान्य बदलाव या किसी नई स्ट्रेन के उभरने के संकेत नहीं हैं।

10 दिनों में तीसरी ...

सोशल मीडिया पर कथित तौर पर *पाकिस्तान जिंदाबाद* और *हिंदुस्तान मुर्दाबाद* जैसे नारे भी लगाए गए हैं। पिछले 10 दिनों में मुख्यमंत्री को दो बार धमकी मिलने के बाद अब तीसरी धमकी सामने आई है। मामले को लेकर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की ओर से सोशल मीडिया पर प्रसारित सामग्री की जांच की जा रही है।

राहुल गांधी हिंदू धर्मशास्त्र...

हिंदू धर्मशास्त्रों को लेकर समाज में विभिन्न मत और व्याख्याएं प्रचलित हैं। ऐसे में किसी ग्रंथ के संबंध में एकतरफा धारणा प्रस्तुत करने के बजाय उसके मूल स्वरूप, संदर्भ, उद्देश्य और शास्त्रीय परंपरा को समझना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक मंचों से धर्मग्रंथों पर की जाने वाली टिप्पणियों का समाज के विभिन्न वर्गों पर प्रभाव पड़ता है। उन्होंने मनुस्मृति के श्लोक *पिता रक्षति कौमारे, भर्ता रक्षति यौवने...* का उल्लेख करते हुए कहा कि इसमें स्त्री की परतंत्रता की बात नहीं कही गई है, बल्कि परिवार और समाज की ओर से उसकी सुरक्षा और दायित्व का उल्लेख है। उन्होंने कहा कि संस्कृत में *रक्षति* का अर्थ सुरक्षा करना है, न कि किसी प्रकार का नियंत्रण स्थापित करना। शंकराचार्य ने कहा कि सनातन परंपरा में नारी को शक्ति और सम्मान का स्वरूप माना गया है। उन्होंने ऋग्वेद की ऋषिकाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति परस्पर पूरकता और सम्मान की भावना पर आधारित रही है।

मणिपुर में सुरक्षा बलों ...

सीआरपीएफ, आरएएफ और कोब्रा की संयुक्त टीम ने घेराबंदी एवं तलाशी अभियान चलाया। अभियान के दौरान दो देशी 12-बोर बंदूकें, विभिन्न निर्माताओं की 14 अन्य 12-बोर बंदूकें, 1,225 राउंड 12-बोर गोलियां, छह वीएचएफ/वायरलेस सेट और तीन चार्जर बरामद किए गए। इसके अलावा एक गोल्डन एंटलर टेलीस्कोप, 18 बीपी वेस्ट और एक पाउच भी जब्त किया गया। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा बलों की वापसी के दौरान मुख्य रूप से महिलाओं सहित ग्रामीणों ने पत्थरों से सड़क अवरुद्ध कर दी और कथित तौर पर सत्यापन नहीं किए गए हथियार एवं गोला-बारूद वापस करने की मांग की। बाद में सुरक्षा बलों ने स्थिति को नियंत्रित कर लिया। एक अन्य अभियान में सीडीओ-काकचिंग ने इंफाल ईस्ट जिले के इरिलबुंग थाना क्षेत्र के कियामगेई अवांग लीकाई में तलाशी अभियान चलाकर आरपीएफ/पीएलए के सक्रिय कैडर नामेइराकपम संजू मीतेई उर्फ नगनबा (35) को उसके आवास से गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से एक एके राइफल, एक सीएमजी कार्बाइन, विभिन्न हथियारों की नौ मैगजीन, अलग-अलग कैलिबर के 737 राउंड गोला-बारूद, तीन बीपी प्लेट और तीन बीपी जैकेट बरामद किए गए। वहीं, 23 अगस्त को सीडीओ-आईडब्ल्यू की टीमों ने मोइदांगपोक मानिंग लीकाई में तलाशी एवं जांच के दौरान ओइनाम गिप्सन सिंह (26) उर्फ जिप्सी उर्फ चेइचातपा को गिरफ्तार किया। वह इंफाल पश्चिम जिले के क्वाकैथेल लैश्राम लीकाई का रहने वाला है। उसके पास से .32 पिस्तौल और चार राउंड गोलियों से भरी मैगजीन बरामद की गई। सुरक्षा बलों ने मणिपुर में उग्रवादी गतिविधियों, जबरन वसूली और अवैध हथियारों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है।

नौसेना दूसरे स्वदेशी...

हालात में काम करने वाले गोताखोरों को लगातार मदद मिलेगी। यह सबमरीन रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद करने की नौसेना की क्षमता को भी बढ़ाएगा। जहाज में नेविगेशन, प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट और सटीक स्टेशन कीपिंग के लिए मॉडर्न सिस्टम हैं। साथ ही डाइविंग, पानी के अंदर दखल और मेडिकल सपोर्ट के लिए खास सुविधाएं भी हैं। ये क्षमताएं निपुण को सतह के नीचे मुश्किल ऑपरेशन के लिए एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करने में मदद करती हैं। *निपुण* की कमीशनिंग से नौसेना की भारत के समुद्री इलाकों में खास डाइविंग और पानी के अंदर मिशन करने की क्षमता और मजबूत होगी। इस देश में बने प्लेटफॉर्म का शामिल होना देश के शिपबिल्डिंग इकोसिस्टम की बढ़ती क्षमता को भी दिखाता है, ताकि नौसेना की ऑपरेशनल जरूरतों को पूरा करने के लिए टेक्नोलॉजी के हिसाब से एडवांस और खास जहाज बनाए जा सकें। नौसेना के कैप्टन विवेक मधवाल ने बताया कि जहाज पर लगा क्रेस्ट डाइविंग सपोर्ट वेसल के तौर पर जहाज की मुख्य भूमिका और गहरे समुद्र में डाइविंग से जुड़ी हिम्मत, धीरज और प्रोफेशनल काबिलियत को दिखाता है।

सरकार जातिगत जनगणना को ...

राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को जातिगत जनगणना के संबंध में 21 पन्नों का संयुक्त पत्र लिखा है। यह कांग्रेस की ओर से इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री को लिखा गया तीसरा पत्र है। इससे पहले 16 अप्रैल 2023 और 5 मई 2025 को भी खरगे ने पत्र लिखे थे लेकिन अब तक किसी का जवाब नहीं मिला। उन्होंने कहा कि पार्टी लगातार मांग कर रही है कि इस विषय पर सभी राजनीतिक दलों और राज्य सरकारों से चर्चा की जाए और सामाजिक न्याय को ध्यान में रखकर जनगणना कराई जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार जानबूझकर इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए है और ईमानदारी से जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहती।

डीआरडीओ की मिसाइल ...

रक्षा विनिर्माण क्षेत्र के विकास में सहयोग करना है। डीआरडीओ उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण, उन्हें अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ढालने और रक्षा प्रणाली में शामिल करने की प्रक्रिया को सुगम बनाने तथा देश की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से भारतीय उद्योग जगत के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रौद्योगिकी का यह हस्तांतरण घरेलू उद्योगों को निर्धारित योग्यताओं, प्रमाणन और विनियामक आवश्यकताओं के अनुसार स्वदेशी उत्पादन में सक्षम बनाकर रक्षा क्षेत्र के अनुकूल परिवेश में उनकी अधिक भागीदारी को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इस कदम का मकसद रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र में भारतीय उद्योग की भूमिका को बढ़ाना और देश के अंदर औद्योगिक पैमाने पर मिसाइल उत्पादन को तेजी से बदलना है।

राष्ट्रपति ने ओणम और ...

नई फसल के आने की खुशी में प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। यह पर्व देश की समृद्ध संस्कृति विरासत और भाईचारे का प्रतीक है तथा विविधता में एकता की भावना को मजबूत करता है। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर नौका दौड़, लोक नृत्य तथा अन्य पारंपरिक कलाओं और खेलों का विशेष महत्व होता है। ये केरलम की संस्कृति और जीवन-मूल्यों को दर्शाते हैं।

प्रधानमंत्री समेत कई ...

गर्व होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने लोगों से अपना यूपीआई अनुभव साझा करने और यह बताने की अपील की कि इसने आपकी जिंदगी पर क्या प्रभाव डाला। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोजी के नेतृत्व यूपीआई के 10 साल परिवर्तनकारी बदलाव के एक दशक की कहानी है। एक साहसी सोच से लेकर डिजिटल पेमेंट की सफलता की कहानी बनने तक, यूपीआई ने हर भारतीय के लिए लेन-देन को तेज, आसान, सुरक्षित और सुलभ बना दिया है। यह डिजिटल इंडिया की ताकत है। सशक्तिकरण, समावेश और जीवन को आसान बनाने के लिए तकनीक।

जागीरोड में मंत्री पीयूष ने किया सीएम-एएए लाभार्थियों से संवाद

मोरीगांव (हिंस)। असम के कृषि, सिंचाई एवं संसदीय कार्य मंत्री पीयूष हजारिका ने मंगलवार को जागीरोड में मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम अभियान (सीएम-एएए) के 1,000 से अधिक लाभार्थियों के साथ संवाद किया। इस दौरान उन्होंने योजना के तहत स्थापित उद्यमों की जमीनी प्रगति की समीक्षा की। मंत्री ने लाभार्थियों को पारंपरिक व्यापार के साथ-साथ मुर्गीपालन, सूअर पालन, मत्स्य पालन, बागवानी और बहुफसली खेती जैसे उत्पादन आधारित क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देने की अपील की। उन्होंने उद्योग विभाग से कृषि एवं उत्पादन गतिविधियों से जुड़े लाभार्थियों को

प्राथमिकता देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर खाद्य उत्पादों का उत्पादन बढ़ाना असम को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आवश्यक है। हजारिका ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व में शुरू किया गया सीएम-एएए युवाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और टिकाऊ उद्यमिता को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि प्रारंभिक वित्तीय सहायता का उचित उपयोग नहीं करने वाले लाभार्थियों को आगे की किस्तों से वंचित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकारी धन का उपयोग निर्धारित उद्देश्य के लिए ही किया जाना चाहिए। मंत्री ने युवाओं से खाली पड़ी जमीन का उपयोग आय के स्रोत के रूप में करने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि कृषि विभाग अगले वर्ष बड़े पैमाने पर पौध वितरण अभियान शुरू करेगा, जिसमें नारियल, सुपारी, अमरूद, लीची और एप्पल बेर जैसी व्यावसायिक फलों की किस्मों के पौधे वितरित किए जाएंगे। उन्होंने मखाना की खेती की आय क्षमता का भी उल्लेख किया और इच्छुक किसानों को विभाग की ओर से हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया। साथ ही, मंत्री ने मोरीगांव के जिला कृषि अधिकारी को पूरे जिले में व्यापक जागरूकता शिविर आयोजित करने का निर्देश दिया, ताकि इच्छुक उद्यमी कृषि अवसंरचना कोष के माध्यम से कृषि आधारित व्यवसाय स्थापित करने के लिए उपलब्ध सहायता का लाभ उठा सकें।

नगांव लोस उपचुनाव कांग्रेस ने मांगें आवेदन के साथ एक लाख रुपए शुल्क

गुवाहाटी (हिंस)। नगांव लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी ने टिकट के दावेदारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। प्रत्याशियों को आवेदन पत्र के साथ एक लाख रुपए जमा करना होगा। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 28 अगस्त निर्धारित की गई है। उल्लेखनीय है कि बीते विधानसभा चुनाव के मौके पर भी प्रदेश कांग्रेस ने टिकट की मांग करने वाले प्रत्येक प्रत्याशी से 50 हजार रुपए बतौर शुल्क वसूले थे। टिकट नहीं दिए जाने की स्थिति में इसे लौटाया नहीं गया।

असम में रेशम उत्पादन क्षेत्र को डिजिटल मजबूती, मंत्री बिश्वजीत दैमारी ने डिजिटल प्रणाली का किया शुभारंभ

गुवाहाटी (हिंस)। असम सरकार के रेशम निदेशालय ने मंगलवार को रेशम उत्पादन प्रबंधन सूचना प्रणाली का औपचारिक शुभारंभ किया। इस डिजिटल मंच के माध्यम से राज्य के रेशम उत्पादन क्षेत्र में डिजिटल शासन, सूचना प्रबंधन और हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय को बढ़ावा मिलेगा। असम सरकार के हथकरघा, वस्त्र एवं रेशम मंत्री बिश्वजीत दैमारी ने इस डिजिटल प्रणाली का औपचारिक शुभारंभ किया। इस अवसर पर रेशम निदेशक लखीमी दत्ता, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के विशेष सचिव एवं सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी कौशर जे हिलाली, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के निदेशक अंकुर भराली, वरिष्ठ एसीएस अधिकारी काजोरी राजखोवा समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। यह प्रणाली एरी, मूगा, शहतूत और तसर रेशम उत्पादन को एकीकृत करने वाले डिजिटल मंच के रूप में विकसित की गई है। इसके जरिए किसान, किसान हित समूह, जिला रेशम कार्यालय और राज्य प्रशासन एक साझा

डिजिटल मंच से जुड़ सकेंगे। इस प्रणाली का उद्देश्य सूचनाओं के निर्बाध आदान-प्रदान, प्रभावी निगरानी और रेशम उत्पादन क्षेत्र से जुड़े विभिन्न स्तरों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करना है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री दैमारी ने रेशम उत्पादन क्षेत्र में पारदर्शिता, बेहतर समन्वय और सेवाओं की उपलब्धता बढ़ाने के लिए तकनीक एवं डिजिटल मंचों को अपनाने के महत्व पर जोर दिया।

गोलाघाट में पैंक्रियाज के ऑपरेशन के बाद महिला की मौत, डॉक्टर पर गंभीर आरोप

गोलाघाट (हिंस)। असम के गोलाघाट में पैंक्रियाज की बीमारी के ऑपरेशन के करीब 25 दिन बाद गुवाहाटी में इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई। मृतका के परिजनों ने ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। परिजनों के अनुसार, ज्योस्मिता बोरा का 25 जुलाई को गोलाघाट शहर स्थित एचजीएम नर्सिंग होम में पैंक्रियाज का ऑपरेशन किया गया था। उनका आरोप है कि ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर ने महिला के पेट में करीब डेढ़ फुट लंबा चीरा लगाया। बताया गया

है कि यह ऑपरेशन नुमलीगढ़ रिफाइनरी के अधीन विवेकानंद अस्पताल के डॉ. भास्कर हाजरिका ने किया था। ऑपरेशन के बाद ज्योस्मिता की हालत बिगड़ने पर उन्हें गुवाहाटी ले जाया गया, जहां करीब 25 दिनों तक उपचार चलने के बाद उनकी मौत हो गई। ज्योस्मिता के परिजनों ने डॉ. भास्कर हाजरिका के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए पूरे मामले की जांच की मांग की है। हालांकि, मामले में डॉक्टर या संबंधित नर्सिंग होम की ओर से तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मोरीगांव में उपचुनाव की तैयारियों की समीक्षा की

मोरीगांव (हिंस)। असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) अनुराग गोयल ने मंगलवार को मोरीगांव जिले का दौरा कर आगामी उपचुनाव के लिए जिला प्रशासन की तैयारियों की समीक्षा की। जिला आयुक्त कार्यालय के कांफ्रेंस हॉल में मुख्य निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। जिला आयुक्त सृष्टि सिंह ने उन्हें चुनाव के सुचारु संचालन के लिए की जा रही प्रशासनिक तैयारियों और व्यवस्थाओं की जानकारी दी। अनुराग गोयल ने चुनाव संबंधी विभिन्न तैयारियों की समीक्षा की, जिसमें लॉजिस्टिक व्यवस्था, ईवीएम की तैनाती तथा विभिन्न चुनावी प्रकोष्ठों के कामकाज और आपसी समन्वय शामिल था। उन्होंने अधिकारियों को सभी आवश्यक तैयारियां समय पर पूरी करने तथा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और निर्देशों का

कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बैठक में जिला विकास आयुक्त ओरपा बागलारी, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्यजीत चेतिया, अतिरिक्त जिला आयुक्तों, सहायक आयुक्तों, निर्वाचन अधिकारी, सर्किल अधिकारियों, ईवीएम अधिकारियों और विभिन्न प्रकोष्ठों के प्रभारी अधिकारियों सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

विश्वनाथ सदर पुलिस सभा कक्ष का उद्घाटन

विश्वनाथ चरिआली (विभास)। सांसद रंजीत दत्ता ने आज विश्वनाथ चरिआली सदर पुलिस स्टेशन के परिसर में सांसद निधि से लगभग 22 लाख रुपए की लागत से निर्मित पुलिस सम्मेलन कक्ष का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में सांसद के साथ-साथ आयुक्त करबी सैकिया करण, बिहाली के विधायक मुनिन्द्र दास, जिला वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आसिफ अहमद और जिले के अन्य शीर्ष पुलिस अधिकारी उपस्थित थे।

लखीमपुर के जेल रोड पर धू-धू कर जला पाइप से लदा ट्रक

लखीमपुर (हिंस)। असम के लखीमपुर स्थित जेल रोड पर मंगलवार को पाइप से लदा एक ट्रक अचानक आग की चपेट में आ गया। देखते ही देखते ट्रक धू-धू कर जलने लगा, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, बिजली के तार में शॉर्ट सर्किट होने के कारण ट्रक में अचानक आग लगी। आग तेजी से फैलने से ट्रक में लदे पाइप भी इसकी चपेट में आ गए। घटना में किसी के हताहत होने की तत्काल सूचना नहीं है। आग लगने के कारणों और नुकसान का विस्तृत ब्योरा अभी सामने नहीं आया है।

कामरूप में असम के पहले बेस आइसोलेशन तकनीक युक्त मॉडल जिला आपातकालीन संचालन केंद्र का उद्घाटन

रंगिया (विभास)। कामरूप जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से एकीकृत जिला आयुक्त कार्यालय परिसर में नवनिर्मित मॉडल जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र का औपचारिक उद्घाटन किया। असम सरकार की अतिरिक्त मुख्य सचिव सह एएसडीएमए की मुख्य कार्यकारी अधिकारी एल स्वीटी चांगसन ने कामरूप के जिला आयुक्त सह कामरूप डीडीएमए के अध्यक्ष देवेन कुमार मिश्रा की उपस्थिति में इसका उद्घाटन किया। इस केंद्र का उद्घाटन राज्य में आपदा तैयारियों और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली के बुनियादी ढांचे को अधिक मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। नया मॉडल आपातकालीन परिचालन केंद्र का एक उल्लेखनीय पहलू इसके निर्माण में *बेस आइसोलेशन तकनीक* का उपयोग है। भूकंप के दौरान कंपनों और ऊर्जा के प्रभाव को कम करके महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को सुरक्षित रखने के लिए उपयोग की जाने वाली यह उन्नत भूकंप-रोधी तकनीक असम में पहली बार इस प्रकार के केंद्र में इस्तेमाल की गई है। इस तकनीक का उपयोग राज्य में आपदा-प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के निर्माण के क्षेत्र में एक उच्च मानक स्थापित

करेगा। यह मॉडल जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र कामरूप जिले में आपदा और आपातकालीन प्रबंधन के लिए एक केंद्रीकृत नियंत्रण और समन्वय केंद्र के रूप में कार्य करेगा। बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, आगजनी, औद्योगिक दुर्घटनाओं और अन्य आपदाओं के समय यह केंद्र त्वरित समन्वय, संचार, सूचना प्रबंधन, स्थिति के मूल्यांकन और निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सप्ताह के सातों दिन 24 घंटे कार्यरत रहने के लिए नियोजित यह केंद्र आपातकालीन स्थितियों में बिना किसी बाधा के कार्य जारी रखने में मदद करेगा। यह जिला प्रशासन, आपातकालीन सेवाओं, विभिन्न विभागों, त्वरित प्रतिक्रिया एजेंसियों और अन्य संबंधित हितधारकों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करेगा। इस केंद्र के माध्यम से आपातकालीन स्थिति में सूचनाओं के त्वरित आदान-प्रदान, समन्वित राहत अभियानों तथा जनशक्ति, सामग्री एवं अन्य संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन को बल मिलेगा। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए एल. स्वीटी चांगसन ने परियोजना की नवीन विशेषताओं और भूकंप-संवेदनशील क्षेत्र के रूप में असम के लिए इसके महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भूकंप जैसी आपदाओं से निपटने के लिए आवश्यक आधुनिक और भूकंप-रोधी निर्माण तकनीक का समावेश इस केंद्र को एक विशेष आयाम प्रदान करता है। उन्होंने आगे कहा कि एक आधुनिक और स्वतंत्र आपातकालीन परिचालन केंद्र होने से अधिकारी एक ही स्थान से आपातकालीन प्रतिक्रिया गतिविधियों का संचालन, समन्वय और नियंत्रण कर सकेंगे, जिससे प्राकृतिक आपदाओं के दौरान अधिक त्वरित, समन्वित और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित होगी।

रंगिया में भारी मात्रा में गांजा जब्त, एक गिरफ्तार

रंगिया (विभास)। रंगिया पुलिस ने एक विशेष अभियान चलाकर भारी मात्रा में अवैध गांजा जब्त किया। इस संबंध में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, 23 अगस्त की रात करीब 10 बजे रंगिया के सहायक आयुक्त, सह-जिला आयुक्त और सह-जिला पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में पुलिस टीम ने पीतांबर हाटबजाली गांव में छापेमारी की। इस कार्रवाई के दौरान गांव के निवासी (दिवंगत हरकांत कुमार के पुत्र) विपुल कुमार के घर से 3.745 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपी विपुल कुमार को मौके से ही हिरासत में ले लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जब्त गांजे को अपनी कस्टडी में ले लिया है और घटना की आगे की जांच जारी है।

फकीराग्राम नगरपालिका में विदाई समारोह आयोजित

कोकराझाड़ (हिंस)। फकीराग्राम नगरपालिका के सभाकक्ष में मंगलवार को विदाई समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में नगरपालिका की कार्यपालक अधिकारी नवनीता बोड़ो तथा बड़ा बाबू बाबुल धर को औपचारिक रूप से विदाई दी गई। नगरपालिका के अध्यक्ष सुल्तान आलम ने दोनों विदाई अधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए उनके कार्यकाल और योगदान की सराहना की। उन्होंने उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर नगरपालिका के उपाध्यक्ष प्रणव शर्मा सहित सभी वार्ड पार्षद एवं नगरपालिका के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। समारोह में उपस्थित लोगों ने विदाई ले रहे दोनों अधिकारियों के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त कीं।

स्पेन के दत्तक माता-पिता को बच्चे का औपचारिक हस्तांतरण

कामरूप, अमीनगांव (विभास)। कामरूप जिला प्रशासन और जिला बाल संरक्षण इकाई, कामरूप के तत्वावधान में तथा विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्था, बोको के सहयोग से आज अमीनगांव स्थित एकीकृत जिला आयुक्त कार्यालय के सभाकक्ष में औपचारिक रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय दत्तक ग्रहण हस्तांतरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में स्पेन से आए दत्तक ग्रहणकर्ता माता-पिता को एक बच्चा औपचारिक रूप से सौंपा गया। कामरूप के जिला आयुक्त देव कुमार मिश्र की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में कामरूप जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण के सचिव शरीफ उद्दीन अहमद पठान, अतिरिक्त जिला आयुक्त (समाज कल्याण) गीताश्री लाचित और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पूनम पेगु उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित

करते हुए जिला आयुक्त देव कुमार मिश्र ने कहा कि दत्तक ग्रहण नियम, 2022 के तहत इस कानूनी प्रक्रिया के सफलतापूर्वक संपन्न होने से भारत और स्पेन के बीच मैत्रीपूर्ण और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बच्चे के सुखद और स्नेहमय वातावरण में बड़े होने की उम्मीद जताते हुए उन्होंने आशा व्यक्त की कि भविष्य में बच्चे को असम आने का अवसर दोबारा मिलेगा। जिला आयुक्त ने दत्तक ग्रहण प्रक्रिया को सुचारू रूप से पूरा करने में सहयोग देने वाले सभी विभागों, एजेंसियों और हितधारकों का आभार व्यक्त किया। इसके साथ ही, उन्होंने स्पेन की अधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण एजेंसी के प्रतिनिधि एवं अनुवादक दिलीप कुमार को दत्तक माता-पिता और अधिकारियों के बीच संचार की सुविधा प्रदान करने में उनके सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। कामरूप जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण के सचिव ने इस सफल दत्तक ग्रहण प्रक्रिया का साक्षी बनने पर प्रसन्नता व्यक्त की। वहीं दूसरी ओर, दत्तक माता-पिता ने पूरी प्रक्रिया के दौरान जिला प्रशासन और संबंधित अधिकारियों द्वारा दिए गए सहयोग के लिए हार्दिक आभार जताया। यह दत्तक ग्रहण प्रक्रिया किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2021 में संशोधित) और दत्तक ग्रहण नियम, 2022 के तहत निर्धारित विस्तृत कानूनी प्रक्रिया के अनुसार पूरी की गई। पूरी प्रक्रिया केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी, जिला बाल संरक्षण इकाई कामरूप, विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्था बोको और स्पेन की अधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण एजेंसी के बीच समन्वय के माध्यम से संपन्न हुई।

धुबड़ी भोलानाथ महाविद्यालय में भूमि जन सेवा फाउंडेशन की बैठक संपन्न

धुबड़ी (विभास)। समाज के प्रति जवाब देही और जन सेवा के उद्देश्य से गठित भूमि जन सेवा फाउंडेशन जन कल्याण कौशल विभाग पर्यावरण संरक्षण और जैविक कृषि के क्षेत्र में काम करने लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है यह बात भूमि जन सेवा फाउंडेशन के संस्थापक शिवम ब्रह्म ने कल आयोजित धुबड़ी भोलानाथ महाविद्यालय के डिजिटल क्लासरूम में पहली बैठक में कहीं। इस बैठक में धुबड़ी के विशिष्ट समाजसेवी उत्तम प्रसाद, जीतू मणि दास, फाउंडेशन के संस्थापक शिवम वर्मा के साथ फाउंडेशन के सदस्य उपस्थित थे। बैठक में फाउंडेशन की आगामी कार्यक्रम संगठन को मजबूत करने और समाज के समग्र विकास के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर विस्तार से चर्चा की गई। फाउंडेशन ने आने वाले दिनों में विशेष रूप से जनकल्याण, युवा समाज का कौशल विकास इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी और नेतृत्व विकास प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए सहायता पर्यावरण संरक्षण वृक्षारोपण और जैविक कृषि के प्रसार के क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई गई है। फाउंडेशन की ओर से कहा गया है कि केवल सरकार या किसी एक संगठन के प्रयास से समाज का पूर्ण विकास संभव नहीं है समाज के प्रत्येक नागरिक की भागीदारी और सहयोग के माध्यम से ही एक स्वस्थ आत्मनिर्भर और उन्नयन समाज का निर्माण किया जा सकता है इस उद्देश्य से भूमि जन सेवा फाउंडेशन किसी भी राजनीति या व्यक्तिगत स्वास्थ्य से ऊपर उठकर जन सेवा और समाज के विकास के लिए काम करते रहने की बात कही है।

सप्तधारा एक मजबूत, आत्मनिर्भर और विकसित भारत का रोडमैप है : डॉ. संबित पात्रा

गुवाहाटी। आज नई दिल्ली में एक प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद डॉ. संबित पात्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के *शक्ति की सप्तधारा* (ताकत के सात आधार) के विजन को 2047 तक *विकसित भारत* बनाने का रोडमैप बताया। डॉ. पात्रा ने कहा कि *सप्तधारा* भारत की आर्थिक ताकत, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, राष्ट्रीय सुरक्षा, सस्टेनेबिलिटी (स्थिरता) और सांस्कृतिक सॉफ्ट पावर को एक साथ लाती है। इससे देश अगले पांच से सात वर्षों में वह हासिल कर पाएगा जो पिछले कई दशकों में हासिल नहीं हो सका था। उन्होंने *सप्तधारा* के पहले आधार-मैन्युफैक्चरिंग पावर-पर प्रकाश डाला, जिसमें हमने आयात पर निर्भरता से हटकर ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग देश बनने की ओर कदम बढ़ाया है। डॉ. पात्रा ने आयात पर निर्भर अर्थव्यवस्था से ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की भारत की यात्रा को रेखांकित किया। इलेक्ट्रॉनिक्स का उत्पादन 2014-15 में लगभग 1.9 लाख करोड़ से बढ़कर 2024-25 में 12 लाख करोड़ हो गया, जबकि मोबाइल-फोन का उत्पादन 18,000 करोड़ से बढ़कर 5.45 लाख करोड़ हो गया। मोबाइल-फोन का निर्यात लगभग 1,500 करोड़ से बढ़कर 2 लाख करोड़ हो गया। *सेमीकॉन इंडिया 2.0* जैसी पहलों के साथ, भारत डिजाइन और कंपोनेंट्स से लेकर तैयार उत्पादों तक पूरी घरेलू वैल्यू चेन बना रहा है। भारत न केवल दुनिया के लिए एक बाजार बन रहा है, बल्कि एक भरोसेमंद मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर भी बन रहा है। दूसरी *सप्तधारा* यानी कृषि और फूड प्रोसेसिंग है, जिसमें हम खेती से ग्लोबल फूड पावर बनने की ओर बढ़े हैं; इस बदलाव में फूड प्रोसेसिंग और निर्यात अहम भूमिका निभा रहे हैं। कृषि क्षेत्र अब उत्पादकता, वैल्यू एडिशन, प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग और निर्यात के दम पर आगे बढ़ रहा है। भारत में कृषि निर्यात 2013-14 में 37.29 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2024-25 में 51.1 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है, जबकि कृषि निर्यात में प्रोसेस्ड फूड (संसाधित खाद्य पदार्थों) की हिस्सेदारी 13.7 प्रतिशत से बढ़कर 20.4 प्रतिशत हो गई है। भारतीय कृषि उत्पाद अब एशिया, मध्य पूर्व, अफ्रीका और अन्य क्षेत्रों के बाजारों तक पहुंच रहे हैं।

सतिया के बरभुइयां गांव में ज्योति प्रसाद अग्रवाल नाटक के नाटक रूपालिम का मंचन

विश्वनाथ (विभास)। सतिया में ज्योति प्रसाद अग्रवाल के नाटक *रूपालिम* का सतिया बरभुइयां गांव के अरुण रंगमंच में सिल्भर जुबली साल भर मनाए जाने के कार्यक्रम के तहत मंचन की गई नाटक का उद्घाटन नदुवार विधान सभा क्षेत्र के विधायक व सफल अनुभवी अभिनेता पद्म हजारिका ने किया। नाटक संचालक भवानी भुइयां ने उनकी नाटक से जुड़ी लंबी अनुभव से नाटक को स्टेज पर जीवंत कर दिया जो कबीले तारीफ था। दर्शकों को बिना किसी परेशानी के नाट्य माध्यम से पूरी कहानी को अच्छे से पेश करना, जबकि नाटक को एक एक्ट से दूसरे एक्ट में ले जाना डायरेक्टर की एक और बड़ी कामयाबी है, जिसे वहां मौजूद दर्शकों ने खूब सराहा था। नाटक के निर्देशक भवानी भुइयां ने किरदारों में इमोशंस

और नाटक की घटनाओं को बहुत अच्छे से डायरेक्ट किया है। स्टेज पर मुख्य किरदार में *रूपाली* के तौर पर उद्दीप्ता कस्तूरी भुइयां की प्रदर्शन बहुत ही जानदार और इमोशनल करने वाली थी। उन्होंने प्यार, गर्व और त्याग की भावनाओं को खूबसूरती से दिखाया। इसी तरह, *मायाब* के भूमिका में विद्यामन भुइयां *जुनाफा* के रोल में लोहित भुइयां और *मोनीमुगध* के मुश्किल किरदार के रोल में बिप्लव सैकिया ने शानदार प्रदर्शन किया। *रुक्मी राजा* के रोल में दिलीप भुइयां और *एटिवन* के रोल में पुवाली भुइयां ने नाटक की अहमियत को और बढ़ा दिया। नाटक में प्रशांत फुकन *रंगाधियन* के रोल में हैं और ऑफिसर्स-जोनमोनी भुइयां राजमोनी भुइयां, हिमांशु भुइयां और मृणाल गोस्वामी *रिमू* के रोल थे नाटक में अपूर्व हजारिका, उत्पल पटवारी, रोमन भुइयां अंजन सैकिया, जागरण भुइयां मणिमुग्धा की सेना में (जिज्ञासा प्रतिम भुइयां, प्रीतम भुइयां, ज्ञानम भुइयां), मणिमुग्धा की पत्नी (पायल सैकिया, समीक्षा भुइयां और रुक्मी राजा की पत्नी के रूप में (ज्योस्ना भुइयां, कृषांगी पटवारी), सीनरी व डांस ग्रुप (गंगोत्री भुइयां, प्रकृष्टा भुइयां, मयूराक्षी भुइयां, योगिता भुइयां जुमन सैकिया, मधुस्मृता बोरा, कृष्णली सैकिया) की भरपूर कोशिशों ने नाटक को एक नया रूप दिया अभिजित भुइयां की कोरियोग्राफी हर सीन में अच्छे से फिट बैठती दिखाई दी थी। नाटक की एक और खास बात रही अनिल भट्टाचार्य का म्यूजिक डायरेक्शन बहुत ही बढ़िया था। पर्दे के पीछे, प्रतुल बोरा और जुबीन सैकिया के कीबोर्ड, अंजन राजबंशी का तबला, ज्योति प्रकाश बोरा कि पैड, कृष्ण दास की बांसुरी और कंकणा देवी और रक्तिम बोरा की आवाजों ने दृश्यों को और अधिक भावुक और गतिशील बना दिया। प्रणब भुइयां, प्रशांत सैकिया, निपेन सैकिया, मुकुल भुइयां और मनोरंजन कटकी के स्टेज सेट ने पौराणिक वातावरण को खूबसूरती सजा दिया था ज्योतिष फुकन, सागर दुवरा, रंजीत हजारिका, प्रांजल सैकिया और रक्तिम हजारिका के मेकअप ने प्रत्येक चरित्र को सही आकार दिया। इसके अलावा, प्रियम बोरा द्वारा प्रकाश सजावट और दीप बोरा द्वारा ध्वनि नियंत्रण ने नाटक के पूरे माहौल को एक विशेष आयाम दिया था कुल मिलाकर, अभिनेताओं की एकाग्रता के कारण *रूपालिम* का मंचन बहुत सफल और मनोरंजक रहा। अरुण रंगमंच के सिल्भर जयंती वर्ष में इस सुंदर प्रयास के लिए पूरे नाटक समूह को सभी स्थानीय जनता ने बधाई और शुभकामनाएं दी है।

संपादकीय

मंदिर पर्यटन की प्राथमिकताएं

पिछले तीन साल में हिमाचल के प्रमुख 36 मंदिरों ने 419.88 करोड़ बटोर कर यह साबित कर दिया कि तीर्थाटन से हिमाचल बहुत कुछ कर सकता है। बेशक प्रतिवर्ष 150 करोड़ की मंदिर कमाई को हम अच्छी योजनाओं-परियोजनाओं से बड़ा सकते हैं, यदि धार्मिक पर्यटन को विस्तृत भूमिका में देखा जाए। एक अनुमान के अनुसार हिमाचल में यात्रा की 80 फीसदी वजह केवल तीर्थाटन है, लेकिन हमारा टूरिस्ट मैप इसकी गवाही नहीं देता। इसके लिए अहम है मंदिर व्यवस्था में सुधार तथा प्रशासनिक व वित्तीय ढांचे में सुधार। समस्त मंदिरों का रखरखाव, उनका योजना व बजट आकार तथा कॉडर की समानता या एक रूपता नहीं होगी, तो आय-व्यय के बीच केवल स्वार्थ सिद्धियां ही होंगी। आवश्यक यह है कि एक केंद्रीय ट्रस्ट तथा मंदिर व्यवस्था के लिए मंदिर प्रबंधन एवं विकास प्राधिकरण बने। उदाहरण के लिए तीन साल की मंदिर कमाई अगर 419.88 करोड़ है तो इसी के अनुरूप खर्च का हिसाब एकीकृत नहीं है। अधिकतर मंदिर ट्रस्ट आय-व्यय का सबसे बड़ा भाग या तो अनावश्यक प्रशासनिक खर्चों, कर्मचारी तनख्वाहों या अनुत्पादक खर्चों में होता है। कई तरह के शैक्षणिक संस्थान मंदिर ट्रस्ट चला रहे हैं, तो यह सही नहीं है। मंदिर की आय का एक हिस्सा मंदिर के विस्तार या आय बढ़ाने के लिए होना चाहिए। अगर मंदिर प्राधिकरण के तहत मंदिरों की आय-व्यय का सांचा तय हो तो न केवल पारदर्शिता आएगी, बल्कि योजनाओं-परियोजनाओं का उद्देश्य पर्यटन के साथ जुड़ जाएगा। इतना ही नहीं मंदिर आय को बढ़ाने के लिए कुछ साझे उद्योग शुरू किए जा सकते हैं। मसलन अगर दियोटसिद्ध के रोट व ज्वालामुखी के पेड़ों को तमाम मंदिरों के प्रसाद से जोड़ा जाए या धूप व गिफ्ट आइटमों का उत्पादन भी तय हो तो मंदिरों की सामूहिक आय बढ़ेगी। मंदिरों की आय से कोंकण रेलवे की तर्ज पर चिंतपूर्णी, दियोटसिद्ध, कांगड़ा, चामुंडा व अन्य मंदिर परिसर जुड़ सकते हैं। इतना ही नहीं भाषा-संस्कृति विभाग अगर मंदिर परिसरों को कला केंद्रों के रूप में विकसित करे, तो सैकड़ों कलाकारों को आजीविका के साधन उपलब्ध होंगे। हर मंदिर में आधुनिक सभागार के अलावा आर्ट म्यूजियम तथा ट्रेड सेंटर विकसित किए जा सकते हैं। मंदिर परिसर को धार्मिक नगर विकास की योजना से जोड़कर शहरी आर्थिकी विकसित की जा सकती है। मसलन बड़े मंदिरों के आठ-दस किलोमीटर क्षेत्र की धार्मिक शहर विकास योजना पर काम करना होगा, ताकि इन क्षेत्रों को मंदिर आय से जोड़कर नई आर्थिकी विकसित की जा सके। मंदिरों की क्षमता का विस्तार अगर विविध संभावनाओं के अनुरूप करें, तो हिमाचल पांच हजार करोड़ की आर्थिकी विकसित कर सकता है। मंदिरों के साथ अलग-अलग टूरिस्ट सर्किट तथा उत्सव व सांस्कृतिक समागमों का एक वार्षिक कैलेंडर जोड़ना होगा। इतना ही नहीं मंदिर पर्यटन के प्रारूप में धरोहर पर्यटन को भी जोड़ा जा सकता है। मंदिरों में श्रद्धालुओं के कई वर्ग आ रहे हैं अतः दर्शन व्यवस्था के अलावा आकर्षण बढ़ाने के लिए, सीमांत क्षेत्रों के पर्यटन को अहमियत देनी होगी। उदाहरण के लिए पांवटा साहिब व ऊना में सिख पर्यटन की अहमियत बढ़ाने के लिए संगठित प्रयास करने होंगे। वाराणसी पहुंचे हिमाचल के मुख्यमंत्री ने फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन को अपने टूअर पैकेज में हिमाचल के विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ने का आग्रह किया है। वाराणसी धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन का एक उत्तम उदाहरण है जहां साधारण से हाई एंड टूरिस्ट सुविधाओं के खाके पूर्ण हैं। अगर हमें वाराणसी की तरह प्रयास करने हैं, तो प्रमुख मंदिरों के प्रबंधन, विकास, अधोसंरचना और सुविधाओं में निखार लाना होगा। विडंबना यह है कि कुछ वर्ष पूर्व ज्वालामुखी में म्यूजिकल फाउंटेन स्थापित हुआ, लेकिन यह आज तक चला ही नहीं।

प्रतिवर्ष 150 करोड़ की मंदिर कमाई को हम अच्छी योजनाओं-परियोजनाओं से बड़ा सकते हैं, यदि धार्मिक पर्यटन को विस्तृत भूमिका में देखा जाए। एक अनुमान के अनुसार हिमाचल में यात्रा की 80 फीसदी वजह केवल तीर्थाटन है, लेकिन हमारा टूरिस्ट मैप इसकी गवाही नहीं देता। इसके लिए अहम है मंदिर व्यवस्था में सुधार तथा प्रशासनिक व वित्तीय ढांचे में सुधार। समस्त मंदिरों का रखरखाव, उनका योजना व बजट आकार तथा कॉडर की समानता या एक रूपता नहीं होगी, तो आय-व्यय के बीच केवल स्वार्थ सिद्धियां ही होंगी। आवश्यक यह है कि एक केंद्रीय ट्रस्ट तथा मंदिर व्यवस्था के लिए मंदिर प्रबंधन एवं विकास प्राधिकरण बने। उदाहरण के लिए तीन साल की मंदिर कमाई अगर 419.88 करोड़ है तो इसी के अनुरूप खर्च का हिसाब एकीकृत नहीं है। अधिकतर मंदिर ट्रस्ट आय-व्यय का सबसे बड़ा भाग या तो अनावश्यक प्रशासनिक खर्चों, कर्मचारी तनख्वाहों या अनुत्पादक खर्चों में होता है। कई तरह के शैक्षणिक संस्थान मंदिर ट्रस्ट चला रहे हैं, तो यह सही नहीं है। मंदिर की आय का एक हिस्सा मंदिर के विस्तार या आय बढ़ाने के लिए होना चाहिए। अगर मंदिर प्राधिकरण के तहत मंदिरों की आय-व्यय का सांचा तय हो तो न केवल पारदर्शिता आएगी, बल्कि योजनाओं-परियोजनाओं का उद्देश्य पर्यटन के साथ जुड़ जाएगा। इतना ही नहीं मंदिर आय को बढ़ाने के लिए कुछ साझे उद्योग शुरू किए जा सकते हैं। मसलन अगर दियोटसिद्ध के रोट व ज्वालामुखी के पेड़ों को तमाम मंदिरों के प्रसाद से जोड़ा जाए या धूप व गिफ्ट आइटमों का उत्पादन भी तय हो तो मंदिरों की सामूहिक आय बढ़ेगी। मंदिरों की आय से कोंकण रेलवे की तर्ज पर चिंतपूर्णी, दियोटसिद्ध, कांगड़ा, चामुंडा व अन्य मंदिर परिसर जुड़ सकते हैं।

एक शिक्षक कार्यरत है और इन स्कूलों में करीब 33.77 लाख विद्यार्थी पढ़ते हैं

विकसित भारत की राह में जर्जर शिक्षा व्यवस्था सबसे बड़ा सवाल

एक शिक्षक, टूटती दीवारें और घटते सरकारी स्कूल-क्या शिक्षा के बिना 2047 का सपना पूरा होगा? दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में देश की प्रगति, डिजिटल क्रांति, अंतरिक्ष उपलब्धियां, आधारभूत ढांचे का विस्तार और वैश्विक मंच पर बढ़ता प्रभाव निश्चित रूप से गौरव का विषय है। लेकिन इसी चमकदार तस्वीर के पीछे यदि हम सरकारी स्कूलों की ओर देखें तो एक दूसरा भारत दिखाई देता है-ऐसा भारत जहां हजारों बच्चे आज भी पर्याप्त शिक्षकों, सुरक्षित भवन, स्वच्छ पेयजल, शौचालय, बिजली और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सवाल यह है कि जिस शिक्षा-व्यवस्था पर विकसित भारत की नींव रखी जानी है, उसकी बुनियाद ही कमजोर होगी तो 2047 का भारत कितना मजबूत होगा? सरकारी आंकड़े इस चिंता को और गंभीर बनाते हैं

आज वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है। एक शिक्षक, टूटती दीवारें और घटते सरकारी स्कूल-क्या शिक्षा के बिना 2047 का सपना पूरा होगा? दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में देश की प्रगति, डिजिटल क्रांति, अंतरिक्ष उपलब्धियां, आधारभूत ढांचे का विस्तार और वैश्विक मंच पर बढ़ता प्रभाव निश्चित रूप से गौरव का विषय है। लेकिन इसी चमकदार तस्वीर के पीछे यदि हम सरकारी स्कूलों की ओर देखें तो एक दूसरा भारत दिखाई देता है-ऐसा भारत जहां हजारों बच्चे आज भी पर्याप्त शिक्षकों, सुरक्षित भवन, स्वच्छ पेयजल, शौचालय, बिजली और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सवाल यह है कि जिस शिक्षा-व्यवस्था पर विकसित भारत की नींव रखी जानी है, उसकी बुनियाद ही कमजोर होगी तो 2047 का भारत कितना मजबूत होगा? सरकारी आंकड़े इस चिंता को और गंभीर बनाते हैं। यूडीआईएसई प्लस 2024-25 के अनुसार देश में 1,04,125 स्कूल ऐसे हैं जहां केवल एक शिक्षक कार्यरत है और इन स्कूलों में करीब 33.77 लाख विद्यार्थी पढ़ते हैं। यानी एक शिक्षक को कई कक्षाओं, अनेक विषयों और प्रशासनिक जिम्मेदारियों के बीच बच्चों की शिक्षा संभालनी पड़ रही है। यह केवल संख्या नहीं, बल्कि उन लाखों बच्चों के भविष्य की कहानी है, जिनके लिए सरकारी स्कूल शिक्षा का सबसे सुलभ और कई बार एकमात्र माध्यम हैं। विडंबना यह है कि उसी देश में हम विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयों, आईआईटी, आईआईएम, मेडिकल संस्थानों और अत्याधुनिक शिक्षण परिसरों की चर्चा करते हैं, लेकिन गांव के उस बच्चे की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं देते जो टूटी छत के नीचे बैठकर भविष्य के सपने देख रहा है। कहीं शिक्षक एक है और कक्षाएं पांच। कहीं विद्यालय भवन जर्जर है, कहीं पानी नहीं, कहीं शौचालय नहीं, कहीं बिजली और पंखे नहीं। हाल के महीनों में उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों में विद्यार्थियों को अधिक शिक्षक, बेहतर भोजन, पेयजल, पंखे और बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर सड़कों पर उतरना पड़ा। फतेहपुर में तो लगभग एक हजार विद्यार्थियों ने जर्जर कक्षाओं, रिसती छतों और सुरक्षित पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए प्रदर्शन किया।

यह स्थिति केवल किसी एक राज्य अथवा किसी एक सरकार की विफलता नहीं है। यह वर्षों से चली आ रही उस प्रशासनिक सोच का परिणाम है जिसमें शिक्षा को प्राथमिकता तो भाषणों में दी गई, लेकिन उसकी गुणवत्ता और जवाबदेही को शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में स्थान नहीं मिला। शिक्षा विभागों में अधिकारियों और कर्मचारियों की बड़ी व्यवस्था है, बजट है, योजनाएं हैं, समितियां हैं, निरीक्षण तंत्र है-फिर भी एक शिक्षक वाले एक लाख से अधिक स्कूल कैसे बने रहे? यह सवाल केवल सरकार से नहीं, पूरे प्रशासनिक तंत्र से पूछा जाना चाहिए। निश्चित रूप से तस्वीर पूरी तरह निराशाजनक भी नहीं है। यूडीआईएसई प्लस के अनुसार 2024-25 में देश में कुल 14.71 लाख स्कूल, करीब 24.69 करोड़ विद्यार्थी और एक करोड़ से अधिक शिक्षक हैं। सरकारी स्कूलों की संख्या 10.13 लाख है, जबकि निजी मान्यता प्राप्त स्कूल करीब 3.40 लाख हैं। सरकार के आंकड़े यह भी बताते हैं कि एकल-शिक्षक स्कूलों की संख्या 2023-24 के 1,10,971 से घटकर 2024-25 में 1,04,125 हुई है और कंप्यूटर सुविधा वाले स्कूलों का अनुपात 57.2 प्रतिशत से बढ़कर 64.7 प्रतिशत हुआ है। इन सुधारों को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन इन्हें अंतिम उपलब्धि मान लेना आत्मसंतोष होगा। क्योंकि शिक्षा की असली कसौटी भवन, कंप्यूटर या आंकड़े नहीं, बच्चे की सीखने की क्षमता और उसके भविष्य का निर्माण है। नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट एक और महत्वपूर्ण तस्वीर सामने रखती है। 2014-15 में देश में 11.07 लाख सरकारी स्कूल थे, जो 2024-25 में घटकर 10.13 लाख रह गए। इसके विपरीत निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों की संख्या 2.88 लाख से बढ़कर 3.39 लाख हो गई। यह परिवर्तन केवल स्कूलों की संख्या का उतार-चढ़ाव नहीं है, यह अभिभावकों की बदलती पसंद और सरकारी शिक्षा में घटते विश्वास का संकेत भी है। सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि जब सरकार के पास भवन है, जमीन है, प्रशिक्षित शिक्षक हैं, वेतन देने की क्षमता है और विशाल प्रशासनिक तंत्र है, तब सरकारी स्कूल निजी स्कूलों से पीछे क्यों हैं? निजी स्कूलों की आलोचना करना आसान है, लेकिन यह भी देखना होगा कि अभिभावक अपनी सीमित आय में फीस देकर भी निजी स्कूल क्यों चुन रहे हैं। इसका उत्तर सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता, अनुशासन, नियमितता, अंग्रेजी एवं तकनीकी शिक्षा, अभिभावक संवाद और सीखने के वातावरण में छिपा है। एसीईआर के आंकड़े भी इस अंतर को रेखांकित करते हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में कक्षा 3 के बच्चों में कक्षा 2 स्तर का पाठ पढ़ पाने वालों का अनुपात सरकारी स्कूलों में 23.4 प्रतिशत था, जबकि निजी स्कूलों में 35.5 प्रतिशत। कक्षा 5 में भी सरकारी स्कूलों का आंकड़ा 44.8 प्रतिशत और निजी स्कूलों का 59.3 प्रतिशत रहा। यानी समस्या केवल स्कूल भवन की नहीं, सीखने के परिणामों की भी है। इसी के समानांतर उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तस्वीर भी चिंता पैदा करती है। पेपर लीक, परीक्षा में अनियमितता, भर्ती में देरी और युवाओं के आंदोलनों की खबरें लगातार सामने आती रही हैं। 2026 में परीक्षा संबंधी विवादों ने विद्यार्थियों और अभ्यर्थियों में असंतोष को व्यापक बनाया। इसका अर्थ यह है कि समस्या शिक्षा-व्यवस्था के निचले स्तर से लेकर उच्च स्तर तक फैली हुई है। प्राथमिक स्कूल में कमजोर नींव, माध्यमिक शिक्षा में गुणवत्ता का संकट और उच्च शिक्षा तथा प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता का सवाल-इन सबको अलग-अलग देखकर समाधान नहीं निकलेगा। सरकारी स्कूल वास्तव में भारत की सामाजिक समानता का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम हैं। इन स्कूलों में ग्रामीण परिवारों, श्रमिकों, गरीबों, वंचित वर्गों और निम्न आय वाले परिवारों के बच्चे बड़ी संख्या में पढ़ते हैं। यदि इन विद्यालयों की गुणवत्ता गिरती है तो सबसे अधिक नुकसान उसी वर्ग को होता है जिसके पास महंगे निजी स्कूलों का विकल्प नहीं है। इसलिए सरकारी स्कूलों की बदहाली केवल शिक्षा का संकट नहीं, सामाजिक न्याय का संकट भी है। यहां एक कठोर लेकिन सार्थक सुझाव पर विचार होना चाहिए-क्या जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के बच्चों के लिए कुछ निश्चित परिस्थितियों में सरकारी स्कूलों में शिक्षा को प्रोत्साहित अथवा अनिवार्य करने जैसी व्यवस्था बनाई जा सकती है? जब नीति बनाने वाले परिवार स्वयं उसी व्यवस्था का अनुभव करेंगे, तब शायद स्कूल की टूटी खिड़की, बंद शौचालय, शिक्षक की कमी और खराब मिड-डे-मील केवल फाइल की टिप्पणी नहीं रहेंगे, बल्कि व्यक्तिगत अनुभव बन जाएंगे। शिक्षा को केवल मध्याह्न भोजन, छात्रवृत्ति, यूनिफॉर्म या मुफ्त पुस्तकों की योजनाओं तक सीमित नहीं किया जा सकता। ये आवश्यक हैं, लेकिन शिक्षा का उद्देश्य केवल बच्चे को स्कूल तक पहुंचाना नहीं, उसे ज्ञान, विवेक, कौशल, संस्कार और आत्मविश्वास से संपन्न नागरिक बनाना है। जिस बच्चे को आज गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिलेगी, उससे कल विकसित भारत के निर्माण में प्रभावी योगदान की अपेक्षा कैसे की जा सकती है।

देश | दुनीया से

सही नहीं है यूपीआई पर कोई भी शुल्क

लोकसभा में 6 अगस्त 2026 को पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 में संशोधन बिल पारित किया है, जिसके अनुसार अब यूपीआई एवं अन्य अधिसूचित इलैक्ट्रानिक भुगतानों पर बैंकों और अन्य पेमेंट प्रदात्ताओं पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) लगाए जाने पर वैधानिक रोक समाप्त हो जाएगी। हालांकि सरकार ने यह कहा है कि उपभोक्ताओं पर इसका असर नहीं होगा और यूपीआई भुगतान देना और प्राप्त करना दोनों ही निशुल्क रहेंगे। जैसा कि बताया जा रहा है कि यूपीआई के माध्यम से 2000 रुपए तक के भुगतान तो निःशुल्क रहेंगे ही, लेकिन 2000 रुपए से ऊपर के भुगतानों पर बैंकों और अन्य भुगतान प्रदात्ताओं पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट लगाया जा सकेगा, जो भुगतान प्राप्तकर्ता, यानी विक्रेता से वसूला जाएगा। हालांकि कितना शुल्क लगाया जाएगा, यह निश्चित नहीं है, लेकिन जिस प्रकार के प्रस्तावों पर चर्चा हो रही है, उनके अनुसार ऊंचे मूल्य के लेन-देन पर एमडीआर 0.25 से 0.5 प्रतिशत के बीच हो सकता है। हालांकि सरकार ने यह कहा है कि छोटे विक्रेताओं और उपभोक्ताओं के लिए यूपीआई की सुविधा निशुल्क रहेगी।

क्या है सरकार का तर्क : सरकार द्वारा यूपीआई भुगतान के नियमों में इस बदलाव का जो कारण बताया जा रहा है, वो यह है कि अभी तक यूपीआई निशुल्क है, लेकिन इसकी लागत को किसी न किसी को तो वहन करना पड़ेगा। यूपीआई पर फीस लगाने के समर्थकों का कहना है कि बैंक और नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन आफ इंडिया (एनपीसीआई) और पेमेंट कंपनियां सर्वरों पर ही नहीं, साइबर सुरक्षा और विस्तार पर भी खर्च करती हैं, जिसे किसी को तो वहन करना ही पड़ेगा। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा कहते हैं

कि यूपीआई को सुरक्षित एवं भरोसेमंद बनाए रखने के लिए किसी को तो भुगतान करना ही पड़ेगा।

पब्लिक गुड है यूपीआई : अर्थशास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार कुछ ऐसी सेवाएं होती हैं जिनका इस्तेमाल गैर प्रतिद्वंद्वी यानी 'नॉन-राइवल' होता है, यानी किसी एक के इस्तेमाल से दूसरों के इस्तेमाल पर कोई बाधा नहीं आती, और ये बिना किसी रोक-टोक के सभी के लिए उपलब्ध होती हैं, और किसी को इसके इस्तेमाल से रोका नहीं जा सकता। ऐसी सेवा को 'प्योर पब्लिक गुड' यानी विशुद्ध सार्वजनिक वस्तु कहा जाता है। कभी-कभी, कुछ सेवाएं गैर प्रतिद्वंद्वी तो होती हैं, लेकिन उनमें लोगों को बाहर रखना मुमकिन होता है। ऐसी चीजों को पब्लिक गुड तो कहा जा सकता है, लेकिन ये 'प्योर पब्लिक गुड' नहीं होतीं। प्योर पब्लिक गुड के उदाहरण हैं- कानून-व्यवस्था, सुरक्षा, पार्क, स्ट्रीटलाइट और सडकें। यूपीआई पब्लिक गुड की दूसरी श्रेणी में आता है, जो प्रकृति से गैर प्रतिद्वंद्वी तो है, लेकिन कीमत वसूलने पर इससे अन्यों को वंचित किया जा सकता है (यानी कुछ लोगों को इससे बाहर रखा जा सकता है)। आम तौर पर, सार्वजनिक सेवाएं ऐसी होती हैं जो समाज के लिए फायदेमंद तो होती हैं, लेकिन उनमें निजी क्षेत्र का निवेश नहीं आता, भले ही सैद्धांतिक रूप से उन तक पहुंच को सीमित किया जा सकता हो। अगर सरकार ने यूपीआई को बनाया न किया होता, तो कोई भी निजी क्षेत्र की कंपनी इतना शानदार प्रोडक्ट नहीं बना पाती। सरकार पब्लिक गुड में इन्वेस्टमेंट करती है क्योंकि वे लोगों के लिए फायदेमंद होते हैं। यूपीआई भी ऐसा ही एक पब्लिक गुड है, जो प्रकृति में तो गैर प्रतिद्वंद्वी है, लेकिन हां, इसमें वंचन मुमकिन है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हमें इसके लिए फीस लेना शुरू कर देना चाहिए? ऐसे पब्लिक गुड पर फीस लेने का फैसला 'हानि-लाभ विश्लेषण' के आधार पर किया जाना चाहिए। आम तौर पर, हमें यह समझना चाहिए कि अगर लागत की तुलना में फायदे बहुत ज्यादा हैं और लागत बहुत ज्यादा नहीं है, तो इसे मुफ्त रखना ही सबसे अच्छा है। लंबे समय से भारत में लॉजिस्टिक लागत बहुत ऊंची रहती रही है, जिसके कारण हमारे उत्पाद दुनिया के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते थे। लेकिन पिछले एक दशक से ज्यादा समय में लॉजिस्टिक लागत में कम से कम एक प्रतिशत की महत्वपूर्ण कमी दर्ज की गई है। एनसीएएआर और डीपीआईआईटी के आंकड़ों के अनुसार यह लॉजिस्टिक लागत 2014 में जीडीपी का लगभग 9 प्रतिशत होती थी, जो अब घटकर 8 प्रतिशत तक पहुंच गई है। लॉजिस्टिक लागत के घटने में यूपीआई का निशुल्क होना एक बड़ा कारण है। समझना होगा कि आज भारत में दुनिया के 49 प्रतिशत ऑनलाइन लेन-देन होते हैं, और जो निशुल्क हैं। यदि यूपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यह भी पब्लिक गुड की श्रेणी में आता है। जिस प्रकार से सडकें, पार्क, स्ट्रीट लाइट, कानून व्यवस्था आदि जीवन को सुगम बनाती है, तो यूपीआई व्यवसाय को सुगम बनाती है। सरकार का दायित्व है कि व्यवसाय की सुगमता (ईज ऑफ डूईंग बिजनेस) सुनिश्चित करे। इसके लिए सरकार विभिन्न प्रकार के प्रयास भी कर रही है। यूपीआई इसमें काफी मदद कर रहा है। देश में सडकों के जाल, रेल सुविधा में बेहतरी और सरकार की नई योजनाएं, जैसे कॉरिडोर इत्यादि ने न केवल व्यवसाय को सुगम किया है, बल्कि उससे लॉजिस्टिक लागत में भी भारी कमी आ रही है।

कहीं सरकार अमरीका के दबाव में तो यह नहीं कर रही? : गौरतलब है कि हाल ही में संयुक्त राज्य अमरीका व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में भारत में यूपीआई लेन-देन के निःशुल्क होने पर आपत्ति दर्ज की गई थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि शून्य एमडीआर नीति, रूपे कार्ड का प्रमोशन, रूपे क्रेडिट कार्ड को यूपीआई के साथ लिंक करने, डाटा स्थानीयकरण नियम और एनपीसीआई द्वारा यूपीआई एप्लिकेशन कंपनियों पर 30 प्रतिशत बाजार भागीदारी की शर्त आदि अमरीकी कंपनियों के व्यवसाय के लिए बाधाएं डाल रहे हैं।

आप का | नजरीया

बीमार हैं स्कूल

देश में एक लाख स्कूल एक ही शिक्षक के भरोसे चल रहे हों, मूलभूत शैक्षिक सुविधाओं का अभाव हो, वहां पढ़ाई का स्तर क्या होगा, अंदाज लगाना कठिन नहीं है। कुछ स्कूल जर्जर इमारतों में चल रहे हैं, कुछ पेड़ तले व बरामदों में- तो सवाल स्वाभाविक है कि सुधार क्यों नहीं होता? आखिर इन स्कूलों का सुधार हमारे नीति-नियंताओं की प्राथमिकताओं में क्यों नहीं होता? जिस शिक्षा विभाग में अधिकारियों व कर्मचारियों की पूरी फौज तैनात है, उसकी जवाबदेही तय क्यों नहीं होती? अब भले ही सरकारी स्कूलों को सीजेपी ने अपना मुद्दा बना लिया हो, लेकिन इससे पहले ही देश के कई भागों में छात्र स्कूलों में सुधार की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। विडंबना यह है कि इन स्कूलों पर ग्रामीण, समाज के वंचित वर्गों, श्रमिकों व गरीब बच्चों की निर्भरता अधिक होती है, फलत: उनकी आवाज भी अनसुनी कर दी जाती है। यदि नेताओं और अधिकारियों के बच्चों के लिये सरकारी स्कूलों में भर्ती अनिवार्य कर दी जाती तो शायद इन स्कूलों के दिन फिर जाते। सरकारी स्कूलों का सच किसी से छिपा नहीं है। नीति आयोग के हालिया आंकड़े इस सच को अनावृत करते हैं। आयोग के आंकड़ों के मुताबिक पिछले एक दशक में पूरे देश में 94 हजार सरकारी स्कूल बंद हुए हैं। साथ ही इसी अवधि में सरकारी अनुदान प्राप्त स्कूल भी 83 हजार से घटकर 79 हजार रह गये हैं। स्कूलों में छात्रों के दाखिले में कमी का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है। लेकिन वहीं दूसरी ओर मुनाफा कमा रहे निजी स्कूलों का कुनबा लगातार बढ़ ही रहा है। उनकी संख्या अब 2 .9 लाख से बढ़कर 3 .4 लाख के करीब हो गई है।

देश के सरकारी स्कूलों की बदहाली किसी से छिपी नहीं है। जिस देश में एक लाख स्कूल एक ही शिक्षक के भरोसे चल रहे हों, मूलभूत शैक्षिक सुविधाओं का अभाव हो, वहां पढ़ाई का स्तर क्या होगा, अंदाज लगाना कठिन नहीं है। कुछ स्कूल जर्जर इमारतों में चल रहे हैं, कुछ पेड़ तले व बरामदों में- तो सवाल स्वाभाविक है कि सुधार क्यों नहीं होता? आखिर इन स्कूलों का सुधार हमारे नीति-नियंताओं की प्राथमिकताओं में क्यों नहीं होता? जिस शिक्षा विभाग में अधिकारियों व कर्मचारियों की पूरी फौज तैनात है, उसकी जवाबदेही तय क्यों नहीं होती? अब भले ही सरकारी स्कूलों को सीजेपी ने अपना मुद्दा बना लिया हो, लेकिन इससे पहले ही देश के कई भागों में छात्र स्कूलों में सुधार की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। विडंबना यह है कि इन स्कूलों पर ग्रामीण, समाज के वंचित वर्गों, श्रमिकों व गरीब बच्चों की निर्भरता अधिक होती है, फलतः उनकी आवाज भी अनसुनी कर दी जाती है। यदि नेताओं और अधिकारियों के बच्चों के लिये सरकारी स्कूलों में भर्ती अनिवार्य कर दी जाती तो शायद इन स्कूलों के दिन फिर जाते। सरकारी स्कूलों का सच किसी से छिपा नहीं है। नीति आयोग के हालिया आंकड़े इस सच को अनावृत करते हैं। आयोग के आंकड़ों के मुताबिक पिछले एक दशक में पूरे देश में 94 हजार सरकारी स्कूल बंद हुए हैं। साथ ही इसी अवधि में सरकारी अनुदान प्राप्त स्कूल भी 83 हजार से घटकर 79 हजार रह गये हैं। स्कूलों में छात्रों के दाखिले में कमी का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है। लेकिन वहीं दूसरी ओर मुनाफा कमा रहे निजी स्कूलों का कुनबा लगातार बढ़ ही रहा है। उनकी संख्या अब 2.9 लाख से बढ़कर 3.4 लाख के करीब हो गई है। यह एक हकीकत है कि सरकारी स्कूलों की स्थिति को लेकर राजनीतिक दलों की जो फिक्र सामने आ रही है, उसके निहितार्थ समझना कठिन नहीं है। इन दलों की सरकारों के दौरान भी इन स्कूलों की दिशा-दशा में कोई बड़ा बदलाव नजर नहीं आया। चिंता इस बात को लेकर है कि इस मुद्दे पर जो राजनीति हो रही है, कहीं उसके चलते सुधार के विमर्श पर आंच न आए। सही मायने में सरकारी स्कूलों का कायाकल्प होना चाहिए। इसमें शासन, प्रशासन, पक्ष-विपक्ष और नागरिकों की भी अहम भूमिका होनी चाहिए। नीति-नियंताओं को सोचना चाहिए कि अभिभावकों से मोटी फीस लेने वाले निजी स्कूल क्यों फल-फूल रहे हैं? सरकारी स्कूलों के पास भवन हैं, पर्याप्त जगह है, सम्मानजनक पगार वाले शिक्षक हैं और सरकारी तंत्र का समर्थन है, तो ये स्कूल पनप क्यों नहीं रहे हैं? क्यों सरकारी स्कूलों में पानी, बिजली, बेंच, टेबल व शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं? बल्कि सुधारों के बजाय शिक्षकों की नियुक्ति में राजनेताओं की धांधली की खबरें अकसर मीडिया में तैरती रहती हैं। विडंबना देखिये कि पढ़ाई-लिखाई के लिये अनुकूल वातावरण की मांग को लेकर राजस्थान व उत्तर प्रदेश के कई शहरों में विद्यार्थी सड़कों पर उतरे हैं। इन बच्चों को अपने भविष्य की फिक्र थी और ये स्कूलों में गुणवत्ता का शैक्षिक वातावरण मांग रहे थे। निश्चित रूप से हमारे नीति-नियंताओं ने सरकारी स्कूलों का उद्धार करने के लिये कभी कोई बड़ा अभियान नहीं चलाया। अब जब मुद्दा तूल पकड़ रहा है तो तमाम घोषणाएं की जा रही हैं। सही मायने में प्राथमिक शिक्षा किसी भी देश के भविष्य की बुनियाद होती है। जब इन स्कूलों में बीमार भविष्य वाले नागरिक तैयार करेंगे तो देश का भला कैसे होगा? दरअसल, सरकारी स्कूल हमारे समाज में व्याप्त आर्थिक विषमता का पर्याय हैं। जो लोग अपने बच्चों को महंगे सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते हैं, वे ही अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजने के लिये मजबूर हैं।

कुछ | अलग

मनुष्य का आविष्कार

प्रकृति जीव उत्पन्न करती है, सृष्टि का संचार करती है, परन्तु मनुष्य पहले स्वयं को, फिर संसार को सुधारने निकल पड़ता है।' दुनिया में पहली दरार अपना स्थान बना चुकी थी। कॉकरोचों ने उसके भीतर अपना छोटा-सा गणराज्य बसाना आरंभ कर दिया था। पृथ्वी पर एक अद्भुत शांति थी। नदियां बिना किसी परियोजना-रिपोर्ट के सरल भाव से बह रही थीं। पर्वत बिना उद्घाटन-समारोह के सिर उठाए खड़े थे। जंगलों को यह चिंता नहीं थी कि उनका सकल घरेलू उत्पाद कितना है। बादलों ने अभी तक मौसम विभाग की स्थापना नहीं की थी। सूरज प्रतिदिन बिना किसी प्रेस विज्ञप्ति के उगता था। चंद्रमा हर रोज बिना किसी सांस्कृतिक समारोह के घटता-बढ़ता रहता था। जीवन इतना स्वाभाविक था कि किसी जीव को यह सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी कि वह जीवित है। सभी जीव सहज भाव से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे।

दृष्टि | कोण

लापरवाही और भ्रष्टाचार पर अंकुश जरूरी

आज सबसे बड़ा सवाल है कि जलभराव के बाद राहत क्यों, संकट आने से पहले तैयारी क्यों नहीं? अधिकांश शहरी जलभराव अचानक पैदा होने वाली समस्या नहीं है। जिन स्थानों पर हर वर्ष पानी भरता है, उनकी पहचान प्रशासन और नगर निकायों को पहले से होती है। यह भी पता होता है कि किस सड़क पर पानी जमा होता है, किस नाले की क्षमता कम है और कहां प्राकृतिक जल निकासी बाधित है। फिर भी हमारा जोर अक्सर पानी भरने के बाद राहत देने पर रहता है, पानी भरने से पहले समस्या रोकने पर नहीं। इस वर्ष असम में बाढ़ से सैकड़ों लोगों की मौत हुई। यह केवल एक आंकड़ा नहीं, बल्कि सैकड़ों परिवारों का दुख है। असम में ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के कारण हर वर्ष बाढ़ का खतरा रहता है। केवल भारी बारिश को जिम्मेदार बताकर हम अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। बाढ़ क्षेत्र पर बढ़ता दबाव, प्राकृतिक जल क्षेत्रों का नुकसान, अनियोजित निर्माण और कमजोर पूर्व चेतावनी व्यवस्था आपदा को अधिक विनाशकारी बना सकती है। हरियाणा की आर्थिक शक्ति गुरुग्राम और देश के प्रमुख कारोबारी केंद्रों में शामिल इस शहर में लाखों लोग काम करते हैं। लेकिन मानसून आते ही कई बार इसकी तस्वीर बदल जाती है। भारी बारिश के बाद सड़कें पानी में डूबती हैं, वाहन घंटों फंसते हैं, सार्वजनिक परिवहन प्रभावित होता है और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी रुक जाती है। हर वर्ष नालों की सफाई, पंपों की व्यवस्था और जल निकासी के इंतजाम किए जाते हैं। फिर अगले मानसून में वही स्थान दोबारा पानी में दिखाई देते हैं। पानी भरने के बाद

पंप लगाना जरूरी है, लेकिन पंप स्थायी समाधान नहीं है। जलभराव के बाद यातायात नियंत्रित करना जरूरी है, लेकिन उससे बेहतर है कि यातायात प्रभावित ही न हो। पानी निकालना जरूरी है, लेकिन उससे अधिक जरूरी है कि पानी जमा ही न हो। गुरुग्राम की समस्या को केवल अत्यधिक बारिश कहकर समझना अधूरा होगा। तेजी से बढ़ते निर्माण ने जमीन की पानी सोखने की क्षमता कम कर दी है। जहां कभी खाली जमीन, तालाब, हरित क्षेत्र और प्राकृतिक जल मार्ग थे, वहां सड़कें और इमारतें खड़ी हो गई हैं। बारिश का पानी जमीन में जाने के बजाय तेजी से बहता है और पर्याप्त निकासी न मिलने पर सड़कें जलाशय बन जाती हैं। इस समस्या से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर और देश के अनेक शहर हर वर्ष सामना करते हैं। हमने शहरों का विस्तार तो कर दिया, लेकिन पानी के लिए जगह नहीं छोड़ी। तालाब, झील और प्राकृतिक जल क्षेत्र खाली जमीन नहीं, बल्कि शहरों की प्राकृतिक बाढ़ नियंत्रण व्यवस्था हैं। सवाल है कि क्या हर बार की बाढ़ व जलभराव समस्या हमारी व्यवस्था की लापरवाही या भ्रष्टाचार है? जहां हर वर्ष नालों की सफाई के नाम पर पैसा खर्च होता है, लेकिन अगली बारिश में वही नाले फिर जाम मिलते हैं। जल निकासी की परियोजनाएं बार-बार बनती हैं, लेकिन जलभराव खत्म नहीं होता, वहां काम की गुणवत्ता और खर्च की निष्पक्ष जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर किसी अधिकारी, ठेकेदार या एजेंसी की लापरवाही से सार्वजनिक धन खर्च होने के बावजूद समस्या बनी रहती है, तो जवाबदेही किसकी होगी? भ्रष्टाचार और लापरवाही पर सख्त कार्रवाई जरूरी है। निर्माण कार्यों में पारदर्शिता, स्वतंत्र गुणवत्ता जांच और प्राकृतिक जल मार्गों पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। प्रत्येक बड़े शहर का वैज्ञानिक बाढ़ जोखिम मानचित्र तैयार होना चाहिए, ताकि यह स्पष्ट रहे कि अत्यधिक बारिश में पानी किस दिशा में जाएगा। मानसून से पहले नालों की सफाई भी औपचारिकता नहीं होनी चाहिए।

यूपी को चार क्रिकेट टीमें देने की मांग, पूर्व मंत्री एवं रणजी क्रिकेटर मोहसिन रजा ने बीसीसीआई के सामने उठाया मुद्दा

लखनऊ, (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यमंत्री एवं पूर्व रणजी क्रिकेटर मोहसिन रजा ने उत्तर प्रदेश की विशाल आबादी और यहां मौजूद क्रिकेट प्रतिभाओं को देखते हुए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के सामने एक बार फिर प्रदेश को कम से कम चार क्रिकेट टीमों का प्रतिनिधित्व देने की मांग रखी है। उन्होंने मंगलवार को जारी अपने बयान में कहा कि उत्तर प्रदेश में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन सीमित अवसरों के कारण बड़ी संख्या में खिलाड़ी उच्च स्तर तक पहुंचने से वंचित रह जाते हैं। मोहसिन रजा ने कहा कि करीब 25 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में क्रिकेट खेलने वाले प्रतिभाशाली युवाओं की संख्या भी बहुत बड़ी है। यदि इस प्रदेश को एक अलग देश माना जाए तो आबादी के लिहाज से यह दुनिया के सबसे बड़े देशों में शामिल होगा। ऐसे में इतने बड़े प्रदेश के लिए केवल एक प्रमुख टीम का होना प्रतिभाओं के साथ न्याय नहीं करता। उन्होंने मांग की कि रणजी ट्राफी के साथ-साथ अंडर-16, अंडर-19 और अंडर-23 जैसे आयु वर्गों में भी उत्तर प्रदेश की कम से कम चार टीमें बनाई जानी चाहिए। इससे प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में छिपी प्रतिभाओं को आगे बढ़ने के अधिक अवसर मिलेंगे। पूर्व रणजी क्रिकेटर ने कहा कि प्रदेश के ग्रामीण और छोटे शहरों में बड़ी संख्या में युवा खिलाड़ी दिन-रात मेहनत कर रहे हैं। इनमें प्रतिभा और क्षमता होने के बावजूद सीमित अवसरों के कारण वे राज्य, आईपीएल और भारतीय टीम के उच्च स्तर तक नहीं पहुंच पाते। टीमों की संख्या बढ़ने से ऐसे खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा साबित करने का मंच मिलेगा। मोहसिन रजा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अधिक टीमों का गठन होने से प्रतिभाओं का दूसरे राज्यों या संस्थानों की ओर पलायन भी रोका जा सकेगा। प्रदेश के खिलाड़ी अपने ही राज्य से आगे बढ़कर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना सकेंगे। उन्होंने बीसीसीआई से अपील की कि उत्तर प्रदेश की विशाल भौगोलिक स्थिति, बड़ी आबादी और यहां उपलब्ध प्रतिभाओं को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के क्रिकेट ढांचे में विस्तार का निर्णय लिया जाए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को अधिक टीमों का प्रतिनिधित्व मिलने से न केवल क्रिकेट प्रतिभाओं को अवसर मिलेगा, बल्कि हजारों युवा खिलाड़ियों के भविष्य को नई दिशा भी मिलेगी।

अगले छह माह में यूपी के एक लाख युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र सौंपेंगे: योगी आदित्यनाथ

-मुख्यमंत्री ने साढ़े तीन हजार युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र, साल 2017 से पहले की सरकारों पर उठाए सवाल

लखनऊ, (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान तीन हजार 572 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस मौके पर उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि पिछले साढ़े नौ सालों में उनकी सरकार प्रदेश के नौ लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी हैं। अगले छह माह में प्रदेश के एक लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। योगी ने कहा कि हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जब हम योग्यतम अभ्यर्थियों का चयन बिना भेदभाव के करते हैं, तो उसका लाभ पूरे प्रदेश को मिलता है। उनकी प्रतिभा और उनकी ऊर्जा का लाभ पूरा प्रदेश लेता हुआ दिखाई देता है और यही पिछले 9-9.5 वर्ष के अंदर डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उपलब्धियों में से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भी है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने नौ लाख 30 हजार से अधिक उत्तर प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाने में सफलता प्राप्त की है और एक भी नियुक्ति पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता। हमने पहले दिन से तय कर रखा है कि जो 2017 के पहले की परिपाटी थी, वह अब नहीं चलेगी। नियुक्ति का विज्ञापन निकलता था, चाचा-भतीजे की जोड़ी और महाभारत का पूरा खानदान फिर वसूली के लिए प्रदेश भर में निकल पड़ता था। नौजवान भटकता रहता था, परिणाम नहीं आता था और अंततः न्यायालय को कोर्ट में स्टे लगाना पड़ता था। हमारे युवाओं का समय बर्बाद होता था। लोग मानते थे कि ये युवा किसी लायक नहीं क्योंकि ये नौकरी नहीं प्राप्त कर रहे। गलती युवा की नहीं होती थी, गलती उन आयोगों और बोर्डों में बैठे हुए और उस समय की सरकारों के भ्रष्ट तंत्र की थी। हमने पहले दिन कहा था कि अगर ये सरकार अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य कर रही है तो हम नकल माफिया की भी और विभिन्न संस्थानों में बैठे हुए माफिया की कमर को भी तोड़ेंगे और उसके आकाओं को भी जमीन-आसमान दिखाने का काम करेंगे। आपने देखा होगा इस दौरान हम लोगों ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई की। माफिया की संपत्ति को जब्त करवाया, उससे वसूली करवाई और नियुक्ति प्रक्रिया को और पारदर्शी तरीके से संपन्न करते हुए नौ लाख 30 हजार से अधिक नौजवानों को हमने सरकारी नौकरी देने में सफलता प्राप्त की। आज जब यहाँ साढ़े तीन हजार कृषि तकनीकी सहायक और मंडी सचिवों को नियुक्ति पत्र वितरण के इस कार्यक्रम के साथ जोड़ रहा हूँ, मैं प्रदेश भर के युवाओं को इस बात के लिए आश्वस्त कर रहा हूँ कि अगले छह महीने के अंदर एक लाख नौजवानों को सरकारी नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं। हमें बुरा लगता है जब कोई युवा कहता है कि हमने परीक्षा दी है, परिणाम अभी तक नहीं आ पाया। हम आयोग और बोर्डों की बैठक लेते हैं और उनसे कहते हैं कि आपको इतनी स्वतंत्रता दे रखी है, परिणाम भी समय पर लाइए। पहले होता क्या था? आप भी इसी प्रदेश में पढ़े होंगे। यूपी बोर्ड की परीक्षा होती थी। उसमें तीन महीने लगते थे। परिणाम आने में तीन महीने लगते थे। इस प्रकार छह महीने तो साल में ऐसे ही बर्बाद होते थे। उसके अगले तीन महीने प्रवेश की प्रक्रिया अलग है। पर्व और त्योहार अलग हैं। तीन महीने भी बच्चों को पढ़ाई के लिए नहीं मिल पाते थे। तब सरकार नौजवानों को किसी लायक नहीं छोड़ती थी। सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए उन्होंने प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। तात्कालिक रूप से नौजवान को लगता था कि हितैषी हैं, हितैषी नहीं थे। वे युवाओं के दुश्मन थे। मैंने 2017 में जब पहली बैठक किया था। उनसे मैंने कहा कि इसको एक महीना करो। उन्होंने कहा नहीं हो पाएगा। तो मैंने कहा कुर्सी छोड़ो, मैं एक महीने के अंदर कराऊँगा। एक महीने के अंदर कराऊँगा और आज मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता है, मैं 14 दिन में यूपी बोर्ड की परीक्षा कराता हूँ और अगले 14 दिन में उसका परिणाम भी दिलाता हूँ। 56 लाख अभ्यर्थी उस परीक्षा में होते हैं, 56 लाख बच्चे बैठते हैं। मैंने उच्च शिक्षा वालों से भी कहा है कि परीक्षा की प्रणाली को और सीमित करो। परीक्षा बच्चों को प्रताड़ित करने का माध्यम नहीं होना चाहिए। उसका आकलन करने का माध्यम होना चाहिए। उसको सहज बनाओ, सरल बनाओ, उसको आत्मविश्वास से भरपूर करो। योगी ने कहा याद करिए यही उत्तर प्रदेश 2017 के पहले बीमारू राज्य कहा जाता था, बीमारू राज्य था। युवा पलायन कर रहा था, किसान आत्महत्या कर रहा था। बेटी के सामने सुरक्षा का संकट था। व्यापारी माफिया से तबाह था। किसान अपने खेत में जाने से डरता था। खेत में अगर उसने मोटर लगा रखी है तो कब चोरी हो गई, उसको पता ही नहीं होता था। ये यूपी के अंदर होता था और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमने जो नौ लाख 30 हजार यूपी के नौजवानों को यूपी के अंदर नौकरी दी है परिणाम क्या है? उससे यूपी को लाभ हुआ है। ये युवा यूपी को बीमारू राज्य से उभार करके अब भारत की तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में उत्तर प्रदेश को स्थापित करने में सफल हुआ है। आज यूपी के अन्नदाता किसान के खेत से कोई मोटर चोरी करके नहीं लेकर जाता है। उसको मालूम है कोई चोरी करेगा तो अगले दिन लंगड़ा जरूर हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक सप्ताह दिन में, एक सप्ताह रात्रि में बिजली आती थी। वह भी तीन घंटे की बिजली। इसमें क्या विकास कोई करेगा। लगभग 10 घंटे की बिजली हम यूपी के किसानों को देते हैं और बिजली भी फ्री में देते हैं। यानी सरकारी ट्यूबवेल में तो बिजली फ्री ही है। इस मौके पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, राज्य मंत्री सरदार बलदेव सिंह ओलख, प्रमुख सचिव रविंद्र कुमार समेत अन्य लोग मौजूद रहे।

पीएम सूर्य घर योजना को गति देने में जुटा प्रयागराज, 25,452 सौर संयंत्र स्थापित

प्रयागराज, (हि.स.)। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत प्रयागराज में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए तेजी से कार्य किया जा रहा है। जिले में योजना के तहत अब तक 35,345 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। इनमें से 25,452 लाभार्थियों के घरों में सौर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। वहीं, 22,363 लाभार्थियों के खातों में सब्सिडी की धनराशि भी भेजी जा चुकी है। योजना को और गति देने के लिए विभागीय स्तर पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि, पिछले करीब 20 दिनों से स्मार्ट मीटर की उपलब्धता प्रभावित होने के कारण कुछ स्थानों पर सौर संयंत्रों की स्थापना का कार्य प्रभावित हो रहा है। स्मार्ट मीटर उपलब्ध नहीं होने से संयंत्र स्थापित करने की प्रक्रिया पूरी करने में परेशानी आ रही है। इससे योजना की प्रगति पर भी प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका है। इस संबंध में जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता को स्मार्ट मीटर की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। विभाग की ओर से भी समस्या के समाधान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ समय से मिल सके और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में जिले की प्रगति बनी रहे। अतिरिक्त सौंदर्य ऊर्जा, नेडा की नोडल अधिकारी कोमिल द्विवेदी ने बताया कि योजना के तहत जिन वेंडरों को वर्क ऑर्डर मिल रहे हैं, वे अपनी क्षमता के अनुसार पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि बड़ी संख्या में सौर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं और लाभार्थियों को सब्सिडी का लाभ भी मिल रहा है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर की उपलब्धता होने पर लंबित कार्यों में तेजी आएगी। विभाग का प्रयास है कि अधिक से अधिक पात्र परिवारों को पीएम सूर्य घर योजना का लाभ मिले और जिले में स्वच्छ एवं सस्ती सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा सके।

सोशल मीडिया ने समाज को जोड़ा या दूर किया? विद्यार्थियों ने तर्कों से छेड़ी रोचक बहस

औरैया,(हि.स.)। उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद में श्री जनता इंटर कॉलेज अजीतमल में समाजशास्त्र क्लब के तत्वावधान में मंगलवार को वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। समाजशास्त्र प्रवक्ता डॉ. अजय कुमार सिंह के संयोजन में आयोजित प्रतियोगिता का विषय सोशल मीडिया ने हमें समाज से जोड़ा है या दूर कर दिया है रहा। प्रतियोगिता का उद्देश्य विद्यार्थियों में नवाचार, तार्किक चिंतन, अभिव्यक्ति कौशल और सामाजिक जागरूकता विकसित करना रहा। प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने विषय के पक्ष और विपक्ष में प्रभावशाली एवं तर्कपूर्ण विचार प्रस्तुत किए। प्रतिभागियों ने सोशल मीडिया के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों को उदाहरणों के साथ सामने रखा। पक्ष में विचार प्रस्तुत करने वाली कक्षा 11 की छात्रा लक्ष्मी को पुरस्कार प्रदान किया गया, जबकि विपक्ष में प्रभावी तर्क रखने वाले कक्षा 11 के छात्र प्रशान्त को पुरस्कृत किया गया।

इसके अलावा परवीन, श्वेता, जानवी और जय कुमार ने भी प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य कृष्ण मोहन उपाध्याय ने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि वाद-विवाद जैसी गतिविधियां विद्यार्थियों में विचार करने, तर्क प्रस्तुत करने और लोकतांत्रिक ढंग से अपनी बात रखने की क्षमता विकसित करती हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को ऐसी रचनात्मक गतिविधियों में बढ़-चढ़कर भाग लेने के लिए प्रेरित किया। प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल में जीवविज्ञान प्रवक्ता देवेंद्र कुमार, अंग्रेजी प्रवक्ता राजबाला और संस्कृत प्रवक्ता डॉ. बृजेश कुमार सिंह शामिल रहे। डॉ. बृजेश कुमार सिंह ने सोशल मीडिया के प्रभाव एवं दुष्प्रभाव पर प्रकाश डाला। राजबाला ने विद्यार्थियों का उत्साह बढ़ाते हुए सोशल मीडिया के लाभदायक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने की बात कही। कार्यक्रम में डॉ. अजय कुमार सिंह, अनुपम कटारे और नकुल देववंशी ने विद्यार्थियों को विषय की सामाजिक प्रासंगिकता तथा वर्तमान डिजिटल परिवेश के संदर्भ में संबोधित किया। वक्ताओं ने कहा कि सोशल मीडिया आज संवाद, सूचना और सामाजिक सहभागिता का महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है, लेकिन इसके अत्यधिक और असंतुलित प्रयोग से सामाजिक दूरी, समय की बर्बादी तथा वास्तविक मानवीय संबंधों में कमी जैसी चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। कार्यक्रम के संयोजक डॉ. अजय कुमार सिंह ने कहा कि सोशल मीडिया स्वयं न तो वरदान है और न अभिशाप, बल्कि उसका प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसका उपयोग किस प्रकार करते हैं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया रिश्तों का विकल्प नहीं, बल्कि रिश्तों को मजबूत करने का माध्यम बने। कनेक्शन बढ़े, लेकिन कनेक्शन के साथ संवाद और संवेदना भी बनी रहे। उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि हाथ में मोबाइल हो, लेकिन दिल में समाज भी होना चाहिए। दुनिया से जुड़ें, मगर अपनों से न टूटें। प्रतियोगिता ने विद्यार्थियों को अपनी बात रखने के साथ-साथ तकनीक के जिम्मेदार और रचनात्मक उपयोग का संदेश भी दिया।

हरिहरनाथ मंदिर जल चढ़ाने जा रहे गणेश चौथ समिति पदाधिकारियों को पुलिस ने रोक दिया

बिजनौर, (हि.स.)। जनपद बिजनौर से सम्भल के हरिहर नाथ मंदिर में जल चढ़ाने के लिए जा रहे गणेश चौथ समिति धामपुर के पदाधिकारियों को पुलिस ने धामपुर के रेलवे तिराहा पर बैरीकेडिंग कर रोक दिया। पुलिस की कार्रवाई के बाद मौके पर काफी देर तक गहमागहमी का माहौल बना रहा। समिति पदाधिकारियों ने शांतिपूर्वक मंदिर जाने और जलाभिषेक करने की अनुमति देने की मांग की। बताया गया कि गणेश चौथ समिति धामपुर के पदाधिकारी करीब छह सात वाहनों के काफिले के साथ धामपुर से स्योहारा काठ मुरादाबाद होते हुए संभल स्थित हरिहर नाथ मंदिर के लिए रवाना हुए थे। समिति पदाधिकारियों का कहना है कि वे काफी वर्षों से लगातार हरिहर नाथ मंदिर में जल चढ़ाने के लिए जाते रहे हैं, लेकिन हर बार उन्हें पुलिस द्वारा रास्ते में रोक दिया जाता है। इस बार भी पदाधिकारी धार्मिक आस्था के अनुसार शांतिपूर्वक जल चढ़ाने के उद्देश्य से मंदिर के लिए रवाना हुए थे। समिति पदाधिकारियों के अनुसार प्रशासन को उनके कार्यक्रम की जानकारी पहले से थी। उनका आरोप है कि सोमवार सुबह करीब छह बजे से ही पुलिस द्वारा पदाधिकारियों के घरों और उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी। जैसे ही समिति के पदाधिकारी अपने वाहनों के साथ धामपुर से स्योहारा की ओर रवाना हुए, और आगे संभल स्थित हरिहर नाथ मंदिर जाने लगे, पुलिस ने स्योहारा मार्ग में बैरीकेडिंग लगाकर उन्हें रोक लिया। पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद समिति पदाधिकारियों और पुलिस के बीच तीखी बहस हुई। पदाधिकारियों ने पुलिस से कहा कि वे किसी प्रकार का विवाद या अशांति नहीं चाहते हैं। उनका उद्देश्य केवल शांतिपूर्वक हरिहर नाथ मंदिर पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक करना है। आगे जाने की अनुमति नहीं मिलने पर समिति के पदाधिकारी सड़क पर ही बैठ गए और हरिहर मंदिर जाएंगे, जल वहीं चढ़ाएंगे जैसे नारे लगाने लगे। मौके पर काफी देर तक समझाने-बुझाने और बातचीत का दौर चलता रहा। समिति पदाधिकारियों ने प्रशासन से शांतिपूर्ण तरीके से मंदिर पहुंचने की अनुमति देने का अनुरोध किया। गणेश चौथ समिति के संयोजक विजय जैन ने कहा कि समिति के पदाधिकारी वर्षों से धार्मिक आस्था के अनुसार हरिहर नाथ मंदिर में जल चढ़ाने जाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बार भी सभी लोग शांतिपूर्वक यात्रा कर रहे थे और किसी तरह का विवाद पैदा करना उनका उद्देश्य नहीं था। उन्होंने प्रशासन से धार्मिक आस्था का सम्मान करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से जल चढ़ाने की अनुमति देने की मांग की।

धंस गया सीसीएल का लंकास्टर अस्पताल, भवन के साथ जमीन में आई दरारें

गिरिडीह, (हि.स.)। सीसीएल गिरिडीह एरिया में भू-धंसान का मामला प्रकाश में आया है मंगलवार की तड़के सुबह भू-धंसान की जद में सीसीएल का लंकास्टर अस्पताल आ गया। अस्पताल की दो भवन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। दोनों भवनों का हिस्सा धंस गया है। जबकि सड़क के साथ-साथ बड़ा भू-भाग में भी चौड़ी-चौड़ी दरार आ गई है। घटना की जानकारी पर सीसीएल गिरिडीह एरिया जीएम कन्हैया शंकर गैवाल, परियोजना पदाधिकारी गोपाल सिंह मीणा, चिकित्सक पदाधिकारी परिमल सिन्हा, सिविल विभाग के रामाकांत समेत अन्य लोग पहुंचे और पूरी स्थिति की जानकारी ली। घटना को लेकर अस्पताल के कर्मी दिलीप कुमार ने बताया कि सोमवार की रात्रि पाली में ड्यूटी में थे। सुबह 4 बजे के आसपास जब वे अन्य कर्मियों के साथ बाहर निकले तो देखा कि जमीन के साथ भवन में धंसान हो रहा है। तुरंत ही सभी कर्मियों को बाहर निकाला और फिर सूचना अधिकारियों को दी। उन्होंने कहा कि यह पूरा अस्पताल खतरे की जद में हैं। उल्लेखनीय है कि इस इलाके में बड़े पैमाने पर अवैध खनन का काम होता रहा है। दशकों से अवैध तरीके से कोयला का खनन किया जाता रहा है। यही कारण है कि यहां की जमीन खोखली हो गई है और धंसान हो रहा है। जिसके जद में अब सीसीएल के एरिया अस्पताल भी आ गया है। वहीं, जीएम, पीओ ने पूरे अस्पताल परिसर का निरीक्षण किया। जीएम ने अधिकारियों को एहतियातन कदम उठाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इस इलाके में किसी की एंट्री नहीं हो, इसे सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। इसे लेकर सीसीएल गार्ड और होम गार्ड की तैनाती कर दी गई है। पत्रकारों से बात करते हुए जीएम ने कहा कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और आगे की रणनीति तय की जाएगी।

सावन की अंतिम सोमवारी पर मनोज तिवारी के गानों पर झूमे लोग

पूर्वी सिंहभूम, (हि.स.)। सावन माह की अंतिम सोमवारी पर जमशेदपुर में आस्था और भक्ति का अद्भुत रंग देखने को मिला। हर हर महादेव संघ की ओर से आयोजित भव्य भजन संध्या में शहर के अलग-अलग इलाकों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। देर रात तक भक्ति गीतों और भगवान भोलेनाथ के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहा। कार्यक्रम में प्रसिद्ध भोजपुरी गायक और सांसद मनोज तिवारी मुख्य आकर्षण रहे। मंच पर पहुंचते ही श्रद्धालुओं ने जोरदार स्वागत किया। मनोज तिवारी ने भगवान शिव की आराधना से जुड़े भजनों की प्रस्तुति दी, जिस पर श्रद्धालु देर तक झूमते रहे। उनके गीतों के बीच पूरा परिसर हर हर महादेव और बोल बम के जयघोष से गूंजता रहा। सावन की अंतिम सोमवारी होने के कारण कार्यक्रम को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह था। भजन संध्या के दौरान महिला, पुरुष और युवा श्रद्धालु शिव भजनों पर भक्तिभाव से झूमते दिखाई दिए। कई श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हुए सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। हर हर महादेव संघ के सदस्यों ने बताया कि सावन की अंतिम सोमवारी पर प्रत्येक वर्ष श्रद्धालुओं के लिए इस तरह के धार्मिक आयोजन किए जाते हैं।

सरकारी भर्तियों की मांग को लेकर पटना में छात्रों का उग्र प्रदर्शन, बैरिकेडिंग तोड़ी, वाटर कैनन से रोका मार्च

पटना, (हि.स.)। बिहार में सरकारी भर्तियों को लेकर छात्रों का आंदोलन मंगलवार को उग्र हो गया। पटना के गर्दनीबाग में 18 अगस्त से धरने पर बैठे छात्रों ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए मार्च निकाला। ऑल बिहार स्टूडेंट यूनियन (एबीएसयू) के छात्र नेता अमन गुट के नेतृत्व में निकले इस मार्च को रोकने के लिए प्रशासन ने जेपी गोलंबर पर भारी संख्या में पुलिस बल और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के जवानों की तैनाती की थी। मार्च के दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों ने जेपी गोलंबर पर लगाए गए बैरिकेडिंग को तोड़ दिया और डाकबंगला की ओर आगे बढ़ने का प्रयास किया। इस दौरान छात्रों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक और तनातनी की स्थिति उत्पन्न हो गई। गांधी मैदान से लेकर इनकम टैक्स गोलंबर तक कई स्थानों पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच भिड़ंत की सूचना है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। गर्दनीबाग में पिछले कई दिनों से धरना दे रहे छात्र अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। मंगलवार को छात्रों ने धरना स्थल से मुख्यमंत्री आवास की ओर मार्च शुरू किया। प्रशासन ने पहले ही जेपी गोलंबर सहित प्रमुख मार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी थी। छात्र जैसे ही जेपी गोलंबर पहुंचे, पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बैरिकेडिंग कर दी। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग हटाकर आगे बढ़ने का प्रयास किया। इसके बाद पुलिस और छात्रों के बीच टकराव की स्थिति बन गई। पुलिस और सीआरपीएफ की टीमें छात्रों को आगे बढ़ने से रोकने में जुटी रहीं। प्रदर्शन के कारण पटना के कई प्रमुख मार्गों पर तनाव की स्थिति बनी हुई है और यातायात भी प्रभावित होने की सूचना है। आंदोलन कर रहे छात्रों की प्रमुख मांग बीपीएससी टीआरई-4 शिक्षक भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया को सरल और स्पष्ट करना है। छात्रों की मांग है कि टीआरई-4 में एक ही परीक्षा के माध्यम से प्रारंभिक परीक्षा (पीटी) और मुख्य परीक्षा (मेंस) की प्रक्रिया पूरी की जाए। छात्रों का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया को इस तरह बनाया जाना चाहिए कि अभ्यर्थियों को बार-बार अलग-अलग परीक्षाओं में शामिल नहीं होना पड़े। उनका तर्क है कि इससे भर्ती प्रक्रिया लंबी होने के साथ अभ्यर्थियों पर अतिरिक्त आर्थिक और मानसिक दबाव भी पड़ता है। इसके साथ ही छात्र टीआरई-4 भर्ती प्रक्रिया में नेगेटिव मार्किंग खत्म करने और परीक्षा प्रक्रिया को अधिक स्पष्ट बनाने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों की एक प्रमुख मांग बिहार की सरकारी नौकरियों में 100 प्रतिशत डोमिसाइल नीति लागू करने की भी है। छात्रों का कहना है कि राज्य की सरकारी नौकरियों में बिहार के स्थानीय अभ्यर्थियों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। छात्रों ने बिहार कर्मचारी चयन आयोग (बीएसएससी) से संबंधित भर्ती प्रक्रियाओं में भी बदलाव की मांग उठाई है। इनमें संविदा कर्मचारियों को मिलने वाला वेटेज समाप्त करने की मांग शामिल है। छात्रों ने बीएसएससी सीजीएल-4, बीएसओ और एईडीओ परीक्षाओं की तारीख जल्द जारी करने की मांग की है। उनका कहना है कि विभिन्न भर्ती परीक्षाओं की तारीख और परीक्षा कैलेंडर को लेकर स्पष्टता नहीं होने से अभ्यर्थियों को लगातार अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने लाइब्रेरियन और बिहार पात्रता परीक्षा से जुड़ी भर्ती प्रक्रिया शुरू करने तथा विभिन्न सरकारी विभागों में लंबे समय से खाली पड़े पदों को जल्द भरने की मांग भी उठाई है। छात्रों ने सरकारी भर्ती परीक्षाओं में उम्र सीमा में छूट देने की भी मांग की है। आंदोलनकारी अभ्यर्थियों का कहना है कि लंबे समय से नियमित भर्ती प्रक्रिया नहीं होने के कारण बड़ी संख्या में अभ्यर्थी निर्धारित आयु सीमा से बाहर हो रहे हैं। छात्रों का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया में देरी का खामियाजा उन युवाओं को भुगतना पड़ रहा है, जिन्होंने वर्षों से सरकारी नौकरी की तैयारी की है। ऐसे अभ्यर्थियों के लिए उम्र सीमा में उचित छूट दी जानी चाहिए। आंदोलनकारी छात्रों ने दरोगा, सिपाही, बीएसएससी और बीपीएससी समेत सभी भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की है। छात्रों का कहना है कि भर्ती परीक्षाओं की प्रक्रिया समयबद्ध, निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए। परीक्षा से लेकर परिणाम और नियुक्ति तक हर चरण के लिए स्पष्ट समयसीमा तय की जानी चाहिए, ताकि अभ्यर्थियों को लंबे समय तक अनिश्चितता में न रहना पड़े। मंगलवार को प्रदर्शन के दौरान छात्र लगातार डाकबंगला की ओर बढ़ने की कोशिश करते रहे, जबकि पुलिस और सीआरपीएफ की टीमें उन्हें आगे जाने से रोकती रहीं। बैरिकेडिंग तोड़े जाने और पुलिस की कार्रवाई के बाद कई स्थानों पर तनाव की स्थिति बनी रही। फिलहाल प्रदर्शनकारी छात्रों और सुरक्षा बलों के बीच गतिरोध बना हुआ है। छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी भर्ती संबंधी मांगों पर सरकार की ओर से ठोस आश्वासन नहीं मिलता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।

बारिश से चमकी धान की फसल, अन्नदाताओं के खिले चेहरे

भागलपुर, हि.स.)। जिले में पिछले कई दिनों से जारी उमस भरी गर्मी और सूखे जैसे हालात के बाद, बीते दिन हुई झमाझम बारिश ने किसानों को बड़ी राहत दी है। इस बारिश से जहां आम लोगों को गर्मी से निजात मिली है, वहीं मुरझा रही धान की फसल को नया जीवनदान मिल गया है। बारिश की बूंदें गिरते ही जिले के अन्नदाताओं के चेहरे खिल उठे हैं और वे पूरी ऊर्जा के साथ खेतों की ओर रुख कर चुके हैं। बीते दिन हुई अच्छी बारिश के कारण धान के खेतों में पानी जमा हो गया है, जिससे मिट्टी की नमी लौट आई है। इस अनुकूल मौसम को देखते हुए किसानों ने खेतों में खाद डालने का काम युद्धस्तर पर शुरू कर दिया है। प्रखंडों से मिल रही रिपोर्ट के अनुसार, सुबह से ही किसान अपने कंधों पर खाद के बोरे लिए खेतों में नजर आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि धान की रोपाई के बाद यह बारिश संजीवनी की तरह है। पानी की उपलब्धता के कारण अब पौधों में कल्ले तेजी से निकलेंगे, जिससे पैदावार अच्छी होने की उम्मीद है। जिले में धान की फसल की स्थितिचालू खरीफ सीजन में बारिश की शुरूआती सुस्ती के कारण जिले में धान की रोपाई पर विपरीत असर पड़ा था। कई इलाकों में धान के खेतों में दरारें पड़ने लगी थीं। हालांकि, हालिया बारिश ने इन दरारों को पाट दिया है। वर्तमान में जिले में अगेती धान की फसल गभ्भा आने की स्थिति में है, जबकि देर से रोपे गए धान के पौधों को इस पानी से सबसे ज्यादा फायदा पहुंचा है। कृषि विभाग के अनुसार, इस बारिश से जिले में धान के उत्पादन के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। भागलपुर जिले में चालू खरीफ सीजन के तहत कृषि विभाग ने कुल 56 हजार हेक्टेयर में धान की खेती का लक्ष्य तय किया है। हालिया मानसूनी बारिश के बाद जिले में धान की रोपाई की रफ्तार काफी तेज हुई है और जिला कृषि कार्यालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार अब तक जिले में कुल लक्ष्य का 92 फीसदी (92%) बुआई का कार्य पूरा किया जा चुका है। जिला कृषि कार्यालय के अनुसार, भागलपुर के सभी 16 प्रखंडों में अब तक कुल 92% धान की रोपनी पूरी हो चुकी है। सबौर, सनहौला और जगदीशपुर जैसे प्रखंडों में रोपनी 93-94% के पार पहुंच गई है, जबकि नवगछिया और टाल क्षेत्रों में भी बारिश के बाद किसान तेजी से शत-प्रतिशत लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र के वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिकों ने इस बारिश को धान के लिए बेहद फायदेमंद बताया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि खेतों में पर्याप्त पानी होने पर ही नाइट्रोजन का छिड़काव करें, ताकि पौधे इसे अच्छी तरह सोख सकें। नमी और उमस बढ़ने से फसलों में 'ब्राउन प्लांट हॉपर' या अन्य कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है, इसलिए खेतों की नियमित निगरानी करें। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पटना केंद्र के अनुसार, राज्य में मानसून का सिस्टम एक बार फिर सक्रिय हुआ है। मौसम वैज्ञानिकों ने पूर्वानुमान जारी करते हुए बताया है कि आगामी 26 अगस्त तक जिले सहित उत्तर और दक्षिण बिहार के कई हिस्सों में बादल छाए रहेंगे और गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम तथा कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने के पूरे आसार हैं।

सर्राफा बाजार में महंगा हुआ सोना, चांदी के भाव में कोई बदलाव नहीं

नई दिल्ली

सर्राफा बाजार में शुरुआती कारोबार के दौरान सोने के भाव में तेजी का रुख बना हुआ नजर आ रहा है। दूसरी ओर चांदी के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ है। देश के ज्यादातर सर्राफा बाजार में सोना 820 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 900 रुपये प्रति 10 ग्राम तक महंगा हो गया है।

कीमत में हुए इस बदलाव के कारण देश के ज्यादातर सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना 1,63,980 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 1,64,130 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह 22 कैरेट सोना 1,50,310 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 1,50,460 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच बिक रहा है। चांदी के भाव में बदलाव नहीं होने के कारण ये चमकीली धातु दिल्ली सर्राफा बाजार में भी 2,59,900 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर बिक रही है।

दिल्ली में 24 कैरेट सोना 1,64,130 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 1,50,460 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 24 कैरेट सोना 1,63,980 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,50,310 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। इसी तरह अहमदाबाद में 24 कैरेट सोने की रिटेल कीमत 1,64,030 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत 1,50,360 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है।

इन प्रमुख शहरों के अलावा चेन्नई में 24 कैरेट सोना 1,63,980 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर और 22 कैरेट सोना 1,50,310 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर बिक रहा है। इसी तरह कोलकाता में 24 कैरेट सोना 1,63,980 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,50,310 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। भोपाल में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,64,030 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है, जबकि 22 कैरेट सोना 1,50,360 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है।

जयपुर में 24 कैरेट सोना 1,64,130 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,50,460 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। पटना में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,64,030 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है, जबकि 22 कैरेट सोना 1,50,360 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। लखनऊ के सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना 1,64,130 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर और 22 कैरेट सोना 1,50,460 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है।

देश के अन्य राज्यों की तरह कर्नाटक, तेलंगाना और ओडिशा के सर्राफा बाजार में भी सोने के भाव में शुरुआती कारोबार के दौरान तेजी का रुख बना हुआ है। इन तीनों राज्यों की राजधानियों बेंगलुरु, हैदराबाद और भुवनेश्वर में 24 कैरेट सोना 1,63,980 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह इन तीनों शहरों के सर्राफा बाजारों में 22 कैरेट सोना 1,50,310 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है।

न्यूज ब्रीफ

धतूरा बेचने पर एमेजान, स्विगी और बिगबास्केट के फूड लाइसेंस सस्पेंड

नई दिल्ली। कर्नाटक के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने एक बड़ा कदम उठाते हुए एमेजान, स्विगी इंस्टामार्ट और बिग बास्केट के फूड लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए हैं। यह कार्रवाई इन ई-कामर्स प्लेटफार्म्स पर जहरीले धतूरे के फल और बीजों को खाद्य उत्पाद के रूप में बेचने पर की गई है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। विभाग की जांच में सामने आया कि धतूरे के उत्पाद एफएसएसएआई लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ खाद्य उत्पाद के तौर पर बेचे जा रहे थे। सुनवाई में एमेजान ने कोई जवाब नहीं दिया, स्विगी इंस्टामार्ट ने अतिरिक्त समय मांगा, जबकि बिगबास्केट ने बिक्री रोकने और मानव उपभोग के लिए नहीं लेबल लगाने की बात कही। हालांकि, प्राधिकरण ने इन स्पष्टीकरणों को संतोषजनक नहीं माना, क्योंकि निरीक्षण में वेयरहाउस में भी ऐसे पैकेट मिले थे। धतूरे की जहरीली प्रकृति के कारण इसे खाद्य पदार्थ के रूप में बेचना अस्वीकार्य है। विभाग ने इन कंपनियों को धतूरे के उत्पाद से जुड़ी सभी आनलाइन लिस्टिंग तत्काल हटाने का निर्देश दिया है। साथ ही, उत्पाद उपलब्ध कराने वाले सप्लायर/विक्रेताओं के लाइसेंस भी निलंबित करने को कहा गया है। कंपनियों को जल्द अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करनी होगी, जिसके बाद ही लाइसेंस बहाली पर विचार होगा।

भारतीय बाजार में नई बजाज पल्सर 125 और 150 जल्द होगी लांच

नई दिल्ली। भारतीय बाजार में बजाज आटो कंपनी नई पल्सर 125 और पल्सर 150 को जल्द पेश करेगी। जानकारी के अनुसार, दोनों मोटरसाइकिलों का डिजाइन मौजूदा माडल की तुलना में अधिक आधुनिक होगा। पल्सर 150 में बेहतर शीतलन व्यवस्था वाला एक नया इंजन मिलने की संभावना है, जिससे इसके प्रदर्शन में सुधार की उम्मीद है। वहीं, मौजूदा पल्सर 125 में 124.4 घन सेंटीमीटर का हवा से ठंडा होने वाला इंजन मिलता है। नई मोटरसाइकिलों में इंजन के प्रदर्शन और तकनीक को लेकर आधिकारिक आंकड़े लान्च के समय सामने आएंगे। नई पल्सर 125 और पल्सर 150 में सबसे बड़े बदलावों में से एक इनके ढांचे से जुड़ा होगा, जहां मौजूदा ट्विन-क्रैडल ढांचे की जगह नए माडलों में सिंगल-डाउनट्यूब ढांचा दिया जाएगा। पीछे की ओर भी महत्वपूर्ण बदलाव किया जा रहा है, जिसमें मौजूदा दो शाक अवशोषक की जगह मोनोशाक सस्पेंशन दिया जाएगा। आगे की ओर पारंपरिक दूरबीननुमा सस्पेंशन मिलने की उम्मीद है। ब्रेकिंग के लिए आगे डिस्क ब्रेक और पीछे ड्रम ब्रेक के साथ एकल-चैनल एबीएस मिलने की संभावना है। कंपनी ने पल्सर के पुराने स्वरूप को पूरी तरह बदलने के बजाय उसे आधुनिक रूप देने की रणनीति अपनाई है। नई मोटरसाइकिलों में हेडलाइट के आसपास का हिस्सा पहले से अलग दिखाई देगा और साइड पैनल में भी बदलाव किए जाएंगे।

ईपीएफ खाते पर ब्याज कब तक नौकरी छोड़ने पर तुरंत बंद नहीं होता, जानें नियम

नई दिल्ली। अक्सर कर्मचारियों को लगता है कि नौकरी छोड़ते ही उनके भविष्य निधि (ईपीएफ) खाते पर ब्याज मिलना बंद हो जाता है। हालांकि, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने इस आम गलतफहमी को दूर करते हुए स्पष्ट किया है कि ईपीएफ पर ब्याज कब तक मिलेगा, यह कर्मचारी की उम्र और रिटायरमेंट की स्थिति पर निर्भर करता है। ईपीएफओ के नए नियमों के अनुसार, हर मामले में ब्याज तुरंत नहीं रुकता, बल्कि कुछ खास प्रावधानों के तहत यह जारी रह सकता है। 55 साल से पहले नौकरी छोड़ने पर भी मिलता है ब्याज ईपीएफओ के दिशानिर्देशों के मुताबिक, यदि कोई कर्मचारी 55 साल की उम्र से पहले नौकरी छोड़ता है या स्वैच्छिक रिटायरमेंट लेता है, तो उसके ईपीएफ खाते पर ब्याज तुरंत बंद नहीं होता। ऐसे मामलों में, कर्मचारी को 58 साल की उम्र तक खाते में जमा राशि पर ब्याज मिलता रहता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस श्रेणी के लिए रिटायरमेंट की तारीख से तीन साल पूरे होने पर खाता निष्क्रिय मानकर ब्याज रोकने का नियम लागू नहीं होता।

सेबी लाएगा बड़े बदलाव, नियम होंगे सरल एवं बढ़ेगी निवेशक सुरक्षा

संबंधित पक्ष लेन-देन से लेकर इश्यू की रकम तक, नियामक कर रहा समीक्षा

नई दिल्ली

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कंपनियों के लिए नियमों का पालन आसान बनाने और निवेशकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कई बड़े बदलावों की योजना बनाई है। सेबी चेयरमैन ने हाल ही में इन सुधारों का संकेत दिया है, जिसके तहत आपस में जुड़े पक्षों के बीच लेन-देन (आरपीटी) और इश्यू से मिली रकम के उपयोग की निगरानी से जुड़े नियमों की समीक्षा की जा रही है। इसी बीच नेशनल स्टाक एक्सचेंज (एनएसई) ने अधिकृत व्यक्तियों (एपी) पर कार्रवाई की समय-सीमा को सख्त किया है, जबकि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज (पीएमएस) में सह-निवेश ने जुलाई में रिकार्ड वृद्धि दर्ज की है।

सेबी का नियामक सरलीकरण और निवेशक सुरक्षा पर जोर: सेबी की योजना कंपनियों के लिए संबंधित पक्ष लेन-देन (आरपीटी) से जुड़े नियमों को और स्पष्ट व आसान बनाने की है। इसका दोहरा मकसद कंपनियों के लिए अनुपालन को सुगम बनाना और निवेशकों के हितों की रक्षा करना है। इसके साथ ही नियामक इश्यू से मिली रकम के इस्तेमाल की निगरानी और उसकी जानकारी देने (डिस्क्लोजर) से जुड़े नियमों की भी समीक्षा कर रहा है, ताकि समय पर पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके और नियमों का पालन करना सरल हो। सेबी एक ऐसा नियम भी लाने पर विचार कर रहा है, जिससे कई एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध कंपनियां एक ही मामले के लिए अलग-अलग एक्सचेंजों के जुर्माने से बच सकेंगी।

एनएसई ने अधिकृत व्यक्तियों पर कार्रवाई की समय-सीमा की सख्त: नेशनल स्टाक एक्सचेंज (एनएसई) ने स्टाक ब्रोकरों के लिए नियमों का पालन न करने वाले अधिकृत व्यक्तियों (एपी) के खिलाफ कार्रवाई की समय-सीमा को बेहद सख्त कर दिया है। एपी स्टाक ब्रोकर के ऐसे एजेंट होते हैं जो ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करते हैं। अब ब्रोकरों को तिमाही खत्म होने के दो महीने के भीतर अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी होगी और इसकी रिपोर्ट तीन महीने के अंदर जमा करनी होगी। हालांकि, यदि कार्रवाई के तौर पर एपी को हटाना (टर्मिनेशन) शामिल है, तो सदस्य को जांच रिपोर्ट मिलने या नियमों का उल्लंघन पता चलने के सात दिनों के भीतर कार्रवाई करनी होगी। यह नई समय-सीमा जुलाई-सितंबर 2026 तिमाही से लागू होगी और इसका उद्देश्य निवेशकों की सुरक्षा को मजबूत करना है।

पीएमएस में सह-निवेश ने दर्ज की रिकार्ड बढ़ोतरी: पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज (पीएमएस) में सह-निवेश के तहत प्रबंधनाधीन परिसंपत्तियां (एयूएम) जुलाई में उल्लेखनीय रूप से बढ़ी हैं। यह मासिक आधार पर 10.2 फीसदी बढ़कर 6,743 करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जो इस साल की सबसे बड़ी मासिक बढ़ोतरी है। सह-निवेश की सुविधा पीएमएस ग्राहकों को बड़े पोर्टफोलियो के बजाय विशिष्ट निवेश अवसरों पर मैनेजर के साथ मिलकर निवेश करने की अनुमति देती है। इस बढ़ोतरी में असूचीबद्ध सामान्य डेट का अहम योगदान रहा, जिनकी एयूएम में महीने के दौरान 36.9 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई। वहीं, 44 फीसदी हिस्सेदारी के साथ इस सेगमेंट का सबसे बड़ा हिस्सा रही असूचीबद्ध इक्विटी में भी 2.3 फीसदी की बढ़ोतरी हुई।

गेहूं उत्पादों के निर्यात से हटा प्रतिबंध, अच्छी पैदावार के बाद सरकार का फैसला

नई दिल्ली

घरेलू खाद्य सुरक्षा और मूल्य नियंत्रण के लिए 2022 में लगाई गई थी रोक

केंद्र सरकार ने गेहूं से बने उत्पादों की निर्यात नीति में बड़ा बदलाव करते हुए उन पर लगे प्रतिबंध हटा लिए हैं। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अब गेहूं या मेस्लिन आटा, मैदा, सूजी, होलमील आटा और मिश्रित गेहूं के आटे का निर्यात बिना किसी बाधा के किया जा सकेगा। यह फैसला देश में गेहूं की बेहतर उपलब्धता और रिकार्ड उत्पादन अनुमानों के बीच लिया गया है, जिससे घरेलू खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होने के साथ-साथ किसानों और निर्यातकों को भी लाभ मिलने की उम्मीद है।

यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब भारत ने 2022 में गेहूं और उससे बने उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। उस वक्त सरकार का मुख्य उद्देश्य देश की 1.4 अरब आबादी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और घरेलू बाजार में गेहूं व आटे की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाना था।

13 मई 2022 को गेहूं की निर्यात नीति को मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में लाया गया था, जिसके बाद उसी साल अगस्त में गेहूं के आटे के निर्यात पर भी इसी तरह के प्रतिबंध लागू किए गए। यह कदम रूस-यूक्रेन संघर्ष के कारण वैश्विक स्तर पर गेहूं की आपूर्ति में आई बाधा और भारतीय गेहूं की बढ़ती विदेशी मांग के जवाब में उठाया गया था, जिसने घरेलू कीमतों पर भारी दबाव डाला था। हालांकि, प्रतिबंधों के बावजूद, सरकार ने कुछ विशेष गेहूं उत्पादों के निर्यात की अनुमति बनाए रखी थी। इस साल फरवरी में, बेहतर स्टाक उपलब्धता का हवाला देते हुए, सरकार ने 25 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) गेहूं और अतिरिक्त 5 एलएमटी गेहूं उत्पादों के निर्यात की अनुमति दी थी। ताजा आंकड़ों के अनुसार, भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन रिकार्ड स्तर पर पहुंचने का अनुमान है।

टीसीएस ने जर्मनी की लग्जरी कार निर्माता पार्श के साथ की साझेदारी

मुंबई। भारतीय आईटी दिग्गज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) ने जर्मनी की लग्जरी कार निर्माता पार्श के साथ एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। इस डील के तहत टीसीएस पार्श के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) पर पांच साल तक काम करेगी और साथ ही पार्श की आईटी व कंसल्टिंग कंपनी एमएचपी का भी अधिग्रहण करेगी। हालांकि घोषणा के बावजूद कारोबार में कंपनी के शेयर में हल्की गिरावट दर्ज की गई। टीसीएस और पार्श के बीच यह साझेदारी पांच साल के लिए हुई है, जिसकी कुल वैल्यू 1.25 अरब यूरो (करीब 11,000 करोड़ रुपये) है। इस समझौते के तहत टीसीएस पार्श के कारोबार में एआई के इस्तेमाल को बढ़ावा देगी। इसमें गाड़ियों की इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग से लेकर कंपनी के दैनिक कामकाज और ग्राहक अनुभव तक सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जाएगा। टीसीएस इसके लिए एक विशेष एआई मोबिलिटी सेंटर भी स्थापित करेगी, जो आटो सेक्टर में एआई और नई तकनीकों के विकास पर केंद्रित होगा। डील का दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा पार्श की आईटी और कंसल्टिंग कंपनी का अधिग्रहण है, जिसे टीसीएस 32 करोड़ यूरो (लगभग 2,800 करोड़ रुपये) में खरीदेगी।

वाणिज्य मंत्री गोयल ने जापान से अधिक संस्थागत पूंजी निवेश का किया आह्वान

नई दिल्ली/टोक्यो

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जापान के प्रमुख वित्तीय एवं निवेश संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में दीर्घकालिक पूंजी प्रवाह एवं निवेश साझेदारी मजबूत करने और भारत की विकास यात्रा में जापानी भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा की।

गोयल ने एक्स पर जारी पोस्ट में लिखा, टोक्यो में दूसरे दिन की शुरुआत प्रमुख विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) के प्रतिनिधियों के साथ नाश्ते पर गोलमेज बैठक से हुई। इस दौरान भारत में निवेश के बदलते माहौल, ईज आफ डूइंग बिजनेस (कारोबार में आसानी) में हुई प्रगति और अलग-अलग सेक्टर में उभर रहे व्यापक अवसरों पर चर्चा की गई। साथ ही, ग्लोबल निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल बनाने और साझा विकास के लिए मजबूत व लंबे समय तक चलने वाली पार्टनरशिप बनाने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया गया।

बैठक में मित्सुबिशी यूएफजे फाइनेंशियल ग्रुप (एमयूएफजी), डेवलपमेंट बैंक आफ जापान (डीबीजे), मिजुहो, मार्गन स्टेनली, नोमुरा और निप्पान लाइफ के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हुए। इस दौरान भारत की आर्थिक संभावनाओं, उभरते निवेश अवसरों और जापानी संस्थागत निवेश को और सुगम बनाने के उपायों पर विचारों का आदान-प्रदान हुआ।

गोयल ने बैठक में भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था पिछले साल 7.7 फीसदी बढ़ी और देश साल 2047 तक 30 लाख करोड़ डालर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में काम कर रहा है। उन्होंने भारत के मजबूत बैंकिंग क्षेत्र, पर्याप्त पूंजी और गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के कम स्तर के साथ-साथ देश में बढ़ते मध्यम वर्ग और बढ़ती खर्च योग्य आय का उल्लेख किया। मंत्री ने कहा कि सेमीकंडक्टर, कृत्रिम मेधा (एआई), डेटा सेंटर, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, उन्नत विनिर्माण और डिजिटल बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में जापानी कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण अवसर मौजूद हैं। वाणिज्य मंत्रालय ने बयान में कहा, जापानी वित्तीय संस्थानों ने भारत के साथ बढ़ती भागीदारी साझा की और देश की दीर्घकालिक विकास संभावनाओं पर मजबूत भरोसा जताया। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने एक्स पर जारी एक अन्य पोस्ट में लिखा है कि कावासाकी हेवी इंडस्ट्रीज़ के प्रेसिडेंट और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) यासुहिको हाशिमोटो और वहां के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। गोयल ने बताया कि हमने रोबोटिक्स, हाइड्रोजन टेक्नोलाजी और हेवी इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के अवसरों पर चर्चा की। भारत के बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन एनर्जी के लक्ष्यों को देखते हुए, जापान की बड़ी कंपनियों के साथ सहयोग की काफी संभावनाएं हैं।

ग्लोबल मार्केट से कमजोरी के संकेत, एशिया में भी बिकवाली का दबाव

नई दिल्ली

ग्लोबल मार्केट से कमजोरी के संकेत मिल रहे हैं। अमेरिकी बाजार पिछले सत्र के दौरान गिरावट के साथ बंद हुए। वहीं डाउ जान्स फ्यूचर्स फिलहाल मामूली बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। यूरोपीय बाजार में पिछले सत्र के दौरान मिला-जुला कारोबार होता रहा, जबकि एशियाई बाजार में दबाव के बीच कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है।

टेक शेयरों में हुई बिक्री के कारण पिछले सत्र के दौरान अमेरिकी बाजार में दबाव बना रहा, जिसकी वजह से वाल स्ट्रीट के सूचकांक गिरावट के साथ बंद हुए। एस एंड पी 500 इंडेक्स 0.28 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 7,652.86 अंक के स्तर पर बंद हुआ। इसी तरह नैस्डेक ने 200.26 अंक यानी 0.76 प्रतिशत टूट कर 25,980.19 अंक के स्तर पर पिछले सत्र के कारोबार का अंत किया। डाउ जान्स फ्यूचर्स फिलहाल 0.03 प्रतिशत की मामूली तेजी के साथ 53,430.70 अंक के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है।

यूरोपीय बाजार पिछले सत्र के कारोबार के बाद मिले-जुले परिणाम के साथ बंद हुए। एफटीएसई इंडेक्स 0.35 प्रतिशत उछल कर 10,854.32 अंक के स्तर पर बंद हुआ। इसके विपरीत सीएसी इंडेक्स ने 0.37 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 8,453.01 अंक के स्तर पर पिछले सत्र के कारोबार का अंत किया। इसके अलावा डीएएक्स इंडेक्स 0.11 प्रतिशत फिसल कर 26,106.60 अंक के स्तर पर बंद हुआ। एशियाई बाजार में लगातार दबाव बना हुआ नजर आ रहा है। एशिया के नौ बाजार में से सात के सूचकांक गिरावट के साथ लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं, जबकि दो सूचकांक मजबूती के साथ हरे निशान में बने हुए हैं। निक्केई इंडेक्स 252.91 अंक यानी 0.39 प्रतिशत की बढ़त के साथ 65,781 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.37 प्रतिशत की तेजी के साथ 5,701.64 अंक के स्तर पर पहुंचा हुआ है।

दूसरी ओर, गिफ्ट निफ्टी 0.11 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 24,183.50 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह हैंग सेंग इंडेक्स 0.21 प्रतिशत लुढ़क कर 25,464 अंक के स्तर पर पहुंच गया है। ताइवान वेटेड इंडेक्स में बड़ी गिरावट नजर आ रही है। फिलहाल यह सूचकांक 372.08 अंक यानी 0.83 प्रतिशत टूट कर 44,390.24 अंक के स्तर तक गिर गया है।

इसी तरह कोस्पी इंडेक्स 0.64 प्रतिशत फिसल कर 6,653.93 अंक के स्तर पर पहुंचा हुआ है। इसके अलावा जकार्ता कंपोजिट इंडेक्स 0.37 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 6,501.67 अंक के स्तर पर, शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.15 प्रतिशत की गिरावट के साथ 3,876.38 अंक के स्तर पर और सेट कंपोजिट इंडेक्स 0.09 प्रतिशत टूट कर 1,599.64 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहे हैं।

एशियाई खेलों में अपने पदकों का सूखा दूर करने उतरेगी मीराबाई चानू

नई दिल्ली

भारत की अनुभवी भारोत्तोलक मीराबाई चानू का लक्ष्य जापान के आइची-नागोया, जापान में होने वाले आगामी एशियाई खेलों में पदक जीतना है। एशियाई खेल 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक खेले जाएंगे और चानू को इसमें पांच सदस्यीय भारतीय भारोत्तोलन टीम में उन्हें शामिल किया गया है और वह इन खेलों मे पदक की प्रबल दावेदार के तौर पर उतरेंगी।

चानू अब तक एक भी बार एशियाई खेलों में पदक नहीं जीत पायी हैं हालांकि उनक पास ओलंपिक पदक है। गौरतलब है कि महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में प्रतिस्पर्धा करने वाली चानू ने अपने करियर में ओलंपिक से लेकर राष्ट्रमंडल खेलों में कई स्वर्ण पदक जीते हैं पर हैरानी की बात है कि वह एशियाई खेलों में एक भी पदक नहीं जीत पायी हैं।

साल 2023 हांगझोऊ एशियाई खेलों में पदक के बेहद करीब थीं पर उन्हें अंत में चौथे स्थान से संतोष करना पड़ा था। मीराबाई ने इस लक्ष्य के महत्व पर जोर देते हुए कहा है, एशियाई खेलों का पदक मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा।

मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी क्योंकि मुझे वहां जीतना है जहां मैंने पहले कभी पदक नहीं जीता है। इसलिए, एशियाई खेल मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। आइची-नागोया में पदक जीतने से मीराबाई चानू का तीन बड़े खेल आयोजनों ओलंपिक, एशियाई खेल और राष्ट्रमंडल में पदकों का संग्रह पूरा हो जाएगा, जो उन्हें इस खेल के दिग्गजों के क्लब में पहुंचा देगा।

वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता 22 से 28 सितंबर तक टोकाई सिटिजन्स जिम्नेजियम में होगी, भारतीय टीम में चार महिलाएं और एक पुरुष भरोत्तोलक शामिल हैं। इस टीम की खासियत यह है कि पांच में से चार सदस्यों ने हाल ही में ग्लासगो में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीते थे, जो उनकी वर्तमान फार्म और क्षमता को दर्शाता है।

मीराबाई के अलावा, टीम में महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में ज्ञानेश्वरी यादव और 69 किलोग्राम वर्ग में हरजिंदर कौर शामिल हैं, दोनों ने पिछले महीने राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीता था। सेराम निरुपमा देवी 61 किलोग्राम कैटेगरी में महिला टीम को पूरा करती हैं।

वहीं पुरुषों में, ऋषिकांत सिंह चनमबम एशियाई खेलों में भारत के एकमात्र प्रतिनिधि होंगे। उन्होंने पिछले महीने राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीता था और वे 60 किलोग्राम वर्ग में हिस्सा लेंगे। इन सभी खिलाड़ियों का लक्ष्य अपनी उत्कृष्ट प्रदर्शन से देश के लिए गौरव अर्जित करना होगा।

न्यूज ब्रीफ

डीपीएलः साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज ने नई दिल्ली टाइगर्स को पांच विकेट से हराया

नई दिल्ली। साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज ने दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए सोमवार रात

नई दिल्ली टाइगर्स को पांच विकेट से हरा दिया। साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज ने 169 रन के लक्ष्य को 18वें ओवर में ही हासिल कर लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए नई दिल्ली टाइगर्स ने 20 ओवर में नौ विकेट पर 168 रन बनाए। लक्ष्य थरेजा ने 47 गेंदों पर 62 रन की शानदार पारी खेलकर टीम की पारी को संभाला। आखिरी ओवरों में नमन तिवारी ने दो गेंदों पर 10 रन और रेवान रक्यान ने छह गेंदों पर 17 रन बनाकर टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज की ओर से अंकित डबास ने चार ओवर में 16 रन देकर दो विकेट लिए। वहीं दिवांश रावत ने दो ओवर में 25 रन खर्च करने के बावजूद चार विकेट झटककर प्रभावी प्रदर्शन किया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज ने अच्छी शुरुआत की। अनमोल शर्मा ने शानदार फार्म जारी रखते हुए एक और अर्धशतक लगाया और टीम को मजबूत आधार दिया। वह 16वें ओवर में आउट हुए, लेकिन दूसरे छोर पर एकांश डोबाल ने पारी को संभाले रखा। इसके बाद अंकित ने 18वें ओवर में पार्थ की गेंदों पर लगातार तीन छक्के लगाकर मुकाबले का रुख पूरी तरह साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज के पक्ष में कर दिया। वह पांच गेंदों पर 18 रन बनाकर आउट हुए। एकांश 18 गेंदों पर 38 रन बनाकर नाबाद रहे। साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज ने 18वें ओवर में लक्ष्य हासिल कर पांच विकेट से शानदार जीत दर्ज की।

जोआओ फोंसेका पेट की चोट के कारण अमेरिकी ओपन से बाहर

न्यूयार्क। ब्राजील के युवा टेनिस खिलाड़ी जोआओ फोंसेका पेट की चोट के कारण अमेरिकी ओपन

2026 से बाहर हो गए हैं। दुनिया के 26वें नंबर के खिलाड़ी ने सोमवार को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी। 20 वर्षीय फोंसेका इस साल शानदार प्रदर्शन के बाद अमेरिकी ओपन में खिताब के दावेदारों में शामिल थे। उन्होंने फ्रेंच ओपन में शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल तक का सफर तय किया था, जहां उन्होंने दुनिया के पूर्व नंबर एक खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को भी हराया था। फोंसेका ने कहा कि पेट की चोट को लेकर जांच और उपचार शुरू होने के बाद उन्हें और उनकी टीम को लगा कि पूरी तरह फिट होने के लिए उन्हें अभी और समय की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी ओपन उनके लिए बेहद खास टूर्नामेंट है और इससे हटने का फैसला आसान नहीं था। फोंसेका ने कहा कि वह जल्द से जल्द वापसी करने के लिए कड़ी मेहनत जारी रखेंगे। फोंसेका अमेरिकी ओपन से हटने वाले प्रमुख पुरुष खिलाड़ियों की सूची में शामिल हो गए हैं। इससे पहले जैनिक सिनर, होल्गर रूने और जैक ड्रेपर भी चोटों के कारण टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले चुके हैं।

भुवनेश्वर ने यूपीटी20 लीग में सबसे अधिक डाट बाल्स खेलने का रिकार्ड बनाया

लखनऊ। पिछले काफी समय से भारतीय टीम से बाहर चल रहे तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार आजकल

यूपीटी20 लीग में खेल रहे हैं। इसी दौरान भुवनेश्वर ने 400 डाट बाल्स फेंकने का एक नया विश्व रिकार्ड बनाया है। अपनी स्विंग गेंदबाजी के कारण चर्चाओं में रहे भुवनेश्वर ने यूपीटी20 लीग में साबित किया है कि अब भी उनकी गेंदबाजी की धार कायम है। डाट बाल्स उन गेंदों को कहा जाता है जिनपर कोई रन नहीं बनता। लखनऊ फाल्कन्स की कप्तानी करते हुए भुवनेश्वर ने इस टूर्नामेंट के इतिहास में 400 डाट बाल्स की थीं। उन्होने यह उपलब्धि सत्र के अपने पांचवें मैच में हासिल की। यूपीटी20 लीग के चार सत्र में अब तक 35 मैचों में 124 ओवर गेंदबाजी करते हुए उनके नाम कुल 408 डाट बाल्स हैं। वहीं आंकड़ों पर ध्यान दें तो भुवनेश्वर ने इस टूर्नामेंट में हर ओवर में 3 से अधिक डाट गेंदें फेंकी हैं। भुवनेश्वर इस प्रकार इस सत्र में छाये हुए हैं। उन्होंने 9 मैचों में 118 डाट गेंदें फेंकी हैं जबकि दूसरे सत्र के 11 मैचों में 120 डाट गेंदें फेंकी। तीसरे सत्र में भी उनकी कफी गेंदों पर रन नहीं बने। उन्होंने 10 मैचों में 117 डाट बाल्स दर्ज कीं। इस चौथे सत्र में भी, उन्होंनरे पांच मैचों में ही अब तक 53 डाट गेंदें फेंकी हैं। गौरतलब है कि टी20 क्रिकेट में डाट बाल्स से विरोधी बल्लेबाजी पर दबाव पड़ता है और वह बड़े शाट लगाने के जरुरत से ज्यादा जोखिम भी लेने लगता है।

इंडिया ओपन 2028 का आयोजन दिल्ली की जगह गुवाहाटी में होगा : बीएआई

नई दिल्ली

बैडमिंटन एसोसिएशन आफ इंडिया (बीएआई) ने कहा है कि प्रतिष्ठित बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडिया ओपन साल 2028 में नई दिल्ली की जगह पर गुवाहाटी में आयोजित किया जाएगा। बीएआई के अनुसार आयोजन स्थाल में ये बदलाव सुरक्षा कारणों से किया गया है क्योंकि उस समय गणतंत्र दिवस होने के कारण सुरक्षा इंतजाम करना कठिन होगा। बीएआई ने ये भी कहा कि यह बदलाव केवल एक वर्ष के लिए है। वहीं साल 2027 का इंडिया ओपन दिल्ली में ही होगा, और 2028 के बाद, टूर्नामेंट 2029 में फिर से दिल्ली में वापस आ जाएगस।

बीएआई महासचिव संजय मिश्रा ने कहा कि इंडिया ओपन 2028 जनवरी के आखिरी सप्ताह में खेला जाएगा। इसी दौरन रान नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड और उससे जुड़े व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए जाते हैं, जिससे आयोजन में बाधा आ सकती थी। मिश्रा ने कहा, इसलिए हमने महसूस किया कि केवल एक वर्ष के लिए टूर्नामेंट को गुवाहाटी स्थानांतरित किया जान चाहिए। यह 2029 में नई दिल्ली लौट आएगा। यह कदम टूर्नामेंट के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

वहीं गुवाहाटी को 2028 संस्करण की मेजबानी मिलने से पूर्वोत्तर भारत में बैडमिंटन को एक बड़ा मंच और प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है, जिससे इस क्षेत्र में खेल के विकास में तेजी आये। गौरतलब है कि इंडिया ओपन भारत के सबसे प्रतिष्ठित बैडमिंटन टूर्नामेंटों में से एक है और बीडब्लयूएफ विश्व टूर का एक प्रमुख आयोजन है, जिसमें दुनिया भर के शीर्ष खिलाड़ी भाग लेते हैं। इस बीच, संजय मिश्रा ने 2026 बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के सफल आयोजन पर भी संतोष व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि नई दिल्ली में हुए इस टूर्नामेंट के आयोजन और व्यवस्थाओं की खिलाड़ियों, अधिकारियों और बैडमिंटन फेडरेशन के सदस्यों ने भी सराहना की। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले दो सत्रों के इंडिया ओपन के दौरान नई दिल्ली के आयोजन स्थल को लेकर कई सवाल उठे थे और बीएआई को कुछ आलोचनाएं भी झेलनी पड़ी थीं। मिश्रा ने कहा कि जिन खिलाड़ियों ने पिछली बार आलोचना की थी। उन्हीं ने इस बार सराहना की है।

एसए टी-20 लीग के पांचवें सत्र में ईस्टर्न केप की ओर से खेलेंगे मिचेल मार्श

जोहांसबर्ग। दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट लीग एसए20 लीग का पांचवां सत्र सत्र क्रिकेट प्रेमियों के लिए विशेष रहेगा। इसमें कई बड़े अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी खेलते नजर आयेंगे। इस सत्र में आस्ट्रेलिया के टी20 कप्तान मिचेल मार्श से लेकर इंग्लैंड के आलराउंडर कुरेन खेलते दिखें। इन क्रिकेटरों के होने से लीग की लोकप्रियता और रोमांच का स्तर बढ़ेगा। मार्श तीन बार की चैम्पियन सनराइजर्स ईस्टर्न केप के साथ जुड़कर एसए20 में अपनी नई पारी शुरु करेंगे। सनराइजर्स के पास पहले से ही क्विंटन डिकाक, मैथ्यू ब्रीज्के, जार्डन हरमान और कप्तान ट्रिस्टन स्टब्स जैसे दमदार बल्लेबाज मौजूद हैं, जिससे उनकी बल्लेबाजी लाइनअप और मजबूत हो गई है। वहीं, इंग्लैंड के स्टार आलराउंडर सैम कुरेन अब मुंबई इंडियंस केपटाउन की जगह डरबन सुपर जाइंट्स के लिए खेलेंगे। वह अपनी राष्ट्रीय टीम के साथी जोस बटलर के साथ सुपर जाइंट्स टीम का हिस्सा होंगे, जो निश्चित रूप से टीम को एक नई गति प्रदान करेगा। वहीं पिछले सत्र की उपविजेता प्रिटोरिया कैपिटल्स ने भी अपनी टीम में अहम बदलाव किए हैं। उन्हें शीर्ष क्रम में इंग्लैंड के विस्फोटक बल्लेबाज फिल साल्ट और आस्ट्रेलिया के मैट शार्ट जैसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी मिल गए हैं। कैपिटल्स के पास पहले से ही डेवाल्ड ब्रेविस, शेरफान रदरफोर्ड, आंद्रे रसेल और कोनोर ईस्टरहुइजेन जैसे आक्रामक बल्लेबाज मौजूद हैं, जिससे उनकी बल्लेबाजी और भी जबरदस्त दिख रही है। वहीं इग्लैंड के एक और आलराउंडर विल जैक्स अब कैपिटल्स से एमआई केपटाउन टीम में शामिल हो गए हैं। एसए20 लीग के कमिश्नर और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान ग्रीम स्मिथ ने इन बड़े खिलाड़ियों की मौजूदगी पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि मिचेल मार्श, सैम कुरेन और फिल साल्ट जैसे विश्व स्तरीय खिलाड़ियों का लीग में शामिल होना इसकी बढ़ती लोकप्रियता को दिखाता है। गौरतलब है कि एसए20 का अगला सत्र 17 जनवरी से शुरू होगा और क्रिकेट प्रशंसकों को लगभग एक महीने तक जोरदार मुकाबले देखने को मिलेंगे। लीग का फाइनल मुकाबला 21 फरवरी को केपटाउन में खेला जाएगा, जहाँ विजेता टीम ट्राफी उठाएगी।

महिला डीपीएलः साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज ने सेंट्रल दिल्ली क्वींस को 11 रन से हराया

नई दिल्ली

दिल्ली प्रीमियर लीग (डीपीएल) 2026 के महिला वर्ग में साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज ने शानदार आलराउंड प्रदर्शन करते हुए सेंट्रल दिल्ली क्वींस को 11 रन से हरा दिया। बारिश के कारण आठ ओवरों तक सीमित रहे इस मुकाबले में साउथ दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 68 रन बनाए, जिसके जवाब में सेंट्रल दिल्ली की टीम 5 विकेट पर 57 रन ही बना सकी।

अरुण जेटली स्टेडियम में साउथ दिल्ली की कप्तान श्वेता सहरावत ने 21 गेंदों में तीन चौकों की मदद से 26 रन बनाकर टीम की पारी को संभाला। तनिषा सिंह ने भी 13 गेंदों पर 19 रन का उपयोगी योगदान दिया। इससे पहले प्रिया पुनिया ने तेज शुरुआत करते हुए चार गेंदों में नौ रन बनाए।

सेंट्रल दिल्ली की ओर से सुमिति सोनी और मेधावी बिधूड़ी ने दो-दो विकेट लेकर विपक्षी बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखा।

69 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी सेंट्रल दिल्ली क्वींस की शुरुआत बेहद खराब रही और टीम ने पहली ही गेंद पर अपना पहला विकेट गंवा दिया। इसके बाद दीक्षा शर्मा ने 16 गेंदों में चार चौकों की मदद से 22 रन बनाकर पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन छठे ओवर में उनके रन आउट होने के बाद टीम की मुश्किलें बढ़ गईं।

अरुषि गोयल ने 14 और मोनिका ने नौ रन बनाए, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचने के लिए यह पर्याप्त नहीं रहा। साउथ दिल्ली की ओर से रूपाली विश्व मोहन, दिशा नागर और एकता भदाना ने एक-एक विकेट लिया। अनुशासित गेंदबाजी और चुस्त क्षेत्ररक्षण के दम पर साउथ दिल्ली ने मुकाबला 11 रन से अपने नाम कर लिया।

भारतीय पुरुष हाकी टीम विश्वकप से बाहर हुई

एम्सटलवीन। भारतीय पुरुष हाकी टीम अर्जेटीना के हाथों दूसरे चरण के मुकबले में 3-5 से मिली हार के साथ ही एफआईएच हाकी विश्वकप से बाहर हो गयी है। भारतीय टीम को सेमीफाइनल में जगह बनाने इस मुकाबले में जीत की जरुरत थी पर वह असफल रही। इससे पहले भारतीय महिला टीम भी विश्वकप से बाहर हो गयी थी। के बाद भारतीय पुरुष हाकी टीम का भी वर्ल्ड कप 2026 में सफर खत्म हो गया. अर्जेंटीना ने वागेनर स्टेडियम में खेले गए पूल-ई के इस मुकाबले मे शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाते हुए पहले ही क्वार्टर में दो गोल दाग कर मुकाबले में अच्छी खासी बढ़त हासि कर ली थी। इससे भारतीय टीम दबाव में आ गयी। भारतीय टीम ने हालांकि शुरुआती झटकों से उबरकर वापसी के प्रयास किये पर वह सफल नहीं हो पायी। अर्जेंटीना की रक्षापंक्ति को भेदना उसके लिए परेशानी का कारण बना रहा। वहीं इसी समय उसे विरोधी टीम के आक्रमण का भी सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ही भारतीय टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें भी समापत हो गईं।

दक्षिण अफ्रीकी टीम को झटका, आलराउंडर जेसन स्मिथ त्रिकोणीय सीरीज में नहीं खेलेंगे

जोहांसबर्ग

दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट टीम को इसी माह 28 अगस्त से नामीबिया और जिम्बाब्वे के खिलाफ शुरु होने जा रही त्रिकोणीय सीरीज में आलराउंडर जेसन स्मिथ के बिना ही उतरना होगा। स्मिथ चोटिल होने के कारण इस सीरीज से बाहर हैं। क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका (सीएसए) के अनुसार स्मिथ के जांघ की मांसपेशियों में खिंचाव आया है। सीएसए ने माना है कि इस आलराउंडर का नहीं खेलना टीम के लिए बड़ा झटका है। टीम प्रबंधन ने अभी तक स्मिथ के विकल्प की घोषणा नहीं की है। इससे साफ है कि उससे मौजूदा दल पर ही भरोसा जताया है।

सीएसए ने कहा, आलराउंडर जेसन स्मिथ दाहिनी जांघ की मांसपेशी खिंचाव के कारण विंडहोक में नामीबिया और जिम्बाब्वे के खिलाफ होने वाली ट्राई-सीरीज से बाहर हो गए हैं। स्मिथ की चोट की गंभीरता का आकलन करने के लिए उनकी और जांच की जाएगी, विशेष रूप से नामीबिया के खिलाफ 09 सितंबर से शुरू होने वाली एकदिवसीय सीरीज में उनकी उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं।

यह ट्राई-सीरीज 28 अगस्त से 6 सितंबर तक विंडहोक में खेली जाएगी, जिसमें बाएं हाथ के स्पिनर ब्योर्न फोर्टुइन अफ्रीकी टीम की कप्तानी करेंगे। इस ट्राई-सीरीज के बाद, दक्षिण अफ्रीका 9 से 13 सितंबर तक नामीबिया के खिलाफ एकदिवीसीय मैच खेलेगा। यह प्रतियोगिता दक्षिण अफ्रीका के लिए इस साल की शुरुआत में हुए पुरुष टी20 विश्व कप के बाद पहली टी20 सीरीज होगी।

टीम में कई प्रमुख नियमित खिलाड़ियों को आराम दिया गया है, जिससे टीम युवा खिलाड़ियों से भरी है। इस बार ईथन बाश, डुआन जानसेन जैसे

उभरते हुए खिलाड़ियों को पहली बार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलने का अवसर मिलेगा। इनके अलावा, डेवाल्ड ब्रेविस, टोनी डी जोरजी और क्वेना मफाका जैसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी, जो पहले ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेल चुके हैं या अपनी घरेलू लीगों में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, टीम के साथ नामीबिया का दौरा करेंगे। यह सीरीज इन खिलाड़ियों के लिए भी अपनी जगह पक्की करने और अनुभव हासिल करने का सुनहरा मौका है।

टीम इस प्रकार है :

ब्योर्न फोर्टुइन, ईथन बाश, डेवाल्ड ब्रेविस, टोनी डी ज़ोरज़ी, कानर एस्टरहुइज़ेन, जार्डन हरमन, रुबिन हरमन, डुआन जानसेन, क्वेना मफाका, मोकोएना, न्काबा पीटर, लुआन-ड्रे प्रेटोरियस, लुथो सिपाम्ला और प्रेनेलन सुब्रायेन।

सूर्यकुमार ने अब भी नहीं छोड़ी टीम इंडिया में वापसी की उम्मीदें, नेट्स में जमकर अभ्यास कर रहे

मुम्बई

टी20 विश्वकप में भारतीय क्रिकेट टीम को जीत दिलाने वाले सूर्यकुमार यादव आजकल टीम से बाहर चल रहे हैं। सूर्यकुमार को विश्वकप के बाद कप्तानी हीं नहीं टीम से भी बाहर कर दिया गया था। इसका कारण उनका खराब फार्म और बढ़ती उम्र को बताया गया था सूर्या ने हालांकि अपनी वापसी की उम्मीदें अब भी नहीं छोड़ी हैं। सूर्या जानते हैं कि जिस प्रकार से टीम में लगातार नई प्रतिभाएं आ रही हैं उसमें उनकी वापसी आसान नहीं रहेगी।

ऐसे में उनके पास कड़े अभ्यास और अपने को साबित करने के अलावा कोई और चारा नहीं है। इसी कारण वह आजकल नेट्स में जमकर अभ्यास कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो भी साझा किया है। इसमें वह कड़ा अभ्यास करते दिख रहे हैं। इस वीडियो के साथ उन्होंने लिखा था अभ्यास को मैच से भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण बनाओ। जब आप

नेट्स में खुद पर अधिक दबाव डालोगे, तो खेल के दौरान शांत रहना आपकी आदत बन जाएगी। मुश्किलों का सामना करो!

सूर्यकुमार के इस अभ्यास सत्र से यह साफ है कि उन्होंने टीम में वापसी के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। वहीं भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) साल 2026 के टी-20 विश्व कप को देखते हुए युवा प्रतिभाओं पर ही ध्यान दे रहा है। उसका प्रयास टीम को मजबूत बनाना है। इसको देखते हुए वह एक बार फिर सूर्यकुमार को अवसर देगा, ऐसे संभावनाएं नहीं हैं।

अब देखना यह होगा कि सूर्यकुमार का कठिन अभ्यास सफल होता है या नहीं। भारतीय टीम में वापसी का उनका सफर निश्चित रूप से आसान नहीं होगा, लेकिन क्रिकेट के मैदान पर अपनी अनूठी पहचान बनाने वाले इस खिलाड़ी ने हमेशा ही चुनौतियों का पूरे साहस से सामना किया है।

यूपी टी20 लीग : रिंकू और स्वास्तिक की आक्रामक पारी से मेरठ मेवरिक्स जीती

नई दिल्ली। मेरठ मेवरिक्स के कप्तान रिंकू सिंह और स्वास्तिक चिकारा की आक्रामक बल्लेबाजी से यूपी टी20 लीग 2026 के 16वें मुकाबले में गोरखपुर लायंस की टीम को करारी हार का सामना करना पड़ा है। रिंकू ने वर्षा बाधित इस मुकाबले में 7 गेंदों पर 414.29 के स्ट्राइक रेट से 29 रनों की आक्रामक पारी खेलकर अपनी टीम को 6.4 ओवर में ही जीत दिला दी। बारिश की बाधा के कारण इस मैच को घटाकर 8-8 ओवर का किया गया था। इसमें आर्यन जुयाल की कप्तानी वाली गोरखपुर लायंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 8 ओवरों में 91 रन बनाए थे। इसके बाद लक्ष्य का पीछा करते हुए मेरठ मेवरिक्स ने रिंकू और स्वास्तिक चिकारा की आक्रामक बल्लेबाजी से जीत दर्ज की। मेरठ को अंतिम तीन ओवरों में 36 रनों की आवश्यकता थी, तब अक्षय दुबे के रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान से बाहर जाने के बाद कप्तान रिंकू ने कमान संभाली। उन्होंने आते ही तीन छक्के व दो चौके लगाकरकुल 28 रन बनाये। इस प्रकार उन्होंने केवल 7 गेंदों का सामना करते हुए 29 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 3 इ छक्के शामिल थे। वहीं दूसरे छोर पर चिकारा ने 24 गेंदों में नाबाद 44 रनों की अहम पारी खेली और रिंकू के साथ मिलकर टीम को बिना कोई विकेट खोये जीत दिला दी। वहीं इससे पहले, गोरखपुर लायंस ने बल्लेबाजी करते हुए 8 ओवर में 91 रन बनाए। एक समय ऐसा लग रहा था कि गोरखपुर की टीम 100 रनों का आंकड़ा पार कर सकती है पर मेरठ के गेंदबाज जीशान अंसारी ने गोरखपुर की लय को तोड़ दिया। छठे ओवर में उन्होंने आर्यन जुयाल और हरदीप सिंह को आउट कर दोहरा झटका दिया।

आलिंगन सिर्फ अंतरंगता के लिए ही नहीं होता है, बल्कि इससे भी बहुत ज्यादा होता है। आलिंगन प्यार जताने का एक बेहतरीन तरीका तो है ही साथ ही इसके स्वास्थ्यगत फायदे भी हैं। इससे स्मरण शक्ति बढ़ती है और तनाव कम होता है। वैज्ञानिकों को पता चला है कि जब आप किसी को गले लगाते हैं, तो इससे रक्त में एक हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्राव होता है। इससे उच्च रक्तचाप में कमी आती है, तनाव और बेचैनी कम होती है और इससे आपकी स्मरण शक्ति भी बेहतर होती है।

जादू की झप्पी

आलिंगन से एक व्यक्ति की आत्मिक ऊर्जा दूसरे के मन और चेतना में प्रवेश करने लगती है। ऐसा करने से परेशान व्यक्ति को राहत मिलती है। एक अध्ययन से पता चला है कि ब्रिटेनवासी प्रत्येक आलिंगन में नौ सेकेंड से अधिक का समय लगाते हैं और इस तरह हर महीने आलिंगन के लिए वे एक घंटा समय खर्च करते हैं।

सिर्फ यही नहीं, आलिंगन में इतना समय खर्च करने के बावजूद सर्वेक्षण में शामिल किए गए 41 प्रतिशत लोगों ने कहा कि हम आलिंगन में और भी समय खर्च करना चाहते हैं। सर्वेक्षण में पाया गया है कि 69 प्रतिशत ब्रिटिश अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ आलिंगन करना चाहते हैं, जबकि 14 प्रतिशत अपने करीबी मित्र के साथ और नौ प्रतिशत ही अपनी मां के साथ आलिंगन करना चाहते हैं।

वास्तव में आलिंगन प्यार जताने का सबसे बेहतरीन तरीका है। कोई कितना भी परेशान क्यों न हो किसी अपने के गले लगकर बहुत अच्छा महसूस करता है। क्योंकि आलिंगन से एक व्यक्ति की आत्मिक ऊर्जा दूसरे के मन और चेतना में प्रवेश करने लगती है। ऐसा करने से परेशान व्यक्ति को तो राहत मिलती ही है, साथ ही आलिंगन वाला स्वयं भी ऊर्जा से भर उठता है।

प्यार जताने का तरीका

आलिंगन प्यार जताने का सबसे बेहतरीन तरीका है। कोई कितना भी परेशान क्यों न हो किसी अपने के गले लगकर बहुत अच्छा महसूस करता हैं। क्योंकि आलिंगन से एक व्यक्ति की आत्मिक ऊर्जा दूसरे के मन और चेतना में प्रवेश करने लगती है। ऐसा करने से परेशान व्यक्ति को तो राहत मिलती ही है, साथ ही आलिंगन वाला स्वयं भी ऊर्जा से भर उठता है। एक ताजा अध्ययन के अनुसार, आलिंगन से स्वास्थ्य को भी फायदा होता है।

ब्लड प्रेशर पर कंट्रोल

वास्तव में आलिंगन स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होता है, और एक स्वस्थ जीवनशैली को बनाए रखने में भी मदद करता है। यह अवसाद का कम करता है और रक्त के दबाव को बनाए रखने में मदद करता है। रक्तचाप के स्थिर रहने से सिर दर्द और अन्य बीमारियों के होने की आशंका कम होती है।

सिर्फ अंतरंगता नहीं

आलिंगन सिर्फ अंतरंगता के लिए ही नहीं होता है, बल्कि इससे भी बहुत ज्यादा होता है। जो जोड़े एक-दूसरे को गले लगाते हैं उनका अन्य (जो एक दूसरे को गले नहीं लगाते) जोड़ों की तुलना में मजबूत सम्पर्क होता है। जब कोई अपने पार्टनर को गले लगाता है तो वह भी नहीं जानता कि वह बातचीत के कौन से स्तर पर होता है। यहां तक कि कई बार बिना बोले सिर्फ गले लगना ही रिश्ते में जादुई असर करता है।

सावधानी भी जरूरी

वियना विश्वविद्यालय के शोध के मुताबिक किसी को गले लगाते वक्त हालांकि सावधानी बरतनी चाहिए। आप उसी को गले लगाएं, जिसे बहुत अच्छी तरह जानते हैं, वरना इसका उल्टा प्रभाव भी हो सकता है।

उल्लेखनीय है कि ऑक्सीटोसिन को माता-पिता, बच्चों और दम्पतियों के बीच आपसी प्यार बढ़ाने के लिए प्रमुख कारक माना जाता है। सक्रिय सम्बंध में रह रहे साथियों के बीच ऑक्सीटोसिन का स्तर अधिक पाया जाता है।

डिप्रेशन कम करता है

कई शोधों से भी यह बात साबित हो गई है कि किसी के साथ आलिंगन करने से अवसाद से लड़ने में मदद मिलती है। आलिंगन के दौरान रक्त से ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन का स्राव अवसाद से लड़ता है। अगर कोई अपने साथी की बाहों में सोता है तो न केवल उसको आरामदायक और शांतिपूर्ण नींद आती है बल्कि अगले दिन चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान लेकर जागता है।

एक-दूसरे को जानना जरूरी

न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट्स के मुताबिक गले लगाने का फायदा हालांकि तभी मिलता है, जब गले लगने वाले दोनों व्यक्ति एक-दूसरे को जानते हों और एक-दूसरे पर भरोसा करते हों। यदि गले लगने वाले व्यक्ति एक-दूसरे को नहीं जानते या दोनों में से एक गले नहीं लगना चाहे तो इसका कोई फायदा नहीं मिल पाता है। उल्टे इससे बेचैनी बढ़ जाती है। गले लगाना अच्छी बात है, लेकिन भले ही कोई भी कितना भी एक-दूसरे से गले लगे, वास्तविकता यह है कि महत्वपूर्ण चीज आपसी भरोसा है।

रूखापन खत्म होता है

महिलाओं में बच्चों को जन्म देते वक्त और स्तनपान कराते वक्त इस हार्मोन का स्राव होता है, जिससे माता और बच्चों के बीच लगाव बढ़ता है। शोधार्थियों के मुताबिक अपने प्रियजनों को गले लगाने वाले व्यक्ति के स्वभाव का रूखापन भी समाप्त होता है और उसमें समय के साथ मधुरता का विकास होता है।

इंडियन लाइसेंस से विदेशों में ड्राइविंग...

अगर आपके पास इंडियन लाइसेंस है और कार ड्राइविंग के शौकीन तो आपके लिए यह खुशखबरी है कि आप विदेशों की स्मूथ सड़कों पर भी ड्राइविंग का मजा ले सकते है। विदेशों में भी आप इंडियन लाइसेंस को साथ वहां के नियम और कानून का पालन करते हुए कार या फिर बाइक आदि ड्राइव कर सकते हैं। आइए जानते है उन देशों के बारे में जहां इंडियन लाइसेंस के साथ ड्राइविंग की जा सकती है।

न्यूजीलैंड

अगर अपकी उम्र 21 साल से ज्यादा है तो आप 1 साल तक न्यूजीलैंड में इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस के साथ कार ड्राइव कर सकते हैं। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस इंग्लिश में नहीं है तो एंबेसी से न्यूजीलैंड ट्रांसपोर्ट एजेंसी से ट्रांसलेट कराना होता है।

ऑस्ट्रेलिया

आप न्यू साउथ वेल्स, क्वीन्सलैंड, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया कैपिटल टेरिटरी में ही भारतीय वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस से ड्राइव कर सकते हैं। लीगल ड्राइविंग लाइसेंस के साथ आप वही गाड़ी चला सकते हैं जिसकी इजाजत भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस में है। यहां इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस सिर्फ 3 महीने के तक ही चलेगा।

फ्रांस

फ्रांस में इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस को एंबेसी से फ्रेंच में ट्रांसलेट कराना भूलने पर मुसीबत खड़ी हो सकती है। फ्रांस में इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस 1 साल तक चलता है।

अमेरिका

अमेरिका में आप भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस से एक साल तक कार ड्राइव कर सकते हैं। इसके बाद आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट बनवाना पड़ेगा।

साउथ अफ्रीका

साउथ अफ्रीका में कार ड्राइव करने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस इंग्लिश में होना चाहिए और साथ ही इसमें आपकी फोटो और साइन होना सबसे जरूरी है।

नार्वे

अगर आपको नार्वे में ज्यादा समय के लिए रहना है तो आपको वहां का ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। यहां पर आप इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस के साथ 3 महीने तक ही कार ड्राइव कर सकते हैं।

स्विट्जरलैंड

कार ड्राइव करने के लिए इंडियन लाइसेंस स्विट्जरलैंड में सिर्फ 1 साल तक के लिए ही लीगल होता है।

इंग्लैंड

इंग्लैंड में आप इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस के साथ सिर्फ छोटी कार और बाइक ही अपने लाइसेंस से चला सकते हैं। यूके को कार ड्राइव के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन माना जाता है।

जर्मनी

अगर आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो एंबेसी से इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस को जर्मनी में ट्रांसलेट करवा सकते हैं और जर्मनी में 6 महीने तक कार ड्राइव कर सकते हैं।

किताबें पढ़ने वाले ज्यादा जीते हैं ...

कुछ लोग अधिक पढ़ने वाले लोगों का मजाक उड़ाते हैं और उन्हें किताबी कीड़ा तक कहते हैं। अब एक रिसर्च में पता चला है कि जो लोग किताबें अधिक पढ़ते हैं, वे दूसरों की तुलना में अधिक दिनों तक जीते हैं। यह रिसर्च अमेरिका के येल यूनिवर्सिटी में किया गया है। इस रिसर्च में 50 वर्ष से अधिक उम्र के 3635 लोगों को शामिल किया गया। इसमें भाग लेने वाले सभी लोगों को तीन ग्रुप में बांट दिया गया। पहले ग्रुप में किताब नहीं पढ़ने वाले लोगों को शामिल किया गया। दूसरे ग्रुप में साढ़े तीन घंटे तक किताब पढ़ने वाले लोगों को शामिल किया गया और तीसरे ग्रुप में साढ़े तीन घंटे से अधिक पढ़ने वाले लोगों को शामिल किया गया। रिसर्च में पाया गया कि अधिक पढ़ने वाले लोगों में अधिकतर लड़कियां, कॉलेज कर चुके लोग और अधिक आय वाले लोग थे। रिसर्च में देखा गया कि साढ़े तीन घंटे तक पढ़ने वाले लोगों में नहीं पढ़ने वाले लोगों की तुलना में 12 वर्ष के अंतराल में 17 प्रतिशत कम लोगों की मृत्यु हुई। जो लोग साढ़े तीन घंटे से अधिक पढ़ रहे थे, उनमें मृत्यु दर 27 प्रतिशत तक कम देखी गई। किताब पढ़नेवाले औसतन सभी लोग नहीं पढ़ने वालों की तुलना में दो साल अधिक जिए।

रुटीन बिगड़ा तो बिगड़ेंगे बच्चे...

शादी-ब्याह तो कभी छुट्टियों का मौसम। कभी घर पर मेहमान आए, कभी खुद कहीं चले गए। इस आपाधापी में आपका रुटीन तो खराब होता ही है, बच्चों का रुटीन भी गड़बड़ा जाता है। उनका रुटीन वैसा नहीं रह पाता, जैसा सामान्य दिनों में होता है और यही बात खतरनाक है। बाल मनोविज्ञान विशेषज्ञ कहते हैं कि बच्चों के रुटीन को गड़बड़ाने नहीं देना चाहिए। इन विशेषज्ञों की राय है कि कुछ विशेष परिस्थितियों जैसे बीमारी, यात्रा आदि को छोड़कर बच्चों के रुटीन को बिगाड़े नहीं। रूटीन बदलने से बच्चे पढ़ाई से संबंधित कार्य को बोझ समझने लगते हैं। इसलिए माता-पिता को ध्यान देना चाहिए कि बच्चों के सुबह उठने के समय, नहाने, नाश्ता करने, खेलने, टीवी देखने और पढ़ने के समय में विशेष बदलाव नहीं करना चाहिए। हालांकि विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि ऐसे सख्त नियम भी न बना डालें कि बच्चों का बचपना ही खत्म हो जाए। कुछ दिन घूमने-फिरने गए हों तो उन्हें पूरी मस्ती करने देना चाहिए। विशेषज्ञों का मानना है कि यह हो सकता है कि बच्चे कुछ कामों में लेट-लतीफी करें, लेकिन पूरी तरह रुटीन बदलने पर दिक्कतें हो सकती हैं।

शहरी बच्चे ज्यादा नेगेटिव!

इलाहाबाद में स्थित मनोविज्ञानशाला में हाल ही में एक सर्वे हुआ था। ग्रामीण व शहरी इलाकों में छात्र-छात्राओं के बीच कराए गए सर्वे में यह बात सामने आई है कि आज के प्रतिस्पर्धात्मक युग में शहरी बच्चे अपने माता-पिता की उदासीनता के शिकार हो रहे हैं। शोध में यह भी पता चला है कि ग्रामीण इलाकों की तुलना में शहर के बच्चों पर पारिवारिक उदासीनता का ज्यादा नकारात्मक असर पड़ रहा है। 2015-16 शैक्षिक सत्र में कुल 500 छात्र व 258 छात्राओं पर सर्वे किया गया। ये सभी बच्चे 10वीं के विद्यार्थी हैं। जब लड़के व लड़कियों पर अलग-अलग अध्ययन किया गया तो पता चला कि लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की शैक्षिक उपलब्धि और समायोजन पर इस उदासीनता का अधिक प्रतिकूल प्रभाव है। सर्वे के बाद अभिभावकों के लिए तीन प्रमुख सुझाव दिए गए हैं। अभिभावकों को सलाह दी गई है कि दूसरे बच्चों से तुलना की बजाय अपने बच्चे की उपलब्धि एवं अच्छे प्रयासों की सराहना करें। बच्चों पर विश्वास करने की आदत विकसित करें और उन्हें घरेलू कार्य का दायित्व सौंपें जिससे वे शैक्षिक व घरेलू कार्यों में सामंजस्य स्थापित करने में सक्षम हो सकें। मन की एकाग्रता व स्थिरता को बढ़ाने के लिए रोज लगभग 20 मिनट योगाभ्यास करने की सलाह दी गई है।

विदेश से कितना सोना ला सकते हैं आप?

सोना यानी कि गोल्ड से भारतीयों को कितना लगाव है यह बात किसी से छिपी नहीं है। भारतीयों के गोल्ड प्रेम से दुनिया वाकिफ है। देश में लोग सोने के आभूषण पहनने के अलावा चढ़ावे में भी चढ़ा देते हैं, दान कर देते हैं। विदेशों में रहने वाले भारतीयों में भी सोने को लेकर गहरा लगाव है इसलिए जब भी वह वापस देश लौटते हैं तो सोना साथ में खरीदकर जरूर लाते हैं। कई बार देखा गया है कि लोगों को सोने के साथ एयरपोर्ट पर रोक लिया जाता है। एयरपोर्ट अथॉरिटि को इस बात का शक रहता है कि मिडिल ईस्ट से लोग सोने की तस्करी करते हैं इसलिए लोगों को एयरपोर्ट पर रोक लिया जाता है। इस डर से लोग बाहर से सोना खरीद कर नहीं लाते हैं लेकिन हम आपको बताएंगे कि आप विदेश से कितना ड्यूटी फ्री सोना खरीद कर ला सकते हैं।

ड्यूटी फ्री सोने की सीमा

ड्यूटी फ्री सोना लाने के लिए आपको कुछ जरूरी बातों की जानकारी होनी चाहिए। अगर आप एक वर्ष से अधिक विदेश में रह चुके हैं तो आप 50 हजार रुपए तक का सोना भारत में ड्यूटी फ्री लेकर आ सकते हैं। वहीं महिलाओं के लिए यह छूट एक लाख रुपए तक है। महिलाएं एक लाख रुपए तक की कीमत का सोना ड्यूटी फ्री लेकर भारत आ सकती हैं।

सिक्के और बिस्किट

अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि अगर ऐसा है तो क्या विदेश से सोने के सिक्के या फिर सोने के बिस्किट ड्यूटी फ्री शर्तों के अंतर्गत लेकर आ सकते हैं ? इसका जवाब है नहीं। क्योंकि ड्यूटी फ्री की शर्तें सिर्फ सोने के आभूषणों पर लागू हैं और उनकी भी सीमा है ऐसे में आपको सोने के सिक्कों और बिस्किट्स पर ड्यूटी देना पड़ेगा।

कितना है ड्यूटी शुल्क

एक सवाल आपके मन में उठ रहा होगा कि, अगर सोना निर्धारित कीमत से अधिक है तो कितनी ड्यूटी चुकानी होगी? तो इसका जवाब है कि आपके पास ड्यूटी फ्री सोने से जितना अधिक सोना है उसका 10.3 प्रतिशत आपको चुकाना होगा। इस मामले में भी आपको नियम और शर्तें जान लेनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति एक किलो से अधिक सोना नहीं ला सकता।

रसीद साथ रखिए

आप यदि विदेश से सोने के आभूषण या फिर सिक्के खरीदकर ला रहे हैं तो आपको उसकी रसीद साथ रखनी चाहिए। यह कस्टम्स में पूछ-ताछ के दौरान आपकी मदद करेगी साथ ही आपके पास खरीदारी और सोने की सही कीमत का एक प्रमाण भी रहेगा। इस तरह की रसीद आपको आगे आने वाली परेशानियों से बचाएगी।

यह अफवाह है

आम तौर पर लोगों में ये भ्रांतियां होती है कि विदेश से यदि सोने के आभूषण खरीद कर ला रहे हैं तो उन्हें पहन कर आना चाहिए क्योंकि पहने हुए आभूषणों पर किसी तरह की ड्यूटी नहीं देनी पड़ती है लेकिन ये सच नहीं है। यहां भी वही नियम और शर्तें लागू रहती हैं।

जाते वक्त भी दें ब्योरा

आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि विदेश जाने से पहले आपको अपने गहनों के संबंध में कस्टम को जानकारी दे देनी चाहिए। चाहे आपने छोटी सी अंगूठी ही क्यों ना पहनी हो, विदेश जाने से पहले आपको एयरपोर्ट पर ये सुनिश्चित करना होगा कि यह आभूषण आपका है और आप इसे देश से ही पहन कर जा रहे हैं। इससे आप वापसी के दौरान होने वाली परेशानी से बच सकते हैं।

भारत में भी खरा सोना

अब दौर पहले के जैसा नहीं रहा। पहले देश में ये धारणा थी कि यहां मिलने वाला सोना उतना खरा नहीं जितना विदेशी सोना होता है। लेकिन सरकार के नियम अब कड़ाई से लागू किए जा रहे हैं जिससे बाजार में सिर्फ हॉलमार्क के ही सोने के आभूषण बिक रहे है। इसलिए अब इस बात से चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है कि देश में मिलने वाला सोना खरा है या नहीं।

मुद्रक एवं प्रकाशक राकेश शर्मा द्वारा अजय त्यागी के लिए ईको प्रिंटिंग प्रेस, पोस्ट एवं पीएस : गड़चुक, कटाबाड़ी मस्जिद के पास, कामरूप (मेट्रो), गुवाहाटी-35 से मुद्रित एवं **गुड लक पब्लिकेशंस, हाउस नं. 30, डी. नेउग पथ, डोना प्लैनेट के नजदीक, एबीसी, जीएस रोड गुवाहाटी-5 से प्रकाशित।**
संपादक : राकेश शर्मा, मोबाइल : 94350-14771, 97070-14771 ● **कार्यकारी संपादक : प्रदीप शील ● सहयोगी संपादक : रवि शंकर चौधरी ● फोन : 0361-2960054 (संपादकीय)** e-mail : viksitbharatsamacharghy@gmail.com, **(सभी विवाद सिर्फ गुवाहाटी न्याय क्षेत्र के अधीन)**